हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1987

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 6 मार्च, 1987

पृष्ठ संख्या

तांराकित प्रश्न एवं उत्तर	(8) 1
वक्तव्य–	
स्थानीय शासन राज्य मंत्री द्वारा गुड़गांव शहर के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत पेयजल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न होने	(8) 18

सम्बन्धी	
समितियों की रिपोर्टस पेश करना––	
(1) कमेटी ओन पब्लिक अकाउंट्स की 25वीं रिपोर्ट	(8) 18
(2) कमेटी ओन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 23 वीं, 24वीं, 25वीं और 26 वी रिपोर्टस	(8) 18
(3) कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शड्यूल्ड ट्राइब्ज की 12वी रिपोर्ट	(8) 19
(4) कमेटी औन सबार्डिनेट लैजिस्लेशन की 18 वीं रिपोर्ट	(8) 19
(5) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 18 वीं रिपोर्ट	(8) 19
वर्ष 1987– 88 के बजट पर अनुदानों को मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(8) 19

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 6 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डी गढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon. Members, we will start with questions.

Number of Government J.B.T. Teachers with B.Ed. qualification in the State

***1239. Seth Ram Dass Dhamija & Shri Bhalle Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of Teachers with B.Ed. qualification, if any, working as J.B.T. Teachers in the Government Schools in the State as on 1st January, 1987; and

(b) the time by which such B.Ed. Teachers are likely to be absorbed in their own B.Ed. cadre ?

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) :

(a) 1200

(b) Since the promotion of J.B.T. teachers to the post of Masters/ Mistresses depends upon availability of

vacancies in the promotion quota, it is difficult to indicate the exact time by which these teachers are likely to be absorbed in the B.Ed. cadre.

सेठ रामदास धमीजा : स्पीकर साहब, बहुत से जे० बी० टी० टीचर्ज ने पांच– पांच, सात–सात साल पहले बी ० ऐड० किया था । बी० ऐड० करने में एक साल का अर्सा लगता है और पाच–सात हजार रुपये भी खर्च होते हैं। उनको बी ० ऐड० का स्केल देने से सरकार को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है । जो फर्स्ट ग्रेड के हैं उनको स्केल देने से तो चालीस रुपया पर–मंथ का सरकार को नुकसान होगा और जो सैकिण्ड ग्रेड के हैं उनको स्केल देने से टीचरों को बीस रुपया महीना नुकसान होगा और सरकार को बीस रुपया महीना फायदा होगा । जिस आदमी ने बी ० ऐड ० किया और पांच साल से इंतजार कर रहा है वह तो बहुत परेशान है । क्या मन्त्री महोदया पांच साल, तीन साल या दो साल वाले की कोई मियाद मुकर्रर करने की कृपा करेंगी कि सरकार इतनी मियाद वाले को बी ० ऐड ० ग्रेड देगी? स्पीकर साहब, कायदे के मुताबिक तो उनका हक बनता है ।

श्री अध्यक्ष : मियाद नहीं कर सकते as it depends upon certain circumstances.

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने कहा है कि जब जे ० बी० टी ० को बी ० एड० बनाएंगे तो वह प्रोमोशन होता है । स्पीकर साहब, ऐसा बात नहीं है । जे ० जी ० टी ०

के बी ० ऐड० पर प्रोमोशन तो कभी नहीं होती । जे० बी ० टी ० तो जे० बी ० टी ० ही रहेगा । सवाल तो यह है कि कुछ लोगों ने जी ० ऐड० पास कर रखा है चाहे सर्विस में आने के पहले किया है या सर्पिल में रहते हुए किया है । नियम यह है कि जो सर्विस में रहते हुए बी ० ऐड० कर लेता है उसको तो जीं ० ऐड० ग्रेड दे देते हैं परन्तु कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने जे ० बी ० टी ० कर लिया था और नौकरी नहीं लगी थी । नौकरी न लगने के टाईम पर उन्होंने बी० ऐड० कर जिया और जे ० बी ० टी ० टीचर की पोस्ट पर लग गए । क्या मन्वी महोदया बताने जी. कृपा करेंगी कि ऐसे टीचर्ज को बी ० ऐड० ग्रेड देने में 'क्या दिक्कत है जिन्मेंने नौकरी. में न रहते हुए भी बी ० ऐड० पास की– थी ?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, उनको भी ग्रेड दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, अगस्त, 1986 से पहले केवल उन टीचर्ज को बी ० ऐड० ग्रेड के लिए कैसी–डर किया –जाता था जिन्होंने बी ०. ऐड० सर्विस में रहते–– हुए किया है लेकिन उसके बाद यह डिसिजन लिया गया कि उनको भी प्रोमोट किया जाएगा और उनको भी स्केल दिया जाएगा जिन्होंने सर्विस में आने के पहले बी ० ऐड० किया था और जे० बी ० टी ० की पोस्ट पर लगे हुए हैं ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगा कि इस समय मास्टर्ज की कितनी वैकेन्सीज ऐसी पड़ा हैं जो फिल–अप नहीं हुई हैं और क्या उनको फिल–अप किया

जाएगा? अगर फिल–अप किया जाएगा तो कब तक फिल– अप किया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास प्रोमोशन कोटा की केवल 58 वैकेन्सीज अवेलेबल हैं और उनको जल्दी ही फिल–अप किया जा रहा है

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, चौधरी भले राम ने जो कुछ कहा है मैं उसकी दूसरी तरफ जा रहा हूं । जिन लोगों ने सर्विस में होते हुए बी ० ऐड० किया, जिनका पांच–पांच सात–सात हजार रुपया भी खर्च हुआ और एक साल की बगैर पे छुट्टी ली, क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगीं' कि ऐसे लोगों को बी ० ऐड० ग्रेड देने पर विचार किया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, आज की तारीख में जो बी ० ऐड० है चाहे उन्होंने सर्विस में आने से पहले बी ० ऐड० की या बाद में की उनका प्रोमोशन कोटा निर्धारित है । बी ० ऐड० की जो वैकेन्सीज होती हैं, उनके अगैन्सट उन लोगों को लिया जाता है जो जे० बी ० टी ० के रूप में सर्विस कर रहे हैं लेकिन बी ० ऐड० पास हैं क्योंकि जे ० जी ० टीज० को तो बी ० ऐड० के अंगैन्सट प्रोमोट कर ही नहीं सकते । सभी बी ०ऐडज० को कंसीडर किया जा रहा है । स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर की बात का अर्थ समझती हूं । यह चाहते होंगे कि सारी वैकेन्सीज के अगैन्सट उनको लगा दिया जाए लेकिन ऐसा नही हो सकता

क्योंकि जो नए लोग बी ० ऐड० करके आते हैं उनको भी चांस दिया जाता है । पहले से रूल बना हुआ है । पहले प्रोमोशन का कोटा 25 परसैन्ट था बाद में उसको बढ़ाकर 33 परसैन्ट कर दिया और अब गवर्नमैंट इस पर फिर विचार कर रही है कि उसको पचास प्रतिशत कर दिया जाए ताकि जिन लोगों ने पहले से बी ० ऐड० किया हुआ है और जितनी वैकेन्सीज अवेलेबल हैं उनमें से पचास प्रतिशत पर उन लोगों को लगा दिया जाए जो आज जे० बी० टी ० लगे हुए हैं और बी ० ऐड० पास कर रखा है ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, पिछले सैशन में इन्होंने प्रोमिस किया था कि जे० बी० टी० की वैकेन्सीज को दिसम्बर तक पूरा कर लेंगे लेकिन वे पूरी नहीं हुई । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इन वैकेन्सीज को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि हम इन वैकेन्सीज को पूरा नहीं कर सके । जब हमने ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेजिज से पता लगाया तो मालूम हुआ कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जे० बी० टी० की हुई है । स्पीकर साहब, जिन लोगों ने ड्राइंग में कोर्स किया हुआ है, सी० एण्ड वी ० कोर्स किया हुआ है उनको दी ० ऐड० कालेज में छः महीने का कंडैन्सड कोर्स कराने के लिए दाखिला दिलाया है । इसके बाद जे० बी ० टी० इतने अवेलेबल हो जाएंगे कि पूरी पोस्ट्स भरने के बाद काफी बच जाएंगे ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : मन्त्री महोदया ने जवाब दिया है कि आर्टस एण्ड क्राफ्ट्स टीचर्ज को कंडैन्सड कोर्स कराकर जे ० बी ० टी ० पोस्ट्स के अगेन्सट ऐबजोर्ब किया जायेगा । स्पीकर साहब, इन्होंने एक बी ० ऐड० कालेज को सौ वैकेन्सीज दी हैं परन्तु आर्टस और क्राफ्टस के बहुत टीचर्ज बाकी रह गए हैं । क्या मन्त्री' महोदया कालेजिज में और अधिक वैकेन्सीज बढ़ाने की कृपा करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, 125 वैकेन्सीज कर दी हैं । हम निर्धारित सीमा से बाहर नही जा सकते चाहे कितने ही लोग रह जाएं ,

श्री भले राम : स्पीकर साहब, वीकर सैक्शन्ज और हरिजन्ज के लिए हर कोर्स में अथवा टेरनिंग मैं रिजर्वेशन ई । मुझे कई हरिजन जाति के लोग मित्ने हैं और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा नम्बर नहीं आया है । क्या मन्दी महोदया बताने की कृ पा करेंगी कि कंडैन्सड कोर्स के लिए भी रिजवेंशन की जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, रिजवेशन की जनरल पालिसी है जो सब जगह दाखिले में एडौप्ट की जाती हैं । अगर ये हमारे नोटिस में कोई केस लाएंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे । वैसे तो यह सवाल बी० ऐड० से सम्बन्धित है ।

श्री कंवल सिंह : मन्त्री महोदया ने बताया है कि निर्धारित सीमा के हिसाब से ही ऐडमिशन की जाती है । मेरी जानकारी के अनुसार हिसार बी ० ऐड ० कालेज में इन्होंने सौ सीटें दी है वहां पर छरू सौ के करीब ऐप्लीकेशंज आई थी और डबवाली के अन्दर 40– 45 ऐप्लीकेशंज आई थीं । हिसार का कालेज जींद, सिरसा और हिसार को कवर करता हद । वहां के प्रिसपिल ने रिकमैन्ड किया है कि हम दो सौ कैडीडेट्स को ट्रैनिंग दे सकते है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि वहां पर सीटें बढ़ाई जाएंगी keeping in view the increased number of applications ?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, कहन को तो सभी कह सकते है कि हम इतने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते है । गवर्नमैंट को नार्म्ज देखने पड़ते हैए कि वास्तव में कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है । अगर गवर्नमैंट पाच सौ की इजाजत दे दे, तो वह कोई ट्रेनिंग तो नही हुई ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया है कि बारह सौ दी ० ऐड ० टीचर्ज जे ० बी ० टी ० टीचर्ज –के अगैन्सट काम कर रहे है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या सभी ऐबजोर्ब हो जाएंगे ।

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, कुछ समय के उपरान्त तो हो ही जाएंगे ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, वी ० ऐड ० टीचर्ज अडल्ट ऐजूकेशन में भी पढ़ाते हैं । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उन टीचर्ज को बी ० ऐड ० के ग्रेड दिए जाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, अडल्ट ऐजूकेशन तो पार्ट टाईम जौब है और वह तो इससे बिल्कूल डिफरैन्ट मामला है ।

श्री कंबल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि डिफरैन्ट जिलों में डिफरैन्ट कालेजिज में कंगैसड ट्रैनिंग के लिए कितनी–कितनी सीटें दी हैं?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, बी ० ऐड० के ग्यारह कालेजिज हैं और हरेक में 125 कैडिडेटस ट्रेनिंग के लिए दिए हैं । हरेक जिले की इंफरमेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री कवंल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी जानकारी के अनुसार कई जिलों में तीन सौ सीटें दी हैं और हिसार में केवल सौ सीटें दी हैं जबकि हिसार तीन जगहों को कवर करता है ।

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, जो नार्म फिक्स है उसी के अनुसार हमने सीटें दी है जहां 3 सौ सीटें कह रहे हैं वहां कालेज भी ज्यादा है । हिसार वालों पर कोई पाबन्दी नही है । वे वहा चले जाए जहां ज्यादा सीटें है ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से मन्त्री' महोदया से यह जानना चाहता हूं कि बी ० ऐड० कालेजिज के इलावा दूसरे गवर्नमैंट कालेजिज या प्राईवेट कालेजिज में भी मरकार बी० एड० क्लासिज चालू करनें का विचार रखती है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नयी पालिसी के अनुसार न हम गवर्नमैंट कालेजिज में और न हीं प्राईवेट कालेजिज में बी० ऐड० क्लासिज शुरू कर रहे हैं । सरकार की नयी पालिसी के मुताबिक हर किले में एक ट्रेनिग इंस्टीच्यूट खोलने जा रहे है, जिसको गवर्नमैंट चलायेगी और उन के अन्दर प्रौपर तरीके से अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ।

Construction of Bus Queue Shelters

***1277.. Chaudhri Lila Krishan : Will the Minister for Transport** be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideraticn of the Government to construct Bus Queue Shelters in village Dhani Nanaksar on Fatehabad-Ratia Road and at the crossing of Bothan Road on Fatehabad Bhuna Link Road; and

(b) whether the constructicn of Bus Queue Shelters in village Daryapur on Fatehabad -Sirsa Road and Birrana crossing on Fatehabad-Bhuna Road has been started; if so, the time by which these are likely to be completed?

Transport Minister (Shri Amar Singh) :

(a) There is no such prcposal at present.

(b) Bus Queue Shelter in village Daryapur cn Fatehabad-Sirsa Road has already been constructed end Bus Queue Shelter at Tirana Crossing' on Fatehabad-Bhuna Read will be completed by the end of March, 1987.

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर सर, पिछले सैशन में मिनिस्टर साहब ने यह एलान किया था कि चण्डीगढ के पैटर्न पर हरियाणा के अन्दर भी सीमिटिड बस क्यू शैलटर्ज बनाये जाएंगे क्योंकि जो आयरन के बस क्यू शैल्टर्ज बने होते हैं, वे टूट जाते हैं या गिर जाते हैं । अब फिर सरकार वही लोहे के बस क्यू शैल्टर्ज बना रही है, इसके क्या कारण हैं?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष सहोदय, यह ठीक बात दे– कि पक्के बस क्यू शैलटर्ज बनाने का सरकार ने फैसला किया हुआ है लेकिन जहां पर पी० डब्ल्यू० डी ० की जमीन हो और वे हमें नो. औबजैक्शन सर्टिफिकेट दे दें तो वहां पर इनका निर्माण करते है । जहां गांव के अन्दर वस क्यू शैल्टर्ज बनने हों, वहां पर पंचायत की. जमीन होती है । अगर पंचायत जमीन दे दे तो उस जगह पर पक्के शैड्स बना देते हैं, नहीं तो आयरन के बस क्यू शैल्टर्ज बना देते हैं ।

श्री कंबल सिंह : स्पीकर साहब, यह सवाल हिसार जिले से सम्बन्धित है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि

हिसार के अन्दर मायड में, जो एक इम्पौटैट जंक्शन है, क्या बस क्यू शैल्टर बनाने के लिये सरकार विचार करेगी?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा के अन्दर केवल अम्बाला और गुड़गांव में दो बस–स्टैण्डज ही होते थे और अब इस समय 36 बस स्टैण्डज बन चुके हैं । बस क्यू शैल्टर्ज 1982–83 में 100, 1983–84 में 100, 1984–85 में 140, 1985–86 में 140 और 1986–87 में अब तक 130 बनाये जा चुके हैं । मैम्बर साहब ने मायड गांव में जोकि जरूरी जंक्शन है, बस क्यू शैल्टर बनाने की बात की है । उस बारे में बता देना चाहता हूं कि हमारी एक ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट आती है । अगर पंचायत या सराउंडिंग विलेजिज वालों ने इस बारे में कोई आवेदन किया होगा तो मैं इस बारे में अपने जी ० एम० साहब से बात करूंगा । अगर वहां पर पंचायत जमींन दे तो पक्का बस क्यू शैल्टर बना देंगे । अगर पंचायत जमीन न दे तो वहां पर फिलहाल टीन का शैल्टर बना कर दे देंगे बशर्ते कि वहां के लोगों से मांग आई हो ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, जहां पर जी ० टी ० रोड है वहां पर 150 फीट चौड़ी सड़क है और वहां पर बस क्यू शैल्टर्ज बनाने के लिये और जमीन की आवश्यकता नही होती क्योंकि बस क्यू शैल्टर्ज के लिये केवल 10 फीट जमीन की ही आवश्यकता होती है । ऐसी जगहों पर टैम्पोरेरी लोहे के शैडज

की बजाये पक्के सीमिंटड शैड्जही बना दिये जाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा है कि जहां जमीन अवेलेबल हो और पी ० डब्ल्यू ० डी ० वालों को कोई एतराज न हो तो वहां पर हम पक्के शैड्ज बनाएंगे ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात लाना –चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर बहुत से बस स्टैण्डज ऐसे हैं जोकि गांवों से दूर पड़ते हैं और गर्मियों में सवारियों को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है । बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को काफी दिक्कत होती है । ऐसी जगहों पर पानी का भी कोई बन्दोबस्त नहीं है । क्या ऐसी जगहों पर, जहां पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है, हरियाणा रोडवेज इस डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करेगी और कब तक इसका इन्तजाम हो जाएगा?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मैम्बर साहब किसी पर्टीकुलर जगह के बारे में बताएंगे तो उनके इस प्वायंट को हम कंसिडर करेंगे ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल बस क्यू शैल्टर्ज बनाने से सम्बन्ध रखता है लेकिन मैं लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं । कई बार बालियों को रात को बस वगैरह नहीं मिलती

हैं और उनको बस अड्डों पर ही रहना पड़ता है । क्या बालियों की. सुविधाओं के लिये बस अड्डे? पर धर्मशाला वगैरह या उनके ठहरने का कोई बन्दोबस्त किया जाएगा?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल क्यू शेल्टर्ज से सम्बन्धित है लेंकिन मैं माननीय– मैम्बर साहब की जानकारी के लिये बता देता हूं कि बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए केटरिंग व ठहरने आदि का सभी प्रकार का इन्तजाम होता है । वहां बैचिंज वगैरह बनाए हुए हैं ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, रादौर के अन्दर 'ए' क्लास बस स्टैण्ड बना हुआ है लेकिन वहां पर टायलैट और पानी वगैरह का कोई खास बन्दोबस्त नहीं है जिस कारण से औरतों व दूसरे लोगों को काफी मुश्किलात आती हैं । क्या मिनिस्टर महोदय वहां पर यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा देने का विचार करेंगे क्योंकि खासतौर से औरतों वगैरह को टायलैट न होने के कारण काफी मुश्किल होती है?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैम्बर साहब ने जो कहा है उसको हम ऐग्जामिन करवों लेगे । अगर कोई आवश्यकता हुई तौ देख लेंगे । वैसे हर बस स्टैण्ड पर यात्रियों की हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है ।

चौधरी लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल के पार्ट 'ए' मैं दो बस क्यू शैल्टर्ज बनाने के बारे में रिकवैस्ट की

है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह दरखास्त करुगा कि वहा पर बस क्यू–शैल्टर्ज का निर्माण करवा दिया जाए क्योंकि उनका कोई खास खर्चा भी नहीं आएगा । क्या फतेहाबाद–रतिया सडक पर –दानी नानकसर में व फतेहाबाद–भूना लिंक सड़क पर बोथान सड़क के क्रोसिंग पर बस क्यू शैल्टर्ज बनाने के लिये सरकार दोबारा विचार करेगी ताकि लोगों को जो इम समय दिक्कत हो रही है. वह दूर हो ?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, जी ० एम० साहब मै एक ट्रेफिक सर्वे रिपोर्ट आती है । उस के आने के बाद इस पर विचार करेंगे और बना देंगे ।

चौधरी लीला कृष्ण : धन्यवाद जी ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, पिछली बार मन्त्री जी ने इम हाउस में यह आश्वासन दिया था कि अम्बाला का बस स्टैण्ड 31 मार्च, 1987 तक बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन अभी तक तो वहां पर मिट्टी पड़का ही शुरू हुई है । कया मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देगे कि यह बस स्टैण्ड कब तक बनकर तैयार हो जाएगा '?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया था लेकिन मैं फिर बता देना चाहता हूं कि अम्बाला कैन्ट का बस स्टैण्ड निहायत जरूरी है और इसको हम बहुत जल्दी ही पूरा कर रहे हैं ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, सरकार जो बस क्यू शैल्टर्ज बनाती एं, अमूमन यह देखा गया है कि वहां जगह बहुत थोड़ी होती है । फर्श कच्चे होते हैं और लोगों को बैठने के लिये जगह नहीं मिलती । काफी मुश्किलात होती हैं । इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि कम से कम बस क्यू शैल्टर्ज के फर्श तो पक्के करवा दिये जाएं ताकि लोग बसों की इन्तजार करने के लिये वहां आराम से बैठ तो सके ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, बस क्यू शैल्टर्ज जहां पर बनाये जाते हैं वहां पर सीमिन्ट के पक्के बैचिंज वगैरह बनाये जाते हैं ताकि लोगों को बैठने के लिये तकलीफ न हो । जहां कहो ऐसा बस क्यू शैल्टर बना हुआ है. आनरेबल मैम्बर उस बारे में हमें बता दें हम वहां पर काम करवा देंगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, बस स्टैडंज पर जो लैट्रीन और बाथ रूम बने हुए हैं वे बहुत गन्दे रहते हैं । वहां पर आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता । क्या मन्त्री जी उनकी सफाई करवाने का प्रबन्ध करवाएंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, इनकी बात ठीक है कि सैनेटरी कंडीशन का इन्तजाम अभी पूरा नहीं है हम इसकी सफाई का पूरा इन्तजाम करवाएंगे । जहां तक बस अड्डों का सवाल है मैंने पहले भी जानकारी दी थी और अब भी हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं । अम्बाला जिले में अम्बाला सिटी, यमुना

नगर और जगाधरी में हैं । करनाल जिले में करनाल, पानीपत और इन्दरी में है । कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र, पेहवा, पु डरी, कौल, लाडवा, रादौर और शाहबाद में हैं । सोनीपत जिले में सोनीपत और गोहाना में हैं । जींद जिले में जीन्द और नरवाना में है । हिसार जिले मे हिसार, फतेहाबाद, हांसी., टोहाना आदमपुर और भट्टू कलां में हए । भिवानी जिले में भिवानी, तोशाम. बवानी खेडा और सिवानी में हैं । गुड़गांव जिले में गुड़गांव में तथा फरीदाबाद जिले में पलवल में हैं । महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल में है, कनीना में है और रिवाडी में है । रोहतक जिले में रोहतक और बहादुरगढ़ में हैं । स्पीकर साहब, तुक नवम्बर., 1966 के बाद हरियाणा में कुल 3 5 बस अड्डे बने है । इसके अलावा हमारे 16 बस अड्डे ऐसे हैं जो 31 मार्च, 1987 तक कम्पलीट हो जाएंगे । 44 बस अड्डे– ऐसे हैं जिनमें किसी की जमीन एक्वायर हो चुकी है और किसी की साइट ऐप्रूवल के लिए मामला अन्डर ऐग्जामिनेशन है । इस तरह से. 60 बस अड्डे हमारे अंडर कंस्ट्रकशन हैं और 35 कम्पलीट कर दिए हैं । इसके अलावा 610 बस क्यू शैल्टर्ज 1986–87 तक कम्पलीट हो जाएंगे । सरकार ने हर साल 113 बस क्यू शैल्टर्ज बनाने का फैसला किया हए और 1987–88 में भी 130 के लगभग बस क्यू शैल्टर्ज बनेंगे । जहां तक सैनेटरी कंडीशन का सवाल है इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई द्र । वह पड़ताल कर रही है । जहां जहां सैनेटरी कंडीशन पुअर है उसको इम्प्रूव करवाएंगे । आगे के लिए पैसेंजर्ज को इम बारे में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी' ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, औरतों की बगल में बच्चे भी होते है । क्या मंत्री जी जहां जहां बस अड्डे बने हुए हैं वहां पीने के पानी का प्रबन्ध करेंगे?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का जवाब पहले आ चुका है ।

श्री मोहन लाल पिपल : स्पीकर साहब, पटौदी और हेली मंडी में पहले अलग अलग दो नगरपालिकाएं थीं लेकिन अब एक नगर–पालिका हो गई है । क्या मन्त्री जी अगले सारन पटौदी में बस स्टैड बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर इस बारे में वहां से डिमांड भिजवा दें । हम ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट मंगवा लेगे, अगर वहां बस अड्डा बनाने की जरूरत होगी तो जरूर बनाएंगे ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ–हिसार, चण्डीगढ–सिरसा और चण्डीगढ– बरवाला रूट पर जो बसें जाती हैं और आती हैं उनमें सफाई नहीं होती । क्या सफाई के लिए इन्होंने कर्मचारी नही छोड़ रखे हैं? आप देखें कि बसों के अन्दर रेत, मूंगफली के छिलके तथा फटी हुई टिकटों के कागज सवारियां फैंक देती हैं और उसकी सफाई कोई नहीं करता । क्या इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, हमने अभी हिदायत दी है कि जो लौंग रूट की बसें हैं उनमे बाकायदा सफाई का इंतजाम किया जाए और सफाई होती भी है । मेरे लायक दोस्त

किसी बस का नंबर बताएं और टाइम बताएं, हम उसकी बाकायदा जांच करवाएंगे । हमारा सफाई की तरफ पूरा ध्यान है । जहां बसें रात को ठहरती हैं और सुबह चलती हैं वहां सफाई का बाकायदा इन्तजाम है ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, पीछे चार दिन की छुट्टी हुई थी तो मैं अपने घर गया था वह बस बहुत गन्दी थी । उस बस का नम्बर तो मेरे याद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप नम्बर बताएं, नम्बर के बगैर ये क्या कार्यवाही कर सकते है।

चौधरी शकरूल्ला खां : स्पीकर साहब, मेवात के एरिया में सब से बड़ा गांव पुन्हाना है । वहां पररू 1938 से बस सर्विस चालू है क्योंकि पहले प्राइवेट गाड़ियां भी चलती थीं लेकिन आज तक वहां पर कोई बस स्टैंड नहीं है । ड्राईवर लोग सड़क पर ही गाडी खड़ी करते हैं और कंडक्टर सड़क पर बैठ कर ही टिकट काटता है । क्या वहां पर बस स्टैंड बनाने की कोई स्कीम है?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मैंबर साहब यह बात अभी सरकार के नोटिस में लाए हैं । ये मुझे अलग से सारी बात बता दें और वहां की डिमांड क्रिएट करवा दें । हम ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट मंगवा कर कंसिडर कर लेगे कि वहां पर बस स्टैंड की जरूरत है या नही ।

श्री बनारसी दास : बाल्मीकि स्पीकर साहब, झज्जर का बस अड्डा बनना शुरू हो गया है लेकिन उसके फर्श और दरवाजों का काम बाकी रहता एं । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वह कब तक पूरा करवा देंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, झज्जर के बस अड्डे का काम चालू है और हम इसको जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि 600 से कुछ अधिक क्यू शैल्टर्ज बनाए जगाते । क्या इन क्यू शैल्टर्ज को हर एम० एल० ए० के हल्के में बराबर बराबर बांटेंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, क्यू शल्टर्ज हल्का वाइज नहीं बल्कि डिपो वाइज बनाए जाते हैं । हम 10– 10 क्यू शल्टर्ज डिपो वाइज बांटते हैं । हमारे 15 डिपो हैं । ये जी ० एम० के द्वारा अपनी डिमांड भिजवा दें, अगर जरुरत होगी तो ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट को देख कर वहां बना देंगे ।

श्री कैनल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने सैनेटरी कंडीशन के लिए एक कमेटी बनाने की सूचना दी है । मैं जानना चाहता हूं कि उस कमेटी के कौन कौन मैम्बर हैं और उसकी टर्म्ज आफ रैफरेंस क्या है? अगर उस कमेटी की यह रिपोर्ट आ जाए कि वाक्या ही कंडीशन ठीक नहीं है तो उसकी सिफारिशों को इम्पलीमैंट करने मे कितना समय लगेगा?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, यह कमेटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता ये बनाई गई है । हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत देंगे कि वे जनरल मैनेजर्ज की डियूटी लगाएं कि वे रिपोर्ट करें कि कौन कौन से बस अड्डों पर सैनेटरी की कंडीशन ठीक नहीं है । मेरा ख्याल है कि वे एक डेढ़ महीने के अन्दर रिपोर्ट कर देंगे । उसके बाद जहां जहां की कंडीशन पूअर होगी उसको इम्प्रूव करवा देंगे । हम पब्लिक हैल्थ और पी० डब्ल्यू० डी० वालों का ताल मेल करवा कर सारी फैसिलिटीज देंगे ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया कि बस क्यू शैल्टर्ज बनाने के लिये अपनी डिमांड जी ० एम० को भेजी जाए और अगर जरूरत होगी तो बना दिए जाएंगे । मैं पिछले दो तीन साल से लगातार 2–3 गांवों में बस क्यू शैल्टर्ज बनाने केलिए डिमांड भेजता आ रहा हूं लेकिन जी ० एम० ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की । क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जाएगी?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, अगर वहां पर पंचायत है और वह जमीन देने के लिए तैयार है तो सर्वे रिपोर्ट आने पर वहां जरूर बना देंगे ।

चौधरी रोशन लाल : आर्य अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के यह बात विचाराधीन है कि बस अड्डों पर जितनी भी दुकानें हैं उनको शहीद सैनिकों के परिवारों, स्वतन्त्रता सेनानियों को, अपंगों

को और पिछड़े वर्ग के लोगों को अलौट किया जाएगा? दूसरी बात क्या यह भी विचाराधीन है कि इन दुकानों का किराया रीजनेबल लिया जाएगा? हम जब किसी से पूछते हैं कि भाई हुस दुकान का किराया कितना देते हो तो वह बताता है कि 22 हजार रुपया महीना देतो हूं । तो वह यह सारा पैसा पालियों के सिर से निकालता है । जैसे सोडा वाटर है, अगर वह बाजार में एक रुपए का है तो बस अड्डे पर 2–3 रुपए का देते हैं । सवारी जल्दी में दूर नही जाँ सकती और उसको वही से चीज लेनी पड़ती है । यह बड़ी भारी दिक्कत है । क्या इस दिक्कत को दूर करने के लिए कुछ किया जाएगा?

10.00 बजे

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, जब से मैने ट्रांसपोर्ट विभाग को टेक ओवर किया है उसके बाद से मैंने एक जनरल सर्वे कराने के आदेश दिए है कि बस अड्डों पर जो चीजें मिलें वे मार्किट के मुकाबले महंगी न मिलें । दूसरा सवाल यह किया गया है कि जो दुकाने वहा पर लोगो को दी जाती है वे बहुत महंगी दी जाती है । स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट विभाग एक कमर्शियल विभाग है । हम इन दुकानों को औक्शन के जरिए देते हैं । औक्शन में जो ज्यादा बोली लगाता है उसी को दुकान दी जाती है । यह औक्शन हम हर साल एक साल के लिए करते हैं । इसका और कोई रास्ता नही निकाला जा सकता कि ये दुकानें कम रेट पर लोगों को दी जा सकें । इसके अलावा हमने यह भी

निर्णय लियन है कि बस अड्डों की दुकानों पर जो आईटम्ज मिलें, वे सब–स्टैन्डर्ड की न हों और मार्किट के रेट पर ही वहां पर यात्रियों को चीजे मिले । यह हमने इसलिये किया है ताकि लोगों को कोई तकलीफ वहां से सामान खरीदने में न हो और उनकी जेबें बस अड्डों वाली दुकानों पर न काटी जायें ।

चौधरी प्रभु राम : अध्यक्ष महोदय सढ़ौरा और बिलासपुर में कोई बस अड्डा नही है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों स्थानों पर कब तक बस अड्डा बना दिया जायेगा ?

श्री अमर सिंह : जहां आनरेबल मैम्बर बस स्टैड बनवाना चाहते हैं, लिख कर भिजवा दें, उसको जरूर कंसीडर करवायेगे ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, सफीदों के अन्दर सब डिपू है और वहां बस स्टैड का कार्य शुरू करवाया गया छपा लेकिन अव किसी रुकावट की वजह से उस बस स्टैंड के कार्य को बंद कर दिया गया है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस बस स्टैंड का कार्य पुनः कब तक चालू हो जायेगा?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमैंटरी का इस सवाल से कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सफीदों में इस समय बसें शहर के अन्दर से गुजरती है । शहर के अन्दर कई जगहों पर बसों को नाइन्टी डिग्री एंगल से टर्न करना पड़ता है जिसकी वजह से वहां पर आगे दिन ऐक्सीडैन्टस होते रहते हैं । इसी वात को

ध्यान में रखते हुए बस स्टैण्ड को शहर से बाहर बनाया जाना उचित समझा गया । बस स्टैण्ड के लिए तो जमीन भी हए और पैसा भी निर्धारित किया हुआ है और पी ० डब्ल्यू० डी० विभाग भी बस अड्डा बनाने के लिए तैयार है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये अभी तक बाई पास के लिये जमीन नही दिलवा पाये हैं । क्योंकि अब बसें शहर के बाहर से गुजरनी हैं इसलिये जब तक वाई पास के लिए जमीन नहीं मिल जाती और बाई पास नही बन जाता तव तक वहां के बस स्टैण्ड के लिए जो साइट भी ऐप्रूवड है काम करना असंभव है । मै इनसे फिर कहता हूं कि ये बाई पास के लिए जमीन दिलवा दें, काम शुरू करवा दिया जायेगा ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन शहरो में लोकल बसे चलती हैं क्या वहां पर हर स्टौप पर बस क्यू शैल्टर बनाये जायेंगे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, क्या उन के अन्दर लोकल बम सेवा शुरू की जायेगी

श्री अमर सिंह :' स्पीकर सहिब, हर स्टाप पर तो बस क्यू शैल्टर नहीं बनाया जा सकता । जैसे आप गुड़गांव शहर को ही ले लें । यह बहुत बडा शहर है । इस शहर के अन्दर कम से क्रम 100 बस स्टौप होंगे । इसलिए हर जगह क्यू शल्टर बनाया जाना असंभव है । जहां पर मैम्बर साहब –मनवाना उचित समझते हैं वहां के लिए डिमाड भिजवा दें, उस जगह जरूर बनाया जा सकता है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, कैथल डिपू है लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैड क्र्वाटर कुरुक्षेत्र है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट हैड–क्र्वाटर कुरुक्षेत्र कौ भी डिपू बनाया जायेगा ?

श्री अमर सिंह : कैथल बहुत गुराना डिपू है । इसके अलावा कुरुक्षेव में सब– डिपू है । कुरुक्षेत्र को डिपू बनाया जाना जब जरूरी समझा जायेगा तो बना दिया जायेगा ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : स्पीकर माहब, मैंने मन्त्री जो दो कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था, उसका पूरा जवाब इन्होंने नहीं दिया है । मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि बस स्टैण्डों पर जो दुकानें दी जाती है क्या वे शहीद सैनिकों की विधवाओं या उनके परिवार वाला, ऐक्स सर्विस मैन अपगों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए रिजर्व करेंगे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या प्रत्येक बस अड्डे पर जो सामान वहां बेचा जा रहा हो, उसकी रेट लिस्ट लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । ये आपके सवाल का पहले जवाब दे चुके हैं ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, बस अड्डों पर जेबें काटे जाने की आम शिकायतें सुनने में आती हैं । कई बार हमारी जेब भी कटी है । क्या मन्त्री जी बस अड्डों पर यात्रियों की जेखे न काटी जाये इसका कोई इन्तजाम करेंगे ?

श्री अमर सिंह : यदि ऐसी कोई जानकारी मैम्बर साहब को हो तो हमें बता दें, जरूर कार्यवाही की जायेगी । वैसे हर बड़े बस अड्डे पर पुलिस का इन्तजाम है और वहां पर पुलिस हमेशा सतर्क रहती है ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत 'से मस्ती जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हू कि उकलाना और नरवाना तथा उकलाना और हिसार के रास्ते में शाम के वक्त सवारियों की बहुत भारी भीड़ हो जाती है । उसका एक कारण तो यह है कि जो बच्चे उकलाना से नरवाना और हिसार पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें वापस आना होता है । इन दोनों रूटों पर जो लम्बे रूट की बसें चलती हैं वे छोटे रूट की सवारियों को नहीं उठाती जिससे सवारियों को बहुत दिक्कत आती है । उकलाना और नरवाना के बीच एक दिनोदा गांव है । वहां की सवारियों को भी आने–जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता हए । नरवाना से या हिसार से सवारियां जब लम्बे रूट वाली बसों में बैठ जाती हैं तो वस के ड्राइवर और कन्डक्टर्ज उन सवारियों को रास्ते में उतारते नहीं हैं जिसकी वजह से उनका आपस में झगड़ा होता हे । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे रूटों पर स्पैशल बसें चलायी जाएंगी ताकि स्कूल के बच्चों और आम सवारियों को कोई दिक्कत न हो?

श्री अमर सिंह : जहां जहां पर इनको कठिनाई नजर आती है, वहां के बारे में लिख कर भेज दे जांच पड़ताल करवा कर कोई इन्तजाम करवा देंगे ।

Pensionary Benefits to Employees of Municipal Committees

***1251. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether the employees of the Municipal Committees are entitled to the Pensionary benefits and; if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to amend the Haryana Municipal Act, 1973 so as to make the employees of the Municipal Committees eligible for pensionary benefits?

Minister of State for Local Government (Shri Lachhman Dass Arora) : No, Sir. However, the demand of municipal employees for grant of pensionary benefits is being examined.

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब '' यस' ' और ''नो'' में दे कर गोलमोल कर दिया है । 1976– 77 में चौधरी बंसी लाल जी जब डिफैन्स मिनिस्टर थे तो उस समय वहां के कैन्टोनमैंट बोर्ड का 60 प्रतिशत एरिया लेकर अम्बाला कैन्ट में एक न्यू म्यूसिपल कमेटी बनवा दी थी । मेरा सवाल यह है कि कैन्टोनमैंट बोर्ड में काम कर ने वाले कर्मचारियों को तो पैन्शन की सुविधा लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी में काम करने वाले कर्मचारियों को पैन्शन की सुविधा नहीं है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या

म्यूनिसिपल ऐक्ट 1973 की धारा 38 के तहत वहां की नगरपालिका के कर्मचारियों को पैन्शन की सुविधा दी जायेगी ?

श्री लच्छन दास अरोडा : इसके लए हमने एक कमेटी बनाई है । कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही कुछ ऐक्शन लया जायेगा ।

सेठ राम दास धमीजा : क्या म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 38 को तरमीम करके वहां की नगरपालिका के कर्मचारियों को पैन्शन देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री लछमन दास अरोडा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि –एगने एक कमेटी बनाई हुई है । जब तवा उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कोई कमिटमैंट नहीं कर सकते ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माली जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा स्टेट के बाकी. डिपार्टमैंट्स के ऐम्पलाइज में और म्यूनिसिपल कमेटीज के ऐम्पलाइज में यह डिसक्रिमिनेशन क्यों है ?इ क्या हमदर्दी से विचार करके उन्हें एट पार लाया जाएगा?

श्री लछमन दास अरोडा : स्पीकर साहब, मैं पहले ही कह चुका हु कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर सिम्पेथैटिकली विचार किया जाएगा ।

Construction of Siphon in village Bhodia Khera

***1278. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Siphon in village Bhcdia Khera of Fatehabad constituency to pump out the flooded water; and

(b) if so, the time by which the said construction is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) No. Sir.

(b) The question does not arise in view of (a) above.

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर सर, भोडिया खेड़ा गांव फतेहाबाद से 2 किलोमीटर दूर है । बरसात के दिनों में वहां फलड का पानी 20–20 दिनों तक खड़ा रहता है । किसी ओफिसर ने आज तक मौके पर जाकर वहां की हालत नहीं देखी है । क्या मन्त्री जी विश्वास दिलाएंगे कि कोई टीम भेज कर मौका दिखाया जाएगा और वहां साईफन बनवा कर लोगों को राहत दी जाएगी?

चौधरी शमशेर सिह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, भोडिया खेड़ा गांव के पारा से कैनाल गुजरती है । मैंने डिपार्टमैंट से पता किया है और मुझे बताया गया है कि कैनाल में ब्रीच होने

की वजह में पानी वहां खड़ा हो गया था । उनका यह भी कहना है कि वहां आज तक कभी फ्लड नही माता । माननीय मैम्बर चूंकि इस बात पर ऐम्फेसिज दे रहे हैं इसलिए मैं किसी सीनियर औफिसर को भेज कर इसका जरूर पता करवाऊंगा । अगर फ्लड की बात सही हुई तो लिड वाटर को ड्रेन आउट करने का इन्तजाम करेंगे । लेकिन स्पीकर सर, हुनकी मांग पानी को ड्रेन आउट करने की नहीं है । इनकी मांग है कि कैनाल के नीचे साइफन बना दिया जाए । मगर स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी कैनाल या डिस्ट्रिव्यूटरी के नीचे हम साईफन नही बनाते क्योंकि उससे बीच हेने का अन्देशा बना रहता है । इसलिए वहां साईफन तो नहीं वनाया जा सकता लेकिन फ्लड को ईज करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वे करेंगे और मैं इसका पता भी करवा लूंगा ।

Mr. Speaker : Questicns are over.

वक्तव्य–

स्थानीय शासन राज्य मंत्री द्वारा गुड़गांव शहर के कुछ क्षेओ में भूमिगत पेयजल

मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अव थी धर्मबीर गाबा, एम ० एल ० ए ०. के काल अटैन्शन मोशन नं० 3@ जो गुड़गांव शहर के ड्रिकिंग वाटर बीइंग अन फिट फार हयूमैन कंजम्पशन

ऐटसैट्रा ऐटसैट्रा के बारे में दिया गया था, के सम्बन्ध में मिनिस्टर औफ स्टेट कार पब्लिक हैल्थ अपनी स्टेटमैंट देने की कृपा करेंगे ।

जन स्वास्थय राज्य मन्त्री (श्री ए ० सी ० चौधरी) : स्पीकर साहब, इसके बारे में स्टेटमैंट अरोडा साहब देंगे क्योंकि लोकल बौडीज को वे डील करते हैं ।

Mr. Speaker : All right.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा) : स्पीकर साहब, मदनपुरी, शिवाजी पार्क और ओम नगर क्रालोनियां नगरपालिका के अन्दर अनअथोराईज्ड (गैर मंजूर शुद्धा) कालोनियां हैं । इन कालोनियों के अन्दर नगरपालिका की ओर से पीने के पानी की सप्लाई का कोई प्रबन्ध नहीं है । इन कालोनियों के निवासियों ने निजी रूर से हैण्ड पम्प लगा रखे हए, जहां से वह अपने कम गहरे हैण्ड पम्पों से पानी लेते हैं । मदनपुरी के हैण्ड पम्पो से लिये गये पानी के नमूनों को टैस्ट करवाने पर यह पाया गया कि पानी के अन्दर फलोराईड की मिकदार निर्धारित सीमा से अधिक है । यह बताना उचित होगा कि मदनपुरी के इर्द–गिर्द 5 नलके (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट) इस कालोनी के निवासियों की सुविधा के लिये लगाये हुए हैं, जोकि शहर की वाटर सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं । जो पानी कमेटी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, उसमें फलोराईड की मिकदार निर्धारित सीमा के अन्दर है ।

गुडगावां शहर में आमतौर पर जमीन के नीचे जो पानी है, उसकी क्वालिटी सन्तोषजनक नही है । कहीं–कही पर पानी पीने के योग्य कूँ तथा उन जगहों पर 24 नलकूप (टयूबवैल/कुए) Percolation wells लगाये हुये है । इसके अलावा गुडगावा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव बादशाहपूर मे 7 नलकूप (टयूबवैल) लगाये हुये हैं, जोकि शहर की वाटर सप्लाई को अतिरिक्त पानी देने हैं । शहर के अन्दर वाले टयूबवैलो से जो पानी मिलता है, उसकी कुल औसत मिकदार 10 लाख गैलन प्रतिदिन है और बादशाहपुर के नलकूपों मे मिलने वाले पानी की कुल औसत मिकदार 6 लाख गैलन प्रतिदिन तूँ । इस प्रकार गुडगावां में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 18 गैलन पानी उपलब्ध है । पिछले 2 महीनों में म्यू– निसिपल वाटर सप्लाई के 9 सैम्पल इकट्ठे करके टैस्ट करवाये गये थे । इन सभी सैम्पलों में फलोराईड की मिकदार निर्धारित सीमा के अन्दर पाई गई थी । सभी की सारी म्यूनिसिपल वाटर स्पलाई को प्रतिदिन क्लौरीनेट करवाया जाता है । इस लिये इममें किमी प्रकार के कीटाणु आदि शेष नही रहते ।

गुडगावा शहर तथा उसके आम–पास के इन्नाके में जमीन से मिलने वाले पानी की मिकदार तथा क्वालिटी दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही हुए लेकिन शहर को जो पानी दिया जा रहा है, वह पीने के लिये ठीक होता है । गुडुगावां शहर में पानी की कमी की समस्या से सरकार भली भान्ति जानकार है ।

अभी पिछले महीने ही शहर की वाटर सप्लाई ये बढ़ोतरी के लिये 8 लाख रुपये की धनराशि बादशाह पुर गांव में 3 नये टयूबवैल लगाने हेतु दी गई है ।

जहां तक पानी के अन्य स्रोत का सम्बन्ध है, हुड्डा ने नहर के पानी पर आधारित एक स्कीम तैयार की है, जिससे कि शहरी सम्पदा तथा नगरपालिका के इलाके को पानी दिया जायेगा । इस मनोरथ के लिये 70 किलोमीटर लम्बी नहर के जरिये गुडगावां शहर के पास पानी लाया जायेगा और उमे शुद्ध करके सप्लाई किया जायेगा ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, इस स्टेटमैंट में तो कहा गया है कि वाटर सप्लाई की पोजीशन ठीक ही चल रही है लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कालोनीज में पीने का पानी नही हद उन्हें आप पानी देते या नहीं? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय इन्हेने यह कही कि फ्लोराइड इन्होंने चौक करवाया है और वह म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा सप्लाई कितु जाने वाले पानी में ठीक पाया गया । लेकिन मेरा सवाल यह है कि कालोनीज की वाटर सप्लाई में अगर फ्लोराइड की माला ज्यादा होगी तो उसका क्या फायदा है ? क्या मन्त्री जी बताएगें कि फ्लोराइड की सही मिकदार कितनी होनी चाहिए ?

श्री लछमन दास अरोडा : स्पीकर साहब, फ्लोराइड डेढ परसैन्ट तक ठीक होता है लेकिन वहां 5 परसैन्ट है । पानी

सप्लाई करने का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने अभी..बताया कि एक नई स्कीम बनी है और अढाई महीने के अन्दर इनकी जो कालोनीज बाकी है उनमें पब्लिक स्टैन्ड पोस्टस लगा करके वाटर वर्क्स का पानी देने जा रहे हैं । इसके अलावा, मैं यह भी बता दू कि हमने लोगों को दवाई और गोलियां आदि देनी शुरू की हैं और लोगों को समझाना शुरू किया हे कि इस तरीके से पानी को इस्तेमाल करें ।

समितियों की रिपोर्टस पेश करना–

(1) कमेटी औन पब्लिक अकाउन्टस की 25वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब कमेटी औन पब्लिक अकाउन्टस के चेयरमैन, सेठ राम दास धमीजा, कमेटी की ईयर 1988–87 के लिये 25 वी रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Seth Ram Dass Dhamija (Chairman, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Twenty Fifth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1986-87 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-82 (Civil and Revenue Receipts).

(2) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 23वीं, 24वीं, 25वीं और 26वीं रिपोर्टस

श्री अध्यक्ष : अब कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के चेयरमैन, श्री कंवल सिंह कमेटी की ईयर 1986–87 के लिए 23वीं, 24वीं, 25वीं तथा 26वीं रिपोर्टस पेश करेंगे ।

Shri Katmai Singh (Chairman, Committee cn Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Twenty Third, Twenty Fourth, Twenty Fifth and Twenty Sixth Reports of the Committee on Fublic Undertakings for the year 1986-87 on-

(a) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-82 relating tc Haryana Agro Industries Corporation Limited;

(b) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1982-83 relating to Haryana State Handlocm and Handicrafts Corporation Limited ;

(c) the General working of Kurukshetra Development Board; and

(d) the General working of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited.

(3) कमेटी औन दि वैलफेयर औफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शड्यूल्ड ट्राइडस की 12वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शड्यूल्ड ट्राइब्ज के चेयरमैन, चौधरी नेकी राम, कमेटी की ईयर 1988– 87 के लिये 12वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

श्री नेकी राम (चेयरमैन, कमेटी आन दि वेल्फेयर आफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शड्यूल्ड ट्राइब्ज) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1988–87 के लिए अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए समिति की 12वीं रिपोर्ट सदन में सादर प्रस्तुत करता हू ।

(4) कमेटी औन सबार्डिनेट लैजिस्लेशन की 18बीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब चेयरमैन, कमेटी औन सबार्डिनेट लैजिस्लेशन, चौधरी साहब सिंह सैनी, कमेटी की ईयर 1986–87 के लिये 18 वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Chaudhri Sahab Singh Saini (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, **I** beg to present the Eighteenth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1986-87.

(5) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैंसिज की 18वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज के चेयरमैन, राव निहाल सिंह, कमेटी की ईयर 1986–87 के लिये 18 बी रिपोर्ट पेश करेगे ।

Shri Nihal Singh (Chairman, Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Eighteenth Report of the Committee on Government Assurances for the

year 1986-87.

वर्ष 1987– 88 के बजट पर अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1987–88 के बजट की डिमांडज कार ग्रान्टस पर डिस्कशन होगी ।

पहली प्रैक्टिस कें मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करन कें लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमान्डज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी । आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते है लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों । डिस्कशन के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जायेंगी ।

That a sum not exceeding Rs. 94,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 22,53,62,009 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 56,20,59,000 for

revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 11,36,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 5,83,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 31,14,48,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 89,72,06,000 for revenue expenditure and Rs. 38,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 34,99,95,000 for revenue expenditure and Rs. 38,22,53,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 1,78,79,00,000 for

revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 1,07,59,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 18—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 6,16,25.000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demad No. 10—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 10,36,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 12—Labouur & Employment

That a sum not exceeding Rs.. 36,53,20,000 for revenue expenditure and Rs. 2,37,18,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the yeear 1987-88 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare and Re-habilitation.

That a sum not exceeding Rs. 2,72,50,000 for revenue expenditure and Rs. 1,67,70,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 14—Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,88,24,000 for revenue expenditure and Rs. 1,32,66,99,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 10,67,46,000 for revenue expenditure and Rs. 4,29,36,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 49,33,87,000 for revenue expenditure and Rs. 3,93,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 16,21,30,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 2,40,17,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 22,92,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 36,26,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 5,95,66,000 for revenue expenditure and Rs. 5,92,78,003 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,75,78,000 for revenue expenditure and Rs. 13,50,50.009 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will Come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 1,53,41,000 for revenue expenditure and Rs. 1,08,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2,37,19,64,009 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 25—Loans and Advances by State

Government.

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, जिन मैम्बर्ज को बजट पर बोलने का मौका नही मिला है उन्हें डिमांडज पर बोलने के लिये ज्यादा टाईम दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस बात का ख्याल रखा जायेगा ।

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 4, 8, 9, 10, 13, 15 और 18 के बारे में बोलना चाहूंगा । सब से पहली डिमांड नम्बर चार है जो रैवेन्यू के बारे में है । रैवेन्यू विभाग में पटवारी होते हैं । आपको भी पता होगा कि पटवारी गांवों में किसी के घर पर बैठ जाते हैं और वहीं पर काम करते रहते हैं । गांवों के लोग यह समझने लगते हैं कि यह पटवारी इन्ही का अपना आदमी है । आपको यह भी पता ही है कि गांवों में पार्टीबाजी होती है जिसके कारण दूसरे लोग, जिस घर पर पटवारी काम करता है वहां जाना पसन्द नही करते और उनके मन में यही भाव होता है कि यह उन्ही की मानता है, उनकी सिफारिश से ही काम करेगा जिसके कारण उनके काम रह जाते हैं । पहले जमाने में गांवों में पटवारखाना होता था लेकिन अब नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में पटवार खाना खोला जाये, बाकायदा पटवारी का दफतर हो । ऐसा होने से सरकार के काम में ऐफिशिएन्सी बढ़ेगी और गांवों में जो पार्टीबाजी होती है वह भी न होगी । मेरे अपने हल्के में गंगाना,

बुटाना, बड़ौदा गांव हैं जहां पर पटवारखाने की बड़ी आवश्यकता है । ये बहुत बड़े बड़े गांव हैं । कई बार तो पटवारी गांवों में एक एक हफ्ते नहीं आता है, कहीं शहर में ही बैठा रहता है । अगर उसका अपना दफ्तर होगा तो वहीं पर आकर बैठेगा । इसलिए इन तीन गांवों में पटवारखाने अवश्य खोले जाने चाहिएं ।

डिमांड नम्बर आठ बिल्डिग्ज एण्ड रोडज के बारे में है । हरियाणा का हर गांव सड़क से जोड़ा गया है 'ले किन फिर भी कुछ नई सड़कें बनायी जानी जरूरी है । जब भी कोई मन्त्री किसी गांव में जाता है तो यह मांग की जाती है कि हमारी सड़क मंजूर की जाये । इसके अलावा बहुत सी सड़कें टूटी हुई हैं जिनकी मरम्मत होनी जरूरी है । मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि नई सड़क बनाने की बजाए पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाये । उन्होंने कहा है कि सड्कों की मरम्मत का काम तेजी से होना चाहिए और 31 मार्च से पहले होना चाहिए । बहुत सी सड़कें मेरे हल्के में ऐसी हैं जिनकी हालत बड़ी खस्ता है । श्री फूल चन्द मुलाना पिछले दिनों मेरे हल्के में गये थे । जहां जहां पर वे गये उन सभी सड्कों की मरम्मत हो गई । अगर ऐसे ही सड्कों की मरम्मत होती है तो पी ० डब्ल्यू ० डी ० मिनिस्टर साहब को हर जगह घूमा देते हें ताकि सभी सड़कों की मरम्मत 31 मार्च से पहले हो जाये । मेरे हल्के में मुडलाना से बसाना को सड़क जाती है, वह टूटी हुई है । मुडलाना के पास जोहड हे । वह सड़क वहां पर बिल्कुल कट गई है । इसी तरह ढुराना से

रिडाना तक भी सड़क खराब है और महमूदपुर से छतैरा को जो सड़क जाती है वह भी टूटी हुई है । मेरे अपने गांव जागसी के आगे जहां से जीन्द जिला एक किलोमीटर पर शुरू हो जाता है, वहां पर सड़क टूटी हुई है । इसी तरह से ढुराना से बाढोठी की सड़क की भी हालत काफी बुरी है । वहां पर मैंने खुद देखा है । मेरी अपनी गाड़ी रोडी लगने से पंक्चर हो गई थी । इसलिए इस सड़क की भी मरम्मत जल्द सेजल्द करायी जाये । मदीना से छिछडाना को जो सड़क जाती है वह भी टूटी हुई है । इसलिये उसकी भी मरम्मत करायी जाये । मुख्य मन्त्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि पहले टूटी हुई सड्कों की मरम्मत करायी जाय ।

इसके अलावा कई स्कूलों की बिल्डिग भी टूटी हुई हैं जिनका काम पी ० डब्ल्यू ० डी ० विभाग ने ले रखा है । ऐजूकेशन डिपार्टमैंट, पी ० डब्ल्यू ० डी ० से अपनी बिल्डिंग बनवाता है और उन्हीं से मरम्मत करवाता है । चौधरी फूल चन्द मुलाना साहब मेरे साथ भावड गांव में गये थे । वहां पर उन्होंने कमिटमैंट की थी कि स्कूल की बिल्डिंग का काम जल्द शुरू कर दिया जायेगा । ऐजूकेशन विभाग ने तीन लाख रुपया मंजूर कर दिया था और उसमें से आधा पैसा लग भी गया था लेकिन अभी वह काम अधूरा पड़ा हुआ है । मन्त्री महोदय हाउस में बैठे हुए हैं और वे वायदा भी करके आये थे कि काम शुरू कर दिया जायेगा परन्तु आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ । इसलिये मैं

निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्द से काम शुरू किया जाये । इसी प्रकार से मेरे अपने गांव जागसी में दो स्कूल हैं । एक लड़कियों का स्कूल है और एक लड़कों का स्कूल है । लडकों के हाई स्कूल को तो पी ० डब्ल्यू० डी० ने अपने अन्डर ले रखा है लेकिन लड़कियों के हाई स्कूल को अपने अन्डर नहीं ले रखा इसलिए इस स्कूल को भी पी ० डब्ल्यू० डी० अपने अन्डर ले ले ताकि उसकी भी मरम्मत हो सके । मेरा गांव आठ– दस हजार की आबादी का है । वहां काफी बच्चे पढ़ने वाले हैं इसलिए वहां की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए । मेरे अपने हल्के में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर सरकार को न तो कोई कम्पनसेशन देना पड़ता है और न ही कोई और बात है । वहां पर अर्थ वर्क हुआ पड़ा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे गांवों की सडक को प्रायरिटी बेसिज पर बनाना चाहिए । जैसे महमूदपुर गांव है, उस गांव वालों ने पानीपत रोड तक खुद मिट्टी डाली हुई है । इसलिए उस सड़क का बनना बड़ा जरूरी है । खानपुर गुरुकुल में लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, वे वहां से पैदल जाती हैं । इसी तरह से गढवाल से रिढाना को सड़क जाती है उस पर भी मिट्टी डाल रखी है । वहां पर कोई कम्पनसेशन वगैरह सरकार को नहीं देना है तो ऐसी सड़कों को सरकार को ले लेना चाहिए ।

स्पीकर साहब, डिमांड नं० 9 ऐजूकेशन से सम्बन्धित है । मैं इस बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि सरकार ऐजूकेशन पर बहुत पैसा खर्च कर रही है । इस

साल भी लड़कियों के करीब 100 प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है । 50 मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करेगी । इसके अलावा कुछ और स्कूल भी बनायेगी । स्पीकर साहब, इन सब के बावजूद बहुत से गांवों की मांग है कि वहां पर स्कूल या तो अपग्रेड किये जायें या नये स्कूल बनाये जायें । गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके बिल्डिग बना रखी है । आप जानते हैं कि गांव वाले या तो सांग करके पैसा इकट्ठा करते हैं या फिर घूम–घूम कर इकट्ठा करते हैं । कई जगह पर लाखों रुपया इकट्ठा करके स्कूल की बिल्डिग बना दी है । उनकी मांग यह है कि उनके स्कूल को अपग्रेड किया जाये । बहिन जी ने पिछले साल भी कहा था । मेरे यहां एक मदीना गांव है । वहां के लोगों ने 5–7 लाख रुपया खर्च करके 23 कमरे बहुत अच्छे बना रखे हैं । इनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर यह उसको अपग्रेड कर दें । इन्होंने पिछले साल इसके लिये यह कहा था कि अगले साल कर दौ' । मदीना गांव के पास ही एक गांव ठसका है वहां पर प्राइमरी स्कूल है । उसको हाई स्कूल अपग्रेड किया जाये । इसके अलावा गांव कोहला में प्राइमरी स्कूल है । उसको मिडल स्कूल अपग्रेड किया जाये । मेरेरू हल्के में गांव यगाना मे लड़कियो का एक मिडल स्कूल है । आप जानते हैं कि सरकार लड़कियों के स्कूलो को अपग्रेड करने के लिये ध्यान दे रही है क्योकि उनकी शिक्षा को प्रैफरैन्म भी दिया है । वहां पर बिल्डिग भी गांव वालों ने बना रखी है । तो मेरी माग यह है कि उसको अपग्रेड किया जाये । इसी तरह से मेरा अपना गांव है जहां पर दो हाई स्कूल हैं । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं

कि वहां पर कोई भी 10 प्लस 2 का स्कूल नहीं है । सरकार वहां पर ऐसा कोई स्कूल खोलने की बात कंसिडर करने की' कृपा करे ।

अब मैं डिमांड नं ० 10 जोकि मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ से सम्बन्धित है, के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार ने कई डिम्पैसरियों को अपग्रेड किया है । कई जगहे ऐसी हैं जहां पर डिस्पैसंरियां तो हैं, लेकिन वहां पर डाक्टर नही है । मिसाल के तौर पर बुटाना एक गांव हूँ । वहा पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अपग्रेड तो किया गया है लेकिन वहां पर कोई डाक्टर नही है । अगर डाक्टर ही नही होगा तो बीमार बेचारे कहां जायेंगे? इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि वहा पर डाक्टर अवश्य लगाया जाये । सरकार गे जो नये प्राइमरी हैल्थ मैटर्ज खोलने के लिये नीति बनाई है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह ठीक बात है कि 50 के करीब प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज सरकार बनायेगी लेकिन मैं चाहूंगा –कि उन गांवों में या उन एरियाज में ये ज्यादा बनाये जायें जहां पर फ्लड ज्यादा आते हों या बीमारी ज्यादा हों । उसके लिये सरकार ने एक क्राइटेरिया वना रखा है कि 3० हजार की पापुलेशन जहां पर होगी वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैटर बनायेगे । मेरा अपना गांव जागसी है । अगर वहा के आस पास के गांवों जैसे गंगोना, गंगेसर सिवाना माल और ऐचरा की आबादी को मिला लिया जाये तो पापुलेशन 30 हजार से भी ज्यादा बन जाती है । साथ में एक किलोमीटर दूरी पर जिला जींद पड़ता है ।

इसलिये उस एरिया में एक प्राइमरों हैल्थ सेंटर जरूर बनाया जाये । पिछली बार भी मैंने इस हाउस में कहा था । गंगाना गांव के लोगों ने एक रैजोल्यूशन भी पास करके सरकार के पास भेज रखा है । पिछली बार जवाब यह आया था कि सवाना माल गांव में कोई प्राइमरी हैल्थ सेंटर नही है वहां पर अवश्य ही एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाने की बात कंसिडर की जाये ।

इसी तरह से वाटर सप्लाई की बात भी है । यह अच्छी बात है कि सरकार सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधा देने की तजवीज बना रही है लेकिन जो मौजूदा वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, उनकी कोई सफाई नहीं होती । कई कई महीने तक ऐसे दी गन्दगी इकट्ठी पड़ी रहती है । उससे लोगों को पीलिया होगा या कोई और दूसरी बीमारी होगी । इसलिये सरकार को चाहिये कि जो वाटर सप्लाई स्कीमे आलरेडी बनी हुई हैं, कम से कम हर दूसरे महीने उनकी सफाई होनी चाहिये । पिछली बार – इसी हाउस में सैशन में यह सवाल आया था कि कई बार बिजली चली जाती है जिसकी वजह. से लोगों कौ काफी दिक्कत होती है । बिजली की सप्लाई के बारे में तो सरकार कोशिश कर रही है और पहले में इम्प्रूवमैंट है । लेकिन आज भी बिजली की काफी दिक्कत है । इसलिये मेरी मौत यह है कि वहा पर जनंरेटर्ज का प्रवन्ध किया जाने । मेरे हल्के में बड़ौदा हुक गांव है । पिछले दिनों मैं उस गांव में गया था । वहां जाकर मैंने यह देखा कि टूटियां तो लगी हुई हें लेकिन उनमें पानी नहीं आता । ऐसा इसलिये है

क्योंकि जो डिग्गी है, वह ऊंची होनी चाहिए जोकि ऊंची नहीं है । इस बारे में मेरी ऐक्सीयन साहब से बातचीत हुई । उन्होंने यह बताया कि हमने जो इस स्कीम का ऐस्टीमेट बनाया था, वह हमारे ऐस्टिमेट्स से आलरेडी बढ़ गया है । इसिलये हम इसको ऊंचा नहीं बना पाये । उन्होंने यह कहा कि हमारा ऐस्टिमेट्स 5 लाख रुपया एक्सीड कर गया । मेरा कहना यह है कि बेशक 10 लाख रुपया ज्यादा खर्च हो जाये, लेकिन डिग्गी तो ऊंची बनायी जाये और जनरेटर्ज का वहां पर इन्तजाम अवश्य होना चाहिए ।

स्पीकर साहब, डिमांड नं ० 13, जो सोशल वैल्फेयर की है, के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता ी । यह बात ठी?–।–' है कि सरकार ने गरीव वर्ग या समाज के कमजोर वर्ग की तरफ पूरा ध्यान दिया है । सोशल वैल्फेयर के नीचे आगनवाडिया भी आती है । वहां पर सी० डी ० पी ० ओ० बैठती है । वहां पर ये लोग क्या करते है ? न्यूट्रीशन स्कीम के तहत वाकली और पंजीरी वगैरा बच्चों में बांटते हैं । सरकार ने कई गांवो में ऐसे मैटर खोल रखे है । स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे सैटर्ज सभी ब्लौक्स में खोने । इनको यह भी चाहिये कि गांव में ऐसे सैटर्ज हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज के मोहल्लों में खोले होता क्या है ये किसी के घर में खोल देते है । उस घर का लड़की को एम्पलायमैंट दे देते है । दूसरी बात यह है कि वहां बच्चों को खुराक बांटने का सिस्टम भी ठीक नही है । वहां कोई नारा–तोल तो होता नही हए, वह मुट्ठी भर कर बच्चों को दे देते हैं । मेरा

कहना यह है कि बाटने का सिस्टम ठीक किया जाये । इसके अलावा स्पीकर साहब, सोशल वैल्फेयर में एक सुपरवाईजर की पोस्ट होता है । उसकी क्वाली– फिकेशन ऐसी है कि हरिजन लड़कियां उस क्वालीफिकेशन की मिलती नहीं हैं । उसके लिये क्वालीफिकेशन बी ० एस सी० होम साईन्स है और न्यूट्रीशन का उसमें सब्जैक्ट होना चाहिये । शड्यूल्ड कास्टस लड़कियां तो बी ० ए० भी नहीं मिलती हैं । बहिन जी कौ पता होगा कि 200 पोस्टें थीं, पता नहीं इनको पूरी लड़कियां मिली भी है या नही मिली हए । मैं तो यह चाहूंगा कि शड्यूल्ड कास्टस के लिये बी० एस सी० होम साईन्स की बजाये बी० ए० क्वालीफिकेशन कर दी जाये । न्यूट्रीशन सब्जैक्ट की बड़ी भारी जरूरत नहीं है । उसमें उन्होंने चावल ही तो पकाने हैं । उठा कर आग जला कर चावल में पानी डाल कर रख दें, थोड़ी देर में एक जायेंगे । मेरा कहना यह है कि आगे सुई इनके लिये क्वालीफिकेशन में रिलैक्सेशन होनी चाहिये । इसके बाद स्पीकर साहब डिमांड नं० 1 8, जो ऐनीमल हस्बैडंरी के बारे में है उसके बारे में भी मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा । पशुधन किसान का धन होता है । हमारे प्रदेश में 80 लाख के करीब गाय और भैसें हैं । अगर हम उनको ठीक ढंग से मैडिकल फैसिलिटी न दें या उनकी हैल्थ का ख्याल न रखें या उनकी पूरी तरह से देखभाल न करें तो पशु का कोई फायदा नहीं है । हर बार जब बरसात होती है तो पशु बीमार हो जाते हैं । अक्सर पशु को बरसात के मौसम में कोई न कोई बीमारी लग जाती है । डाक्टर तो 8– 10 किलोमीटर दूर से बुलाकर लाना

पड़ता है । पशु को इतनी दूर लेकर जाया भी नहीं जा सकता । इसलिये ऐनीमल्ज की रक्षा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जायें । मेरे हल्के बड़ौदा के एक गांव छतेरा में जोकि तहसील गोहाना में है, एक अस्पताल के लिये बिल्डिंग बनी हुई हे । उसकी महकमे के नाम रजिस्ट्री भी करा दी गयी है । मैं यह 'चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी अस्पताल खोला जाये ताकि वहां के पशुओं की हैल्थ का अच्छा प्रबन्ध हो सके । नेहरा साहा को मैं यदु भी कहना चाहूंगा कि बहुत थोड़े से पशु ही उनकी हैल्थ स्कीम के तहत कवर हो पाये हैं । उसमें परसैटेज बहुत कम है । हैल्थ स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा पशु कवर होने चाहियें और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम को बढ़ाया जाना चाहिये । इसके अलावा पशुओं के लिये पीने के पानी का भी मैं जिक्र करूंगा । इनके पीने के लिये जो जोहड होते हैं, वे इतने गन्दे होते हैं कि कई बीमारियां पशुओं को वहां से ही लग जाती हैं । मैं नेहरा साहब, जो यहां पर बैठे हैं, से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर कभी दवाई छिडकाने का इन्तजाम करते हैं? पानी एक बहुत जरूरी चीज है और नेहरा साहब पहले यह पता करके बतायें कि ऐसा कभी किया है या नहीं? पिछली बार मेरे हल्के के एक गांव भावड में 17 भैसे एक ही आदमी की मर गई थीं । हिसार से एक टीम इसका कारण जानने के लिए आई थी । उन्होंने कहा कि ये भैंसे जहर खाने से मरी हैं चाहे पानी के जरिये या चारे के जरिये भैसों के अन्दर जहर गया हो । इसलिये मेरा कहना यह है कि पशुओं की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए

और ऐनीमल हस्बैडंरी विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ।

स्पीकर साहब, सिंचाई की ओर हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि किसान के हरेक खेत को पानी मिलेगा । मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा है कि तीन महीने के अन्दर यानी 31 मार्च तक हर टेल तक पानी पहुंच जाएगा । टेल तक पानी पहुंचाने के लिये मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं । पिछले दिनों सुरजेवाला जी सोनीपत गए थे और उन्होंने लोगों से सिंचाई सम्बन्धी तकलीफों के बारे में पूछा था । वहां पर बड़ौदा, मदीना भडेरी तथा दूसरे गांवों के लोगों ने एक माइनर की मांग की थी । यह माइनर बुटाना डिस्ट्रीव्यूटरी से निकाली जानी है । वहां मौके पर चीफ इंजीनियर और दूसरे अफसरान मौजूद थे और मन्त्री महोदय ने इसका बनाना मान लिया था । यह बहुत अच्छी बात है । स्पीकर साहब, जहां तक लाइनिंग की बात है उसने कई बार ऐसा होता है कि लाइनिंग ठीक नहीं होती । उसका लैवल गल्त ले लिया जाता है । कोई बुर्जी ऊंची और कोई बुर्जी नीची उठा देते हैं । क् मन्त्री महोदय का ध्यान बड़ौदा माइनर की ओर दिलाना चाहता हू । उसका लैवल ठीक नहीं है । कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है । मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि उसका लैवल ठीक किया जाए जिससे कि टेल पर ठीक पानी पहुंच जाए । जहां तक फ्लड का ताल्लूक है कई ड्रैन्ज ऐसी हैं जैसे कि रिडाना गांव है वहां नहर जाती है और

उसके पैरेलल ड़ेन है । रिंडाना के पास नहर पर पुल है लेकिन ड्रेन के ऊपर पुल नहीं है । औरतें चारा लेकर जाती हैं तो उनको ड़ेन के अन्दर से पानी में से गुजरना पड़ता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ड्रेन पर भी पुल बनाया जाए जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो । स्पीकर साहब, एक कथूरा हैड है उसका उद्घाटन हुआ था । वहां पर ड्रेन के ऊपर एक रजबाहा है वह रजबाहा अधूरा पड़ा है । मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको जल्दी बनाने की कृपा की जाए । स्पीकर साहब, गोहाना शहर बीच में पड़ता है । अगर सोनीपत से आप आएं, रोहतक से आप आएं या पानीपत से आएं तो यह बीच में. पड़ता है और यह ड्रेन के साथ पड़ता है । बहुत अच्छा साइट है । वहां पर टूरिज्म का काम्पलैक्स बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए । मैंने ये कुछ मांगे सदन में रखी हैं आशा है सरकार इनको मानेगी । इतना ही कहकर, स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी अजमत खां (नूंह) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया । इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं । स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 3, 8, 9, 10, 15, 20 और 22 पर बोलना चाहता हूं । स्पीकर साहब, डिंमाड नम्बर 3 होम के बारे में है । इस मद में जो खर्चा किया जा रहा है वह जरूरी है और होना भी चाहिए लेकिन हमारी पुलिस का जो रवैया है वह अंग्रेजों के जमाने जैसा हैं । इसको सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए । देश आजाद है और यहां के शहरियों के साथ

आजाद देश की पुलिस की तरह सलूक किया जाना चाहिए । पुलिस के अन्दर सी० आई० डी० विजिलैन्स, सिक्योरिटी और पुलिस ये तीन चार विंग हैं लेकिन सी० आई० डी० और विजिलैस्स में पुलिस के लोग ही अफसर बना दिये जाते है, पुलिस का सिपाही विजिलैन्स में चला जाता है और उधर से इधर आ जाता हैं । मेरी प्रोपोजल है कि विजिलैन्स सी० आई० डी० और सिक्योरिटी और पुलिस के विंग अलग अलग होने चाहिए । इससे इनके काम में ऐफिशिएन्सी आएगी और जो आजकल पुलिस डिपार्टमैंट में करप्शन बढ़ रहा है वह भी काफी हद तक कम हो जाएगा ।

स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 8 बिल्डिग्ज तथा रोडज के बारे में है । सरकार इसको काफी अच्छी तरह से चना रही है । सड्कों की मरम्मत भी की जा रही है लेकिन जब हम हिसार की तरफ चलते हैं तो उधर जाते हुए हमें कुछ और महसूस होता है ?लेकिन दक्षिण की और चलते छंद तो मालूम होता है कि उधर पैमा कम लगा है । मैं चाहूंगा कि सड़क बनाने तथा मरम्मत पर जो भी सरकार खर्च करे वह उस पैसे को डिस्ट्रिक्टवाइज खर्च करे ताकि हर जगह यह महसूस हो कि सड्कों की मरम्मत हो रही है । स्पीकर साहब, मेरे यहां डिाकरावा गांव में ड्रेन पर पुल है । इममें गठ्ढे पड़े हुए हैं । पी ० डब्ल्यू० डी ० अफसरान को जब कहा जाता है तो वे कहते हैं कि इरीगेशन वाले इसको ठीक करेंगे । गांव के चारों तरफ सड़क की बहुत ही बुरी हालत है । छोटी

गाड़ी भी वहां से नही निकल सकती । पी ० डब्ल्यू० डी ० वाले कहते हैं कि हम तो इस पुल पर मिट्टी भी नहीं डाल सकते । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मरम्मत की जानी हैं या नई बनाई जानी हैं और वे हैं – गुलालता से सीरोली, नूह–नगीना वाया करहेडा– घाघस । करहेडा से भादस । शाह चौखा मजार की सड़क नामुक्म्मल है । आगरा कैनाल की माइनर मानापुर के ऊपर से आलीमेव कौ सड़क जाती है जिस पर पुल नही है और सड़क बनकर भी खराब हो चुकी है । इस पुल को बनाया जाए और सड़क की मरम्मत की जाए । इसी प्रकार मलाई से अलावलपुर रोड की मरम्मत की जाए । एक नई सड़क सापलकी से हथीन बनाई जाए । सांपलकी से यदि हथीन को जाया जाए, जोकि सांपलकी का तहसील, थाना और ब्लौक हैडर्क्याटर है तो अठारह किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है । इसी तरह से मोहदमका से हथीन डेढ़ किलोमीटर है लेकिन चक्कर काटकर नौ–दस किलोमीटर आना पड़ता है । एक सड़क मोहदमका से गुराकसर बननी है और यह सिर्फ आधा किलोमीटर है । रनयाला पटाकपर से धाडौली डेढ किलोमीटर है । इसको बनाने से पिनंगवा और नगीना जाने के लिये लगभग पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर बचेगा । त्रक सड़क घासेडा गांव सैं घग्सेड़ा पी० एच० सी ० जाने के लिए बनाई जाए । यह पी ० एच० सी० घासेडा गांव से एक या डेढ़ किलोमीटर है । पक्की सड़क से पी ० एच० सी ० आने केलिए पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है । इसी

तरह से जरगाली से गूजर नगला नाई नगला से बसई वगैरह – की सड़कें हैं जिनका बनाना बहुत जरूरी है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक सड़क शेखपुर से मेवली है जिसको बनाने से लोगों को बहुत फायदा होगा । डिप्टी स्पीकर साहब, मेवात एरिया में अगर बीस–पच्चीस किलोमीटर सड़क पक्की बना दी जाए तो लोग हजारों किलोमीटर का चक्कर काटने से बच जाएगें इसी तरह से नगीना से साढावाडी–नांगल की सड़क का बनाना बहुत जरूरी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, आलामेव के स्कूल की छत करीब पांच–सात साल से पी० डब्ल्यू० डी ० वालों ने तोड़ कर डाली हुई है और अब तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है । पी ० डब्ल्यू० डी ० वाले पैसा लेकर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते । जो पैसा डिपार्टमैंट वाले लेते हैं उसकों किसी दूसरे काम में लगा देते हैं और जिस काम के लिये पैसा लेते हैं उसको पीछे डाल देते हैं । मेरी सरकार से दरख्वास्त है .कि ऐसी विल्डिग्ज जिनमे बच्चे बैठते हैं उनकी मरम्मत के लिये पैसा खर्च करना चाहिए । डिग्री स्पीकर साहब, पी ० डब्ल्यू०डी ० वाले जिस काम के लिए पैसा लें वह पहले उमी काम पर खर्च होन? चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि पैसा लेकर अपने पाम राड छोडे या दूसरे काम पर खर्च कर दें । डिप्टी स्पीकर साहब, सारे मेवात में भड्को की. हालत बहुत खराब है । मेवात क्षेव की चारों कांस्टिचुगंसीज में मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर्ज की सड़कें रहती होंगी लेकिन उन के वनने से

यदि हिसाब लगाया जाए तो हजारों किलोमीटर्ज का फासला कम हो जाएगा । इन गावों में अक्सर यह देखने में आया है कि यहां से अगर किसी मरीज को हस्पताल ले जाना हो तो हस्पताल तक पहुंचाने के लिये कोई साधन नहीं है, कोई सड़कें नही है । जितनी देर में मरीज हस्पताल में पहुंचेगा उतनी देर में हो सकता है कि वह मर भी जाए । इतना लम्बा चक्कर काट कर जाना पड़ता है । अगर जो–जो सड़कें मैंने बताई हैं उन्हें बना दिया जाए तो लोगों को आने जाने में बड़ी सहुलियत होगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुकेशन के बारे में भी कुछ कहूंगा । रिकार्ड से पता चला है कि हरियाणा के अन्दर 1632 हाई स्कूल्ज हैं । मेवात की चार कास्टिचुएंसीज में कुल 40 स्कूल्ज हैं और केवल 2 हायर सैकेण्डरी स्कूल्ज हैं । इसका मुझे बेहद अफसोस है । इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं? मैं यह कहना चाहता हू कि जहां और जगह हर साल एक एक ब्लाक में 12–12 स्कूल्ज अप–ग्रेड कर दिये जाते हैं तो उसी तरह से हमारे इस पिछड़े हुए इलाके में भी स्कूलों को अप–ग्रेड क्यों न किया जाए? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं टेक्निकल कालेज के बारे में भी कुछ कहूंगा । हमारे इलाका उत्तावड में एक पोलिटैक्निक कालेज मजूंर हुआ था । सरकार ने स्टेट में पोलिटैक्निक कालेजों पर कुल 4–5 करोड़ रुपया खर्च किया है । हमारा इलाका पिछडा हुआ इलाका है । दूसरे इलाकों में हर – जगह लोगों को तालीम दी जा ' रही है । कहीं ऐहहईाकलचर यूनिवर्सिटी है, कहीं मैडिकल

कालेज है, कहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन मेवात में केवल एक टैक्तिकल कालेज की मांग थी और अच्छा होता अगर दूसरे स्थानों के साथ साथ इसको भी ध्यान में रख लिया होता क्योंकि यह आलरेडी मन्जूर हो चुका है । साबका मुख्यमन्त्री जी ने 11 जून को यह प्रोग्राम बनाया था कि इसको स्टार्ट करवा दिया जाएगा लेकिन वे सैन्टर में चले गये और यह काम वहीं का वहीं रह गया । कम से कम यदि इस को इस प्लान में ले लेते तो इस कालेज का काम शुरू हो जाता और इससे मेवात के लोग यह सोचते कि सरकार हमारे इलाके की खुशहाली के लिये ऐजुकेशन की ओर ध्यान दे रही है । मैं चाहूंगा कि जो मेवात की प्रगति के लिये फण्डज रखे गये हैं उसमें से कम से कम 10–20 लाख रुपया उस काम को शुरू करवाने के लिये रख देते । हमारा ही पैसा है, उधर से हटा कर इधर लगा देते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी । इससे लोगों को सहूलियत मिल जाती ।

इसी तरह से मैं मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में भी जिकर करना चाहता हूं । शहरों में कुछेक हस्पताल हैं लेकिन वे हस्पताल अभी देहातों में नहीं पहुंचे । देहाती इन फैसिलिटीज से बिल्कुल वंचित हैं । सरकार की स्कीम है कि कम से कम 3० हजार की आबादी के पीछे एक प्राइमरी हैन्थ सैन्टर बनाया जाए । इसलिये मैं चाहूंगा कि पिंगवा, आकेडा वाजीतपुर, उतावड और आलीमेव, इन पांच जगहों –पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज वनाए जाएं ।

इससे आगे मैं यह कहना चाहता हू कि मेवात के इलाके में गुड़गांव कैनाल जाती है । उस नहर को एस० वाई० एल० से पानी देने के लिये एक स्कीम है जिसको मेवात प्रोजैक्ट का नाम देते हैं । शायद अभी वह कागजों में ही है । जिस वक्त एस० वाई० एल० नहर का पानी हरियाणा में आएगा उस वक्त इसमें पानी दिया जाएगा । फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि झज्जर लिपट इरीगेशन स्कीम के लिए भी एक पैसा बजट में नहीं रखा गया है लेकिन इस किस्म की जितनी भी दूसरी स्कीमज हैं, जैसे जुई, जे० एल० एन०, वैस्टर्न यमुना और लोहारु कैनाल्ज वगैरह, इन सब के लिये बजट में प्रोविजन है इनके लिए अलग से पैसा रखा गया है झज्जर हमारी तरह डैजर्ट इलाका है । वहां की लिपट स्कीम के लिये इसमें कोई पैसा नहीं है और इसी तरह से प्रोजैक्ट का भी कहीं नामोनिशान नहीं है । जब एस० वाई० एल० नहर हरियाणा में आएगी तो उसका पानी ही मेवात के एरिया में दिया जाएगा । उस नहर को मेवात के इलाके में बनाने के लिये भी टाईम चाहिये । पहले जमीन ऐक्यायर होगी फिर उसकी डिमार्केशन होगी । इस काम को लगभग पांच–छः साल लग जाएंगे । इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इलाके की पैदावार हरियाणा के दूसरे इलाकों के लोगों से पिछड़ जाएगी । पिछड़े हुए तो हम पहले से ही हैं लेकिन इस मसें में और ज्यादा पिछड़ जाएंगे । डिप्टी स्पीकर साहव, ब्रा करोड़ रुपये की राशि बजट में से सिर्फ कैनाल की मरम्मत के लिये रखी गयी है । मैं चाहूगा कि सरकार इस मेवात कैनाल के काम को अपने हाथ में ले और इस

के लिये ज्यादा फण्डज को प्रावधान करे क्योंकि मैंने पहेले भी कहा था कि अगर हरियाणी का एक हिस्सा तरक्की नहीं करेगा तो इससे हरियाणा की ही छवि गिरेगी । हमारा यह इलाका दिल्ली के नजदीक पड़ता है, इसलिए इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । जब हम अम्बाला से गुजरते हैं तो हमारा हरियाणा प्रदेश लहलहाता हुआ नजर आता है और जब हमारे इलाके की तरफ अति हें तो देखने पर मन! बहुत दुखी होता है । हम तो केवल किस्मत के सहारे और कुदरत के बलबूते पर ही गुजारा कर रहे है अगर यही हाल रहा तो हरियाणा के ऊपर यह एक बदनुमा धब्वा होगा और हरियाणा की छवि बिगड़ेगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं पशुओं की डिस्पैन्यरिया खोलने के बारे में भी कहना चाहता हूं । राज्य सरकार का 1987–88 के दौरान 30 पशु चिकित्सालयों का दर्जा बढ़ाकर पूरे हस्पताल बनाने का विचार है । मैं चाहूंगा कि नूह और फिरोजपुर झिरका में जिस तरह से सरकार ने 1987–88 में दो डिस्पैन्सरियों के लिए पैसा मन्जूर किया है उसी तरह से ताउडू वगैरह और दूसरे मेवात के इलाकों में भी पशु डिस्पैन्सरियां खोलने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहब अगर अब तक ऐसा सरकार नहीं कर पायी है तो कम से कम अब तो एक दो और पशु–डिस्पैन्सरियां हमारे मेवात के इलाके में खोलने का प्रबन्ध किया जाए ताकि मेवात के लोग अपने पशु धन की रक्षा कर सकें । मेवात में फ्लडज भी आते हैं, सूखा भी पड़ता है

जिससे बीमारी पैदा होती है और पशु मरते हैं । मेवात के लोग इससे और गरीब हो जाते हैं । पशु धन ही मेवात के लोगों का असली धन है । खेती के बाद वहां के लोगों का एक यही धन गुजारे का साधन होता है । लोग अपने पशुओं का दूध बेच–बेच कर गुजारा करते हैं । बीमारी की वजह से हमारी भैसे रोजाना मरती रहती हैं और बीमारी भो बढ्ती जाती है । इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इन स्टाक मैन सैन्टर्ज की संख्या बढ़ाकर हरेक इलाके में, जैसे फिरोजपुर झिरका, नूंह वगैरह में दो दो और देकर इनकी संख्या 8 कर दी जाए । आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

इसी तरह से रूरल डिवैल्पमैंट की बात है । पिछले साल एन० आर० ई० पी० तथा आर० एन० ई० जी० पी० स्कीमों के अन्तर्गत सरकार ने 28 लाख श्रम दिनों का काम पैदा किया है और इस साल केवल 21 लाख श्रम दिनों का काम पैदा किया हए । मेरा कहने का मतलब यह है कि डिवैल्पमैंट आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं हटती परन्तु 1987–88 के बजट में इसके लिये 14 करोड़ से घटा कर 13 करोड़ रुपया रखा गया है । इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि सरकार को इस तरफ से किसी किस्म की कट नहीं लगानी चाहिये । अगर रूरल डिवैल्पमैंट नहीं होगी तो देहातों की तरक्की नही होगी, अगर गांव खुशहाल नहीं होंगे तो शहर चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों न दिखायी दें उनकी आमदनी घटेगी । शहरों की आमदनी घटेगी तो भारत की तरक्की नहीं

होगी । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार रूरल डिवैल्पमैंट की ओर सब से ज्यादा ध्यान दे ।

एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी ० पी० स्कीमों को लाकर केवल हम 300 या 400 दिनों का ही लोगों को रोजगार दिला पाए हैं, यह बड़े ही शर्म की बात है । हमें तो हर गांव में कम से कम इतना काम आरम्भ करना चाहिये ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मित्र सके । जंमें सूरत्रा पीडित इलाके है उनमें राहत कार्य शुरू करवाये जा सकते थे । जौहड खुदवाकर जा सकते थे परन्तु इनकी बजाये हुआ क्या कि तकावी दी गयी । कई जगहों पर 800 रु०, कई जगहों पर 400 रु०, कई. जगहों पर अढ़ाई सौ रु० के लगभग एक ब्लाक के अन्दर दिये गये हैं और अब तो अढ़ाई सौ सैं भी कम करके 200 रु० और किसी गांव में 100 रु० दिये गए । अब उस को भी घटा कर 5० रु० तक ले आए हैं । सरकार को कम से कम एक ही नीति के अनुसार तकावी का वितरण करना चाहिये थन । अब यह भी देखने वाली बात है कि कितनों को ज्यादा पैसा मित्रा है और कितनों को कम मिला है । जिनका पटवारी दोस्त था और जो गांव पहले ही खुशहाल थे, उन को तकावी भी ज्यादा दी गयी। हथीन से लेकर उतावड तक, मोहने से लेकर ताउडू तक, ताउडू से लेकर बडखली तक डग मारे इलाके के लोंगों को अभी तक तकावी नही मिली ई और हथीन में भी नहीं मिली । ताउडू में अगर किसी गांव मे मिली भी है नो वह भी अढ़ाई सो रुपये । तो आप ही देखिये कि

यह क्या तकावी है जबकि किसान को भूसा कम से कम दम गुना चाहिये क्योंकि किसान के पास तीन चार डंगर भी होते है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में तो यूक ही बात कही– जा सकती है कि जितनी भी– ज्यादा से ज्यादा पुरानी बसें है, वे इधर के एरियाज में राखी गई है ।

11.00 बजे ।

आपने देखा होगा कि नई बसे भी चली है लेकिन आली जैसा गांव, जो मेवात के बडे गावो में से एक है, वहां भी कोई बम नही ठहरती । सिवाए एक दो गावों के और कही बस नहीं ठहरती । आलीपूर गांव बहुत दूर है । अलाल पुर और कैराका गांवों में बस ठहरती है लेकिन आगे गुडगाव जाती हूँ । कुछ गांवों से जैसे मेरा अपना गांव है, अगर गै सुबह –चलना शुरु करु तो यहा शाम को पांच बजे से पहले नहीं पहुंच सकता । मैं चाहता हूं कि कम से कम गांवों में तो ऐ सी सर्विस हो जो डायरैक्ट बड़े गांवों से जोड़ता हो । मेरा अपना गांव मलाई है दूसरी तरफ हालीडे एं और सरौली गाव है । ये फरीदाबाद और गुडगांव से कनक्टिड हों ताकि लोग तारीख पड़ने पर रात की बजाय सुबह चल कर वहा पहुंच सवों । कोआप्रेशन के बारे में मैं तो यही कह सकता हू कि लोन की वसूली प्रौपेगन्डा का शिकार है । सरकार ने कहा है कि वह लोगों को 239 कंरोड रुपया लोन देगी । बैंक तो साइकलिंग है यदि लोगों से वसूली का पैसा

आएगा तो 239 करोड़ रुपया आएगा । मौजूदा हालत में रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि एक तरफ तो इलैक्शन सिर पर हैं, दूसरी तरफ प्रोपेगन्डा है और तीसरी तरफ प्रदेश की हालत क्या हैं । तो 239 करोड़ रुपया कहा से दिया जाएगा (ई जिन लोगो की तरफ पहले ही कर्जा ओवर डयू है जव तक वह क्लीयर नही होता तब तक किसी आदमी को लोन नही मिल सकता । अगर कोई आदमी ओवर डयू लोन करीयर न करे तो न तो उसको ग्रामीण बैकों से लोन मिलता है और न ही और दसरे बैको से मिलता है क्योंकि वे क्लीयरैस का सर्टीफिकेट मांगते है । आज की हालत में किसान ओवर डयू लोन क्लीयर नही कर सकता । इसका मतलब यह है कि 239 करोड़ रुपया किसान को नही मिलेगा । अगर सरकार चाहती है कि इन किसानो को पैसा दिया जार' तो किसान को बगैर ओवर डयू लोन क्लीयर किए दुसरे बैंकों मे कर्जा लेने की इजाजत होनी चाहिए । इनके लिए यह रुकावट न हो कि वे सोसाइटियों से लिखा कर 'लाए कि उनके नाम ओवर डयू कर्जा तो नहीं है । ओवर डयू लोन की कंडीशन की सूरत में किसान को आगे लोन नही मिलेगा । इसी वजह सैं आज किसान के तकरीबन सभी लोन बन्द हो चुके हैं । पी ० एल० डी०बी ० के 70 करोड़ रुपए के कर्जे की रिकवरी का टारगेट बनाया गया है । पी० एल० डी० बी ० की आज यह पोजिशन है कि उनके पास किसानों के 80 लाख रुपए के परनोट पड़े हैं जिनके बैक ड्राफ्ट नहीं दियु जा सकते क्योंकि रिकवरी आई नहीं और बैक से आगे पैसा देने का इन्तजाम नही हुआ । ये नवार्ड वे भी पैसा नही ले सके ।

आज की पोजिशन यह है कि किसान को पैसे की जरूरत है और उधर 70 करोड' रुपए की रिकवरी का टारगैट रखा हुआ है । किसान उस हालत में 70 करोड़ रुपया वापिस कर सकता है जब इसके लिए नई स्कीमें आएगी । कुछ स्कीमें तो बिल्कुल पीक पर या टीप पर पहुच चुकी है इन स्कीमों को आप और कहां तक आगे बढ़ाएंगे नई स्कीमें हमें ढूढनी पड़ेगा । अगर किसान की डिवैल्पमैंट करनी है तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा सबसिडी भी देनी पडेगी । मैं एक और बात जनाब की खिदमत में पेश करुं कि एक आदमी खाद के लिए लोन लेता है या तकावी लेता है तो उसे सबसिडी दी जाती है । वही आदमी अगर सोसाइटी से कर्जा ले तो उसे कोई सबसिडी नही दी जति। मै चाहता हू कि जैसे खाद पर सबसिडी दी जाती है उसी तरह से सोसाइटी के कर्जे पर भी सबसिडी दी जाए । अगर सरकार चाहती है कि किसान इस कर्जे से बाहर निकले तो जो भी सोसाइटी के या मिनि बैक्स के कर्जे हैं उन पर भी सबसिडी दी जाए । जव बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज वालों को भी 15 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है तो किसान के लिए कम से कम हम यह कर सकते हैं कि उससे इस साल का व्याज न लिया जाए । वैसे तो व्याज की दर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक असल रकम से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन फिर भी कम से कम इस व्याज को सरकार किसान को सबसिडी के रूप में दे । यह कर दिया जाए कि कर्जे का व्याज सरकार देगी और असल रकम किसान देगा । इस तरह से बैंकों की सरकुलेशन हो

जाएगी और हमारा असल पैसा वापिस हो जाएगा । ऐसा करने से सरकार किसान की भी मदद कर सकेगी । धन्यवाद ।

मास्टर राम सिंह (रादौर–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं डिमांड नं० 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 23, और 25 पर बोलूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के रादौर जिला कुरुक्षेत्र में हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा उपजाऊ भूमि है लेकिन वहां पर जितनी सहूलियतें होनी चाहिएं उतनी नहीं मिल रही हैं । मेरे हल्के में किसानों को अपना अनाज मंडियों तक ले जाने के लिए काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है । अगर डेढ़–डेढ़ और दो–दो किलोमीटर सड़कों के टुकड़े बन जाएं तो लोगों की दिक्कत दूर हो सकती है । मैं वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे. हमारी दिक्कतें नोट करके पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर को बताएं । एक सड़क बेरथली से बुहावी की है जोकि बहुत जरूरी है । यहां से शूगर मिल शाहबाद सिर्फ एक किलोमीटर है । अगर यह सड़क बन जाए तो 20 किलोमीटर का चक्कर बच सकता है । दूसरी सड़क अलाहर से जयपुर की है । यहां से यमुना नगर सिर्फ 6 किलोमीटर पड़ता हे । इस सड़क के न बनने के कारण लोगों को यमुना नगर जाने के लिये 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है । एक सड़क धिलौड से हडतन की है । यह दो किलोमीटर लम्बी है और बहुत जरूरी सड़क है । एक सड़क कंजू से अलाहर की है जोकि डेढ़ किलोमीटर की लम्बाई की है ।

इसके न बनने से 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है । एके सड़क छाहर पुर से मुकर पुर की है । इसके न बनने से लोगों को 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है जबकि यह केवल एक किलोमीटर बननी है । एक सडक हिरंचापुर से वीर वरटोटी गंगोली की है जौ कि बहुत जरूरी है । यहां से कुरुक्षेत्र जाने के लिए सिर्फ 5–6 किलोमीटर का रास्ता है जबकि इसके न बनने से 15– 16 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है । इस सड़क की लम्बाई केवल डेढ़ किलोमीटर है । एक सड़क राम नगर से फरदालपुर की है जोकि एक किलोमीटर लम्बी है । एक सड़क टाटका से वरघट की है यह भी एक किलोमीटर लम्बी है । एक सड़क गुमथला राव से खुखनी तक है । यह भी एक किलोमीटर लम्बी है । अगली सड़क बस स्टैन्ड रादौर से रादौर टाउन की है । यह सिर्फ एक फर्लाग की है । इसी तरह से बस स्टैन्ड रादौर से हरिजन बस्ती तक एक और सडक है यह भी एक फर्लाग का टुकड़ा है । बारिश के दिनों में ये सड़कें न होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है । एक सड़क प्राइमरी हैल्थ सैन्टर रादौर से कैनाल रैस्ट हाउस तक की है । क्योंकि वहां का बाजार बहुत तंग है इसलिये वहां से दो टूक या गाड़ियां साथ साथ नहीं गुजर सकतीं । यदि यह सड़क बना दी जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो सकती है । एक सड़क जठलाना से बाजार तक आधी पक्की करनी बाकी रहती है । वह भी पक्की कर दी जाए । मेरे हल्के में तीन चार गांव ऐसे हैं जहां सड़क है ही नहीं और उनकी आबादी 500 से ज्यादा है । यह सड़क है पोटली से बस्ती

पुरबिया । यह आधा किलोमीटर की सड़क है । दूसरी सड़क है बबैन से बरगत । बरगत की आबादी 400 से ज्यादा है लेकिन कोई सड़क नहीं है । अगली सड़क है टाटका से टाटकी जोकि एक फर्लांग की है । यहां की आबादी 500 से अधिक है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इन गांवों में चूंकि कोई सडक नहीं है इसलिये वहां पर सड्कों का होना आवश्यक है । इसके अलावा संगीपुर में पुल तो बन चुका है लेकिन सड़क नहीं है । इसी तरह से कलेसरा में पुल है लेकिन सड़क नहीं है । मेरे हल्के में कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जिनकी रिपेयर भी बहुत जरूरी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के के अन्दर एक गांव खुर्दबन है । वहां पर एक हाई स्कूल बना हुआ है । उस स्कूल की हालत बहुत ही खराब है । आप ये समझिए कि उस स्कूल की बिल्डिग कच्ची बिल्डिग से भी गई–गुजरी हो चुकी हे । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस स्कूल की बिल्डिग की रिपेयर जल्दी से जल्दी करवाई जाये । अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । मेरे हल्के के रादौर शहर के अन्दर आज से 20 साल पहले एक ट्यूववैल लगा था । उसके बाद से आज तक वहां की आबादी तो तीन गुणा बढ़ चुकी है जबकि ट्यूबवैल एक ही चला आ रहा है । इस बारे में मैं चाहूंगा कि वहां पर इस ट्यूबवैल के अलावा एक और ट्यूबवैल लगाया जाये ताकि वहां की जनता को पीने का पानी बगैर किसी दिक्कत के मिल सके । इसी प्रकार से मेरे हल्के के अन्दर एक गांव कालवा है ।

वहां के हैण्ड पम्पों ने काम करना बन्द कर दिया है और टूसरे कुओं से भी पानी नहीं मिल रहा । अब वहां के लोग ट्यूबवैलों से ही पीने का पानी भर कर लाते हैं । वे भी तब लाते हैं जब बिजली आई हुई हो । जब बिजली नहीं आती तो उस गांव के लोग पीने के पानी के लिये बहुत परेशान हो जाते हैं । मैं चाहूंगा कि उस गांव की समस्या को दूर करने के लिए वहां पर एक वाटर वर्कस बनाया जाये । इसी प्रकार से एक वाटर वर्कस संगोहरा गांव के अन्दर भी बनाया जाये क्योंकि वहां के आसपास के गांवों का पानी का लैवल भी नीचे जा चुका है । संगोहरा में वाटर वर्कस लगाये जाने से 5–6 गांवों को फायदा पहुंच सकता है । इन गांवों में लगे हुए हैण्ड पम्पों ने भी काम करना बन्द कर दिया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे ताकि उन लोगों को पानी की कठिनाई से बचाया जा सके । इसके अलावा मेरे हल्के के जिन– जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, वे हैं, रादौर, कालवा, संघोर, भोगपुर, गुड्डा, जमालपुर, बापा, बुहावी, महावाखेडी, करल माजरा, कासीथल, राजेहडी, बरेहडी और बन्दी । डिप्टी स्पीकर साहब, इन सभी गांवों में पीने के पानी की बहुत समस्या है । मैं आपके जरिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट पीने के पानी के टयूबवैल्ज आदि लगा कर कोई न कोई प्रबन्ध जल्दी से जल्दी अवश्य करे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कुरक्षेत्र से यमुनानगर जो रोड जाता है उस पर जो पुल पड़ता है, वह कम चौड़ा है । इसी प्रकार से लाडवा से शाहबाद वाया वबैन रोड पर जो पुल पड़ता है, उसको भी चौड़ा किया जाये । रादौर से यमुनानगर की तरफ जाते समय रास्ते में जो पु पडता है वह भी काफी तंग है । इन सभी पुलों की चौड़ाई इतनी भी नहीं है कि इन पर आमने–सामने मे आने वाली गाडियां गुजर सकें । यदि इन पुलों पर से कोई गन्ने का ट्रक गुजर रहा हो और वह उस पुल पर खराब हो जाये या उल्ट जाये तो सारा रास्ता बन्द हो जाता है । दूसरे ये पुल वैसे भी बहुत पुराने हो चुके है । इनके गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है । मैं सरकार से प्रार्थना करता हू कि इन सभी पुलों को चौड़ा किया जाये और इनको नए सिरे से बनाया जाये ताकि ऐक्सीडैन्टस होने से बच सकें । इसी प्रकार से मेरे हल्के में तीन–चार पुल नए बनाये जाने बहुत जरूरी है । ये तीन पुल है वबैन–बरगत रोड से बरगत, छारी से छारी, माजरा से झागूरी नग्गल रोड । बबैन के अन्दर मण्डी भी बन चुकी है और वहां पर हैल्थ सैन्टर भी बन चुका है । इस बारे मैं मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिस प्रकार से करनाल से लाडवा डबल रोड है, उसी प्रकार से शाहबाद–लाडवा वाया बबैन रोड को भी चौड़ा किया जाये । यह रोड मिगल होने की वजह से ट्रैफिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है । इन सभी रोडज और पुलों के बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सभी को चौड़ा किया जाये और जहां

पर नए पुल या नई सड़कें बनायी जाने की आवश्यकता हो, वहां पर नए पुल और नई सड़कें बनाई जायें ।

अब मै डिमाड नं० 9 पर बोलना चाहता हूं । मेरे हल्के के कई स्कूल ऐसे हे जिन्हें प्राइमरी से मिडिल स्कूल और मिडिल सें हाई स्कूल अपग्रेड किया जाना है । गरीब लोग और हरिजन बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर के स्कूलों में भेजने में असमर्थ होते हैं । इसलिये उनके बच्चे 5 वी कक्षा से आगे नही पढ़ पाते । वे बच्चो को आगे तक न पढ़ाने में कुछ हद तक आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करतें हैं । उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने बच्चे। को दूर पढ्ने के लिए भेज सकें । मेरे हल्के में जो स्कूल मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड होने हैं वे इस प्रकार हैं –गवर्नमैंट मिडिल स्कूल सन्धाली और टाटका जो प्राइमरी से मिडिल तक अपग्रेड होने हैं, वे हैं–बैन्दी, बरथला, कलाल माजरा, बापा और बकाना ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मै डिमाड नं० 10 पर बोलना चाहता हू । हमारे खादर के एरिया में चिकित्सा की उतनी सुविधाएं उपलबध नहीं हैं जितनी. होनी चाहिएं । खादर एरिया की आबादी 40– 50 हजार के आसपास है । मेरे हल्के के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए दूर के हस्पताल में जाना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें बड़ी भारी दिक्कत. होत है । उन लोगों की सुविधा के लिए मै चाहूंगा कि खादर के एरिया में बरेहडी गांव में एक पी ० एच ० सी ० खोली जाये । रादौर के अन्दर श्री

मुकंद लाल जी नें 50 लाख रुपये की लागत से एक होम्योपैथी कालेज की बिल्डिंग बताई है । इसके बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस होम्योपैथी कालेज को चालू करवाने में सरकार को अपनी तरफ से ग्रान्ट भी दे नी चाहिए बगैर जल्दी मे जल्दी भारत सरकार से इस कालेज को चालू करवाने की मन्जूरी दिलवाई जाये । सारे हरियाणा में केवल यही एक होम्योपैथी का कालेज होगा । इस कालेज की बल्डिग का उदघाटन पहरने चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल जी ने किया था । मैं सरकार से इसके लए पुनः अनुरोध करता हू कि इसके लिये पैसे की सहायता सरकार दे और भारत सरकार से मंजूरी जल्दी से जल्दी दिलवाई जाये ताकि लोगो को इस कालेज का लाभ पहुंच सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, रादौर मे जे पी ० एच ० सी ० है । उसमें कोई लेडी डाक्टर नहीं है । इस बारे में मेरई सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जल्दी से जल्दी एक लेडी ड़ाक्टर भिजवाई जाये ताकि वहां की लेडीज अपना इल अच्छी प्रकार से करवा सकें । कई लेडीज जैन्टस डाक्टर से अपना ईलाज करवाना उचित नही समझतीं इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देते हुए वहां पर एक लेडी डाक्टर नियुक्त करनी चाहिए ।

अब मैं डिमांड नं ० 13 पर बोलना चाहत हू । सरकार ने ही रजनों की चौपालों के लिए काफी ग्रांट दी है । इस समय भी काफी चौ पाले नई बनाई जा रही हैं । मेरे हल्के की कई चौपालों का काम अधूरा पड़ा हुआ है । जो चौ पाले अधूरी पडी

हुई हैं! उनको जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाये । इसके अतिरिक्त जिन गांवों में 30 – 40 ही रजनों के परिवार रहते हैं और वहां पर ही रजनों की चौपालें अभी तक बनाई नहीं गई हैं । वहां हरिजन चौपालें बनाई जाएं । जिन गांवों में ही रजन चौपाले बनाई जानी हैं वे हैं – भोगपुर, गुमथला, इसमाईलपुर, खजूरी, महावार खे डी, मारुपुर । धोलडा, मुकपुर, बोडला और चारी माजरा । मेरा सरकार से अनुरोध है क इन सभी गांवों में जल्दी से जल्दी हरिजन चौपालें बनायी जानी चाहिएं । डिप्टी स्पीकर साहब, जिन हरिजन परिवारों के परिवार बड़े हैं । उनको रहने के लिए रैजिडैंशियल, प्लाटस दिए जाने चाहिएं क्योंकि इस समय जिस मकान में वे रहते हैं, वे एक तो कच्चे हैं और दूसरे इतने छोटे छोटे हैं कि उनका उन मकानों में रहना बहुत हइ मुश्किल बना हुआ है । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरिजनों के ऐं से परिवारों को गांव मैं छोटे – छोटे वाडे (प्लाटस) एलाट किए जाएं ताकि वे अपनी जिन्दगी को अच्छी प्रकार से गुजार सकें ।

अब मैं डिमांड नं ० 15 पर बोलना चाहता हूं । मेरे हल्के के अन्दर वाटर लैवल बहुत नीचे जा चुका है । वहां पर इरीगेशन तो क्या लोगों को पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा है । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस एरिया की दादुपुर नलवी कैनाल को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये ताकि वहां का वाटर लैवल ऊपर उठ सके । हमारा एरिया पैदावार में

सारे हिन्दुस्तान में सबसे आगे है । यदि वहां पर इस कैनाल के जरिए पानी हमें मिल जाता है तो फिर हमारा एरिया सारे संसार में पैदावार के मामले में सबसे आगे आ जायेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे एरिये में दो–तीन सब–स्टेशन मन्जूर हो चुके हैं । बबैन का जो 33 के० वी० का सब स्टेशन है, उसको 88 के० वी० का अपग्रेड किया जाना चाहिए । इसके अलावा बेरथली– में 38 के० वी० का एक सब–स्टेशन लगाया जाना है । इसके लिये हमने जमीन भी दे दी है लेकिन अभी तक इस सब स्टेशन को बनाये जाने का काम शुरू नहीं किया गया है । इस बारे में भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सबस्टेशन का निर्माण कार्य तुरन्त शुरू करवाया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमुना कैनाल का पानी इंडस्ट्रियल ऐफ्लुऐन्ट्स के कारण गन्दा हो जाता है । जब उसे लोग और डंगर पीते हैं तो वे बीमार हो जाते हैं । कई डंगरों की तो मौत भी होती रहती है । इसके अलावा उस एरिया में जब हवा चलती है तो उससे भी बहुत बुरी स्मैल आती है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस इंडस्ट्रियल पौल्यूशन को जल्दी से जल्दी रोका जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इलाके में दो ड्रेन्ज का बनाना बहुत जरूरी है । उनके नाम हैं बबैन और काजू । इनके न बनने से वहां पानी ठहर जाता है और लोगों की जीरी की फसल बरबाद

होती है । इनकी सैक्शन तो हुई पड़ी है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है इसे जल्दी शुरू करवाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, यमुना रिवर मेरे हल्के से गुजरता है और इसकी वजह से हर साल बरसात में 200–250 एकड़ जमीन कट जाती है । जमीन को कटने से बचाने के लिए जो ठोकरें मन्जूर की जाती हैं, उन्हें विभाग उस समय बनाता है' जब पानी बहता है । मैं चाहूंगा कि उस एरिया का सर्वे करवा कर ठोकरें बारिश शुरू होने के 2–3 महीनें पहले बनाई जाएं ताकि जमीन कटाव से बच सके वरना गरीब किसानों की जमीन हर साल काफी माता में कटती जा रही है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं० 18 पशुपालन विभाग की है । मेरे हल्के के अन्दर बहुत बड़े–बड़े गांव हैं और किसान तथा हरिजन भाइयों को पशु पालने का बहुत शौक है लेकिन डिसपैन्सरीज की उन्हें विशेष सुविधा नहीं है । गुमथला राव बहुत बड़ा गांव है लेकिन वहां कोई पशु डिसपैन्सरी नहीं है । इसके लिये उनकी पिछले 15 साल से डिमांड चली आ रही है । पशु पालन मन्ती इसे वहां मंजूर करके आए थे लेकिन अभी तक वह डिसपैन्सरी नहीं बनी । इसी तरह से महवा खेडी, सूरजगढ, गजलाना, धौलरा–खजूरी और मसाना गांव में पशु पालन डिसपैन्सरीज बनाई जानी चाहिएं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर काफी दूर दूर तक न तो कोई मकान हैं और न ही कोई गांव कुए । यदि उन पर जगह जगह बस क्यू शैल्टर्ज वन जाएं तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती है । ये बस क्यू शैल्टर्ज गुमथला राव संघाली, जठलाना, बीर बरटोली, छपरा, कोलापुर बीर मंगोली, ईशाहारी, गुड्डा, जोबल–एस ० के ० रोड पर और बकाना में बन सकते हैं ।

इसके अलावा, डिप्टी सीकर साहब, मेरी, यह भी प्रार्थना है कि मेरे हल्के में कुछ सड़कें ऐसी बनी हुई हैं जिनके ऊपर कोई बस नहीं चलती हालांकि उनके ऊपर 5– 5, 6– 8 गांव हैं । यदि ऐसी सड़कों पर बस सर्विस चल जाए तो वहां के लोगों को भी कुरुक्षेत्र आने–जाने में सुविधा हो जाएगी । ऐसी सड्कों के नाम हैं रादौर से लाडवा वाया बापा और मेहरा आदि । इसके ऊपर पांच छः गांव पड़ते हैं । कुरुक्षेत्र से टाटका सडक पर भी 4– 5 गांव पड़ते हैं । कुरुक्षेत्र से झगूरी सड़क पर भी 6– 7 गांव पड्हे हैं । कुरक्षेत्र से रामनगर सड़क पर 7 गांव पड़ते हैं । इसी तरह से मुस्तफाबाद–बरतोली–बहलोलपुर–लाडवा सड़क पर कई गांव पड़ते हैं । इन सब रूटस पर चूंकि कोई बस नहीं चलती इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनके ऊपर बसें चलाने की कृपा की जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं केवल डिमांड नं ० 4, 8, 11, 1 5, 17 और 24 पर बोलूगा । सबसे पहले मैं डिमांड नं ० 4 पर बोलूंगा । यह रैवेन्यू विभाग की है । मैं सरकार का बहुत आभारी हूं क्योंकि इसने किसानों के ऊपर जो टोडरमल के टाईम से रैवेन्यू का बड़ा भारी बोझ था उसे माफ किया है । हरियाणा चूकि इस लैड टैक्स को माफ करने वाला पहला प्रदेश है इसलिए इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं । वैसे भी, डिप्टी स्पीकर साहब, किसान के ऊपर जब कमी ओलावृष्टि, फ्लड, सू वे और अधिक वर्षा आदि के कारण मुसीबत आती है तो हमारी सरकार हर समय किसान की मदद के लिए आगे आती है । किसान की मुसीबत कौ अपनी मुसीबत समझ कर हर समय उनको ग्रान्ट दी गई है और इमदाद दी गई है । किसान इस सरकार के बहुत आभारी हैं बशर्ते कि अपो– जिशन के लोग उन्हें खर न करें, गुमराह न करें और उकसायें न ।

अब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं ० 8 पर आऊंगा । यह बात ठीक है कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया गया है । एक एक गांव कई कई सड्कों से जुड़ गया हए लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या हए । मैं तीन सारन से इस बात को कह रहा हूं । कभी हाउस में सवाल उठाता हूं, कभी बोलता हूं और कभी चिट्ठियां लिखता हु । मेरे हल्के में भूना रतिया रोड से विलेज कुनाल तक 13 किलोमीटर लैग्थ का एक लिंक रोड़ है जिसके वनाने पर डिपार्टमैंट कभी कोई एतराज

लगाता है और कभी कोई एतराज लगाता है । चौधरी भजन लाल जी से भी रिक्वैस्ट की थी, मंत्री जी से भी रिक्वैस्ट की थी, कई बार फाईल आई और गई लेकिन वह लगभग 1 किलोमीटर की सड़क पिछले चार साल में नही वन पाई । उसमें बात क्या है ' डिप्टी स्पीकर साहब, महकमा अलाइनमैंट बदलता रहता है और इनके कहने के मुताबिक उस पर 19 हजार रुपया खर्च आ चुका है । वे कहते हैं कि दो हजार रुपये का कुछ फर्क है, उस घाटे को हम कहां दिखाए ? मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस रोड को प्रायरिटी कम्पलीट करवाए । दूसरी सडक मोडिया खेडा के लिए है जो फतेहाबाद के नजदीक हए । वहां' चार मन्दिर हैं । इसको भी कृपा करके 2–3 महीने के अन्दर बनवाया जाए क्योंकि इमको भी बनते–बनते तीन सारन होगा हैं ।

डिप्टी– स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० 10 पर बोलूगा । यह बात ठीक है कि हस्पताल काफी अच्छे बन रहे हैं और रोहतक का इंस्टिचयूट पी० जी० आई० लैवल का बन रहा है लेकिन अगर आप देखें तो यह बात सही हए कि हस्पताल तो काफी सुन्दर और अच्छे हैं परन्तु उनमें दवाइयां नहीं मिलतीं । जनता चाहे कितना ही कह ले, एम० एल० ए० कह ले लेकिन वहां दवाइयां नहीं मिलती । जनता ने इसके लिए ऐजिटेशन तक किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना । मैं महकमा हैल्थ से पुरजोर अपील करूंगा कि बड़े–बडे हस्पताल बनाने से कोई फायदा नहीं है जब तर्क गरीबों को वहां दवाइयां न मिलें । जब कोई गरीब

व्यक्ति वहां दिखाने जाता है तो उसे पर्ची लिख दी जाती है लेकिन जब तक उसके पास पैसे न हों, उसका इलाज नहीं हो सकता । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सबसे पहरने दवाइयों का इन्तजाम किया जाए उसके बाद और काम किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, फतेहाबाद दे 80 बैड का हस्पताल है लेकिन डेढ़ साल से वहां लेंडी डाक्टर नही है । बार–बार कहा जाता है कि इसको प्रायरिटी दी जाए लेकिन आज तक वहां लेडी डाक्टर नही भेजी गई । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहाँ जल्दी से जल्दी लेडी डाक्टर को लगाया जाए ।

अब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं ० 11 पर बोलना चाहता हू । खजाना मैत्री कृपया इस बात की ओर विशेष ध्यान दें । फतेहाबाद मौडल टाउन 30 वर्ष से बना हुआ है लेकिन आज तक वहां पर सड़कों की कोई रिपेयर नहीं हुई । पहले तो हुड्डा और अर्बन अकैरटीज के बारे में 10 साल तक झगड़ा चलता रहा लेकिन बाद में कोई अमैंडमैंट की गई कि पुराने मौडल टाउन्ज की सड्कों की रिपेयर म्यूनिसि– पल कमेटीज करेंगी । इस सम्बन्ध में मैंने सी ० एम० साहब से भी रिक्वैस्ट की है और अब फाईनेस मिनिस्टर साहब से भी रिक्वैस्ट करता हू कि फतेहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी को स्पैशल अनुदान दिया जाए ताकि वहां सड़कों की रिपेयर हो सके । आज हालत यह है कि वहां साईकिल भी नहीं चल सकती, स्कूटर और कार तो क्या चलेंगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मै इरीगेशन पर अधिक बोलूगा । अभी हाल में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जो बैठे हुए नही है । मेरी सब से जरूरी मांग फतेहाबाद डिस्ट्रिव्यूटरी को पक्की करने की है । यह डिस्ट्रिव्यूटरी टोहाना से चल कर फतेहाबाद तक जाती है । फतेहाबाद टेल पर पडता है । मेरे ख्याल में यह 39 किलोमीटर लम्बी है । मैंने इसके बारे में कई बार मांग की है लेकिन यह आज तक पक्की नहीं की गई है । सुरजेवाला साहब जब हिसार के दौरे पर गये थे उस समय आफिसर्ज की मीटिंग हुई थी । उसमें यह फैसला हुआ था कि इसे अभी पक्का न किया जाये लेकिन इसकी ऐक्सटैन्शन कर दी जाये । वैसे तो इसकी दोनों ही' चीजें जरूरी है लेकिन पहरने इस की ऐक्सटैन्शन की जाये और बाद में इसे पक्का किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, इस डिस्ट्रिव्यूटरी में कई जगह पा फाइव हैं इसलिए इमका बैड काफी ऊंचा हो सकता है । बैड ऊँचा हौने से हजार एकड जमीन सैराब हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले फाल्ज को ठीक करके फिर इसे पक्का किया जाये ताकि और अधिक सिंचाई हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पहले फतेहाबाद, सिरसा, रतिया और टोहाना के एरिया मे बहुत फ्लड आते थे लेकिन अब वे फ्लड खत्म हो गये है । इन्होंने फ्लडज को चीमू पर रोक कर नहर में डाल दिया हए । पहले ये फ्लडज बड़ी तबाही करते थे लेकिन अब खत्म हो गये हैं लेकिन जो लोकल बारिश का पानी है वह रंगोई

नाले मेँ फैल जाता है जिसके कारण हजारो एकड जमीन खराव हो जाती है । मैंने एक प्रोपोजल सरकार को दी थी कि जो लोकल वारिश का पानी रंगोई नाले में फैल जाता है, उसे चौक करने के लिए इस रंगोई नाले को ड़ेन के रूप मे कन्वर्ट कर दिया जाये जिमने ये हजारों एकड़ जमीन डूबने से बच जायेगी । ड्रेन बन जाने से एक तो वहां का वाटर लैवल ऊंचा हो जायेगा और दूसरे यहां पर इरीगेशन भी ज्यादा हो सकेगी ।

इसी तरह से हमारे यहां फतेहाबाद ब्रान्च हए उसके साथ साथ 11 रैवेन्यू एस्टेटस लगती है । इस ब्रान्च ने उन गांवों को तबाह कर दिया है । उन गांवों के खेतों में पानी भर जाता है । कुछ तो पम्पिंग सैटस लगा कर पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा पानी भर जाता है । इस, पानी के कारण वहां पर सेम भी बहुत ज्यादा होती जा रही है जिमके कारण जमीन खराब हो जाती हैं ।. ये गांव हैं काजलहेडी, मोहम्मदपुर रोही और झढोपल वगैरह । जब बहुत ज्यादा सेम हो जाती है तब महकमे वाले जागते हैं वरना उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं । मैंने सरकार को एक प्रोपोजल दी थी कि फतेहबाद ब्रान्च के दोनों साइडों पर ड्रेन खोदी जाये ताकि सेम का पानी उस ड्रेन में आ जाये । ऐसा करने से वाटर लौगिग दूर हो जायेगी और इरीगेशन भी बढ़ेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इलाके से वाटर लौगिग की प्रोब्लम दूर की जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमान्ड नं० 18 इन्डस्ट्री के बारे में है । यह ठीक है कि हमारे प्रदेश में इन्डस्ट्री बहुत भारी तरक्की कर रही है । उद्योग पनप रहे हैं । लोगों को इन्डस्ट्रियल टेरनिंग भी दी जा रही है । हमारे बच्चे आई० टी ० आई० में ट्रेनिंग ले कर अपने पांवों पर खड़े हो रहे हैं । लेकिन मेरी काफी पुरानी मांग है कि फतेहाबाद बहुत पुराना और बड़ा सब–डिविजन है लेकिन वहां पर आई० टी ० आई० नहीं है । मुझे तीन साल से आश्वासन ही मिल रहा है कि वहां पर आई० टी ० आई० बनायी जायेगी । कोई भी ऐसा सब–डिविजन नहीं है जहां पर आई० टी० आई० न हो इसलिए मेरी इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट है कि वहां पर आई० टी ० आई० खोली जाये । हमारे यहां पुरानी तहसील की बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसमें आराम से आई० टी ० आई० खोली जा सकती है । पिछले सैशन में भी मुख्य मली जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक वहां पर आई० टी ० आई० चालू नहीं हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जल्द से जल्द आई० टी ० आई० खोली जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश में ऐग्रीकल्चर पर काफी पैसा खर्च हो रहा है । ऐग्रीकल्चर के लिए बिजली पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन फिर भी बिजली पानी की काफी परेशानी है । हमारे यहां रतिया को पैडी का ऐरिया डिक्लेयर किया गया था । जब भी उस एरिया के बारे में पूछा जाता कुए

कि क्या कुछ हो रहा है तो यही कहा जाता है कि पालिसी बन रही है । अगर ऐसी ही बात है वह पालिसी जल्द बनायी. जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि मैं उस कार्पोरेशन का चेयरमैन हू । वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का पांच करोड़ दस लाख का कैपिटल है जिसने तीन करोड़ सत्तर लाख रुपये का मुनाफा दिखाया है । हमारी कार्पोरेशन बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है । इसके अलावा, मैं यह भी कहूगा कि हरियाणा में टूरिस्ट कम्पलैक्स बड़ी भारी तादाद में बनाए जा रहे हैं । फतेहाबाद भी सैन्ट्रली लोकेटिड एरिया है । दिल्ली से पंजाब को जो बस जाती है वह सिरसा, फतेहाबाद होती हुई जाती है । फतेहाबाद से चण्डीगढ, भट्टू और रतिया को भी बसें जातीं हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां से दस साइड पर बसें जाती हैं लेकिन वहां पर अभी तक कोई टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं है । इसलिए वहां के लिए भी टूरिस्ट कम्पलैक्स की रूप–रेखा. बनायी जाये और मैं आशा करता हूं कि इसे अगले साल तक बना दिया जायेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त में आज के दिन ग्रीन, व्वाइट और पीली क्रान्ति आ रही है जिसके लिए सरकार मुबारिकबाद की पाव है । इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 4, 8, 7, 8 और 9 पर

बोलना चाहूंगा । सब से पहले मैं रैवेन्यू की डिमान्ड पर बोलना चाहता हूं । हमारी सरकार ने किसानों के लिए काफी राहत दी है क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है । जितना पैसा इस सरकार ने बिजली और पानी के लिए रखा है, इससे ज्यादा किसानों को और कोई भी सरकार राहत नहीं दे सकती । हमारी सरकार ने खालों का कर्जा और मालिया माफ कर दिया है । यह बड़ी भारी बात है । अब मैं तालीम के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा । पहले तो मैं डोमिइसायल सर्टिफिकेट के बारे में अर्ज करना चाहूंगा । इस सर्टिफिकेट के लेने के लिए लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । अगर किसी बच्चे ने डोमि– सायल सर्टिफिकेट बनवाना है या शड्यूल्ड कास्टस का सर्टिफिकेट लेना है तो एस० डी० एम० तहसीलदार, पटवारी और एम० एल० ए० तक की तस्दीक करवानी पड़ती हे । जब किसी एम० एल० ए० ने ही तस्दीक कर दी तो फिर पटवारी की क्या आवश्यकता है? इसी तरह शड्यूल्ड कास्टस का सर्टिफिकेट लेने के लिए चार चार दिन खराब होना पड़ता है । इस सिस्टम में भी तरमीम की जानी चाहिए । शड्यूल्ड कास्टस के लिए तो उनके बर्थ के टाईम ही यह एंटरी हो जानी चाहिए ताकि उन्हें बार बार ये सर्टिफिकेटस लेने के लिए लोगों के पास चक्कर न काटने पड़े । जैनुइन आदमी को सर्टिफिकेट लेने के लिए काफी तकलीफ उठानी पड़ती है । चार चार दिन तक पटवारी डी० सी० आफिस में मिलता नही है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती रहती है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं स्कूलो के बारे मे भी एक अर्ज करना चाहता हूं । मेरे अपने हल्के में 12 स्कूल्ज हैं जिनमें से तीन हाई स्कूल्ज हैं, तीन मिडल और छः प्राइमरी हैं । वहां पर लड़कियों के लिए न कोई सरकारी कालेज है और न हीं स्कूल है । सोशल संस्थाओं की मेहरबानी से कालेज चल रहे हैं । मेरे हल्के की आबादी 1 लाख 34 हजार है । लेकिन लड़कियों का कोई कालेज नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक लड़कियों का भी कालेज सरकार की ओर से खोला जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार टैलीकल ऐजूकेशन और आई० टी ० आईज० को बढ़ावा जरूर दे रही है जिसके.. कारण लोगो को रोजगार मिल रहा है । बाबू वनने के लिए लाखों लोग फिर रहे हैं लेकिन आई० टी ० आई० पास वाले लोगों को मुलाजमत मिल ही जाती है । इसलिए अधिक से अधिक आई० टी० आइज० खोले जाये ।

डिप्टी स्पीकर, साहब मैं एक बात और कहूंगा कि आज के दिन हमारे नेशनल करैक्टर में वहुत कमी आती जा रही हए । मौरल ऐजूकेशन का स्कूलों मैं भी एक पीरियड होना चाहिए जिममें हमारे लीडर्ज की जीवनियों के बारे में पढाना चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे कि हमारेरू देश में आजादी कैसे आयी ।

डिप्टी स्पीकर साहब. मैं इसके बाद एक अम्पंताल का जिक्र करूंगा । हमारे यहां पर 75 बैड का नामुकम्मल अस्पताल है । 1901 में वहां पर अंग्रेजों के जमाने का 50 बैड का अस्पताल बना हुआ है । अब उसको सरकार 75 बैड का बनाने जा रही है । मेरा कहना यह है कि सरकार के नार्मज के मुताबिक 30,000 की आबादी पर एक पी० एच० मी ० होनी चाहिए । वहां की आबादी के मुताबिक जोकि डेढ़ लाख के करीब है, 5 पी० एच० सी० बनते हैं इसलिए यहां एक 100 बैड का अस्पताल होना चाहिए । अम्बाला कैट इसके अलावा जी ० टी ० रोड पर स्थित है जिसको आप ऐक्सीडैटल रोड भी कह सकते हैं । वहां पर रश बड़ा भारी रहता है । वहुत ही मुनासिब मांग है । मैं कई बार यहां पर हाउस में सारे सैशन्ज में ही मांग कर चुका हु कि इसको कम से कम 100 बैड का अस्पताल अवश्य बनाया जाये । साथ ही हल्का मुलाना और नग्गल लगते हैं, वहां के मरीज भी यहां पर आते छैं । वहां पर भी कोई बड़ा अस्पताल नही है । इसलिये मेरा कहना यह है कि इसको कम से कम 100 बैड का अस्पताल जरूर बनाया जाये । इसके बाद मैं डिमाड नं० 8 पर सडको कैं बारे मे कुछ कहना चाहता हूं । पिछले साल हरियाणा में 403 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाई गयी हैं । हिसाब से भी 4–5 किलो मीटर का हमारा हक तो बनता ही है । इस बारे में हमें कम से कम हमारा हक तो मिलना ही चाहिये । मेरे हल्के में तो कोई गांव भी नहीं है । हमारे यहां कुल 5 किलो मीटर सड़क बनाने की जरूरत है । साढ़े. तीन किलो– मीटर का टुकडा फोर लेन का है जो जगाधरी

रोड पर पी० डन्ब्ल्यू० डी० रैस्ट हाउस से लेकर टांगरी तक है और एक डेढ़ किलो मीटर बबियाल रोड का टुकड़ा है, जिसको बनाया जाना चाहिये । बवियाल रोड पर इतनी टैरफिक है कि वहां पर आने जाने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है । इनकी जल्दी से जल्दी मुरम्मत की जाये जो हमारा हक भी हए । अम्बाला में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी है । वहां पर एक इंडियन आयल का दफतर खुला है । वहां से करोड़ों रुपये के सेल्ज टैक्स की आमदनी होती हए । मेरा कहना यह है कि इसका कुछ हिस्सा हमारे भेल पर भी खर्च जरूर होना चाहिये ताकि हमारे शहर की भी कुछ तरक्की हो सके । ऐनीमल हस्बैडरी की बात भी यहां पर आयी है । दूध देने वाले पशु हमारे इलाके मे बहुत हैं । यह वात ठीक है किं एक अस्पताल जरूर हमें दिया गया है तेकिन वह नाकाफी है । वहां पर 6 तो गवाल मंडियां हैं । वहां दो अस्पताल तो पहले से ही हैं एक और जो दिया गया हए इसको मिलाकर कुल तीन अस्पताल होते हैं, जो नाकाफी हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि 20,000 पशुओं की आबादी को ख्याल में रखते हुए वहां पर अस्पताल और दिये जायें । अम्बाला तहसील को ड्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिये हरियाणा सरकार ने 15 अप्रैल, 1984 कौ भारत सरकार को एक सिफारिश की थी । तीन मैशन्ज में मेरे उस रैजोल्यूशन पर बहस चलती रही । इस बारे में सिफारिश भी हो गयी । उसके बाद रोहतक की बारी आयी । रोहतक तो हो गया लंकिन अम्बाला पीछे

रह गया । यह बात मेरे समझ नहीं आयी कि हम कैसे पीछे रह गये ? अम्बाला वैसे सारे नार्म्ज पूरे करता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर बिजली कीं लागत भी बहुत मामूली है । सारी छावनी में सिर्फ 2 लाख यूनिट बिजली लगती है । एक से लेकर 5 वर्कर्ज और एक से लेकर 5 हौर्स पावर्ज की मोटर्ज जरा पर छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज मैं हैं । सारे शहर में इन इंडस्ट्रीज से गरीब वर्कर्ज और मजदूरों को काम मिलता है । हमारा शहर या तो साईंस के सहारे या फिर मिलिटरी के सहारे खड़ा है । अगर मिलिटरी आपरेशन स्कीम पर चली जाये या साईन्स का उद्योग बिजली न मिलने की वजह से बन्द हो जाये तो हमारा शहर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है । (व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी काफी ज्यादा है लेकिन म्यूनि– सिपल कमेटी ने अपने काम करने होते हैं और सरकार ने अपने काम करने होते हैं । मिक्सिज का वह घर है । 400–500 मिक्सिज की इंडस्ट्रीज वहां पर है । इसके अलावा अम्बाला कैट को सिटी आफ साई टीफिक इक्कूमैंट्स भी कहते हैं । यह सारे हरियाणा की ऐक्सपोर्ट का वन–थर्ड हिस्सा अकेला ही ऐक्सपोर्ट करता है । उसके मुताबिक भी हमारा हक बनता है कि इसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर कराया जाये और ऐसा कराने में इसको तरजीह दी जाये । इसमें चार हल्के भी लगते हैं । एक मुलाना, दूसरा नग्गल, तीसरा अम्बाला शहर और चौथा अम्बाला कैट । इन चारों हल्कों के लोग जब यह एलान होगा तो बड़े

खुश होंगे और उनको बहुत फायदा भी होगा । कायदे के मुताबिक उनको उनका हक मिलना चाहिये । धूलकोट में बिजली का सबनटेशन है । वह अम्बाला में है । वहां से बिजली अम्बाला कैट से होकर गुजरती है । लेकिन अम्बाला कैट को वहां से बिजली नहीं मिलती । कहीं 33 के० वी० का स्टेशन बना है, कही 88 के० वी० का स्टेशन बना है तो कहीं पर 220 के० वी ० का स्टेशन बना है । स्टेट में बड़ी तरक्की हो रही है । बहुत सी नाईनों को बिछाया जा रहा है लेकिन अम्बाला कैट को भी उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिये । एक लाईन खुड्डा तक पहुंच चुकी है । खुड्डा अम्बाला कैंट से 5 किलो– मीटर दूर है । वहां से अगर अम्बाला कैट को जोड़ दिया जाये तो हम कम से कम दूसरों के ऐट पार तो हो जाते हैं । अब क्या होता है? जगाधरी में बिजली हो, यमुना नगर में हो, शाहबाद में बिजली हो और अम्बाला कैट में बिजली न हो तो लोग हमसे जवाब तलबी करते हैं कि क्या खास वजह है भाई, क्यों बिजली नहीं हमें मिलती है तो हम जवाब देने के काबिल नहीं होते ।

श्री उपाध्यक्ष : धमीजा जी, आपको क्या हो गया है? Do not paint the dark side of the [picture ? इतनी बुराई क्यों करने लग रहे हो? अगर अम्बाला कैट वालों को पता लगेगा कि कैट पीछे रह गया तो वे क्या कहेंगे? आप तो बढ़िया बढ़िया बातें करते रहे हो, अब भी बढ़िया बात कहो ।

सेठ राम दास धमीजा : डिप्टी स्पीकर साहब, दो बातों में हम पीछे हैं बाकी सब बातों में आगे हैं । हमारी 20 लाख रुपये की म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी हूय हे । हमारे यहां 95 परसैट स्लम क्लीयर हो चुका है । कोई गली कच्ची नहीं रह गयी है । आज कोई वहां का आदमी यह नहीं कह सकता कि हमारी गली कच्ची है । जहां पर आज से सौ साल पहले शहर में 2–3 फुट तक कीचड़ पड़ा रहता था, वह सारे का सारा निकाल दिया गया है । वहां पर अब हालत अच्छी है । बिजली, पानी, सडकें और नालियां ये 4 जरूरतें गरीबों की है । गरीबों की हर जरूरत पूरी कर दी गयी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट में रेलवे का डिविजनल औफिस खोलने का फैसला हुआ है । वहां पर काम चल रहा है । मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार को हरियाणा सरकार यह सिफारिश करे कि वह अपने काम में तेजी लाये । 147 एकड़ जमीन ऐक्यायर भी हो चुकी है । डिविजनल औफिस की बिलडिंग छत तक पहुंच चुकी है । जब यह काम वहां पर मुकम्मल हो जायेगा तो 8,000 फैमिलीज वहां पर आबाद होंगी और इससे 40,000 की आबादी और बढ़ेगी । मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि यदि ये रेलवे को इस बात की सिफारिश करेंगे तो शहर में काफी रौनक नजर आने लगेगी । शहरियों की आबादी 30 प्रतिशत है और वहां से टैक्स वे लोग 70 प्रतिशत देते हैं । सड़कें वहां पर मार्किट कमेटी की वजह से कुछ खराब हैं । मार्किट

कमेटी को म्यूनिसिपल कमेटी के पास 40 परसैटं पैसा जमा करवाना चाहिये लेकिन वह कुछ हिस्सा नहीं देती । शहर में 24 सड़कें हैं, 12 कौस रोड्ज हैं । इन 24 में से 20 सड़कें तो बना दी थीं लेकिन 4 मार्किट कमेटी ने बनानी थी परन्तु उनके बनने की हमें आशा नजर नही आती । हमें यह भी उम्मीद नहीं है कि वह उनके लिये हिस्सा देगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, 20 प्वायंट प्रोग्राम के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं । जितना पैसा 20 प्वायंट प्रोग्राम के लिये खर्च हुआ है, वह सारे देश की प्रगति के लिये ही है । यह 20 प्वायंट प्रोग्राम इतना मुनासिब और सही रास्ता है कि इसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी ही थोड़ी है । अगर यह प्रोग्राम गरीब के घर तक पहुंच जाये तो उसको पूरा हक मिल पायेगा । मैं यह कहूंगा कि जहां तक नये 20 प्वायंट प्रोग्राम का ताल्लुक है, उसमें कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसका छगन न रखा गया हो । पहले 13 प्वायंट गरीबों के लिये खास तौर पर रखे गये हैं ।

अब मैं पलवल की मीटिंग का जिक्र करूंगा । एस० वाई० एल० नहर की कंस्ट्रक्शन का काम जब तक भारत सरकार अपने हाथ में नही लेती तब तक यह नहर बनती नजर नही आती क्योंकि वायदा करने की और बात है और उसको पूरा करना और बात है । एस० वाई० एल0 नहर हरियाणा की सबसे बड़ी जरूरत है । इससे हमारी प्यासी धरती के लोग खुशहाल होंगे । लोग यह

देख रहे हैं कि किस दिन हमारी धरती पर यह पानी आयेगा । जिस दिन यह पानी हरियाणा में आयेगा, उसी दिन से हरियाणा के लोग मालामाल होना शुरू हो जायेंगे । मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि वह इस सारे हाउस की तरफ से आनरेबल प्राईम मिनिस्टर को यह गुजारिश करे कि वह इसका काम अपने हाथ में ले ले । वह यदि एलान कर दें कि यह काम हमने आरने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है तो काफी है । एम० वाई० एल० के पानी के बंटवारे का फैसला तो आ चुका है । जो भी फैसला होगा, चाहे हक में हो या अगेन्स्ट, इसको तो हमें सिर झुकाकर मानना पड़ेगा । अपोजिशन वाले भाइयों का हमें पता नहीं वे मानते हैं या नहीं मानते । लेकिन जितना पानी हमें अवार्ड. में मिलेगा, उतना पानी आयेगा तो सही ।

डिप्टी सीकर साहब, एक बात मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा । पिछले सैशन में मुझे अम्बाला बस–गड्डे की कंस्ट्रक्शन के बारे में 31 मार्च, 1987 की डेट मिली थी । एक साल से तो वहां पर मिट्टी भी पूरी नहीं पड़ा है । वहां पर खड्डा था । अभी तक वहां पर काम चल रहा है । यह हरियाणा का सबसे बड़ा बस–स्टैड है और सबसे बड़ी वर्कशाप है । अम्बाला कैंट की डेढ़ लाख की आबादी है और वहां से तकरीबन 1 5–20 हजार आदमी रोजाना सफर कुरते हैं । मेरा कहना यह है कि इसके लिये कोई डेट निश्चित कर दें कि इस डेट तक इसको बना

देंगे । इसका अगर संगे–बुनियाद चीफ मिनिस्टर साहब से रखवा दें । तो कोई वजह नहीं कि यह जल्दी कम्पलीट न हो ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने पंचों और सरपंचों को एस० वाई० एल० का काम मौके पर दिखाने का जो फैसला लिया है यह सरकार का बहुत ही अच्छा काम है । अगर किसी काम को मौके पर ही देखा जाए तो उसकी सही तस्वीर सामने आ जाती है । अपोजिशन की एक टीम कुछ समय पहले वहां गई थी और उन्होंने कहा था कि वहां पर काम तसल्लीबख्श चल रहा है जबकि ऐसी बात नहीं थी । अपोजिशन वाले तो चाहते हैं कि हरियाणा में पानी न आप, इन्हें सरकार को बदनाम करने का मौका मिले और इस बात को लेकर वे सरकार के खिलाफ प्रौपैगन्डा कर सकें । अपोजिशन वाले झूठा प्रौपेगन्डा करते हैं कि हम लोगों का कर्जा माफ कर देंगे । हमारी सरकार झूठे वायदों में यकीन नहीं करती । हमारी सरकार तो उतना ही कहेगी जितना वह कर सकती है । डिप्टी स्पीकर साहब हमारी सरकार ने किसान क्एरू लिए जितना काम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया । चौधरी लीला कृष्ण वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं और इस कार्पोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है । हुस कार्पोरेशन ने बहुत अच्छे गोदाम वनाए है । डिप्टी स्पीकर साहब, डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन का काम भी बहुत अच्छा रहा हैं और इसने सफेद क्रान्ति, वाइट इंकलाब, लाने में बहुत ज्यादा काम किया है ।

डिप्टी स्पीकर साहब. कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट का भी अच्छा काम रहा हए और बहुत लोगों की इस. विभाग ने इमदाद की है । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोआप्रेटिव का काम सही मायनों में देखना हो तो अंडेमान में जाकर देखा जा सकता है । वहां पर सौ परसैन्ट काम कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के हाथ में है और वहां यह डिपार्टमैंट इतना कामयाब है जिस यहां जिक्र नहीं किया जा सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहव, यहां पर हरियाणा रोडवेज का जिक्र भी आया । ठीक बात है कि हरियाणा रोडवेज ने हिन्दुस्तान में नाम कमाया हए और यह काबिले तारीफ बात है । डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला में किश फिशर नाम के टूरिस्ट कॉम्पलैक्स का उदघाटन 1 जनवरी को चीफ मिनिस्टर साहब ने किया और मैं समझता हूं कि यह कॉम्पलैक्स हरियाणा के अन्दर सब से बड़ा और अच्छा कॉम्पलैक्स होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कोई हवाई अड्डा नहीं है । एक हवाई अड्डा हिसार में खोला गया था लेकिन उसको भी बन्द कर दिया गया । मैं चाहता हुं कि अम्बाला में एक हवाई अड्डा बनाया जाए । मगर यहां हवाई अड्डा बना दिया जाए तो यह बहुत कामयाब रहेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला कैट मे एक जिमनेजियम हमारी सरकार बना रही है जो वर्ल्ड में नम्बर एक पर होगा और

यह देखने के काबिल होगा । यहां पर बच्चों को खेल कूद में पूरा हिस्सा मिलेगा । हमारे बच्चे जब बाहर देशों में जाएंगे तो देश का नाम ऊंचा करेंगे जिस तरह से पी ० टी ० ऊषा ने किया है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी मांग है कि अम्बाला छावनी में एक हुड्डा कालोनी बनाई जाए । इसकी वहां पर बहुत जरूरत है । डिप्टी स्पीकर साहब. सदन में चौपालों का जिक्र किया गया । हरेक हल्के में चौपाल दी गई है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा जिस तरह से दूसरी जगहों पर चौपाल दी गई है उसी तरह से मेरे हल्के को भी चौपाल के लिए 10 हजार रुपये दिए है लेकिन दम हजार रुपए में चूकि चौपाल नहीं बन सकती इसलिए इस अमाउन्ट को और बढाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब । अगर भारत सरकार से अम्बाला को हैवी इंडस्ट्रीज मिल जाए तो अनएम्पलाएमैट की काफी समम्या हल हो सकती है और बेकार लोगों को काम मिल सकते है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हुं और आपका धन्यवाद करता हुं क्योकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी चंदा सिंह (नीलेखेडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा चल रही थी तो उस वक्त भी मैं बोलना चाहता था । मैं आपका बहत शक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । उपाध्यक्ष

महोदय, नीलोखेडी ऐसा टाउन है जिसको उस वक्त बसाया गया था जब देश का विभाजन हुआ था और सारे लोगों के कैम्पों से उठाकर वहां बसा दिय (गय था । स्वतन्त्रता से पहले भारत के नक्शे पर वहां कोई गांव नही था । जल समय यह टाउन बसाया गया उस समय यहां के ला? बड़ी –बडी योजनाए बनाई गई थीं । जब पंडित जवाहर लाल नेहरू नीलोखेडी आते थे तो वे बहुत खुश होते थे । वे देश के अन्दर हजारो नीलोखेडी बसाना चाहते थे । जब यह टाउन बसा था तो उस वक्त एक–दो सरकारी कारखाने बनाए गए थे । एक तो रेलवे की वर्कशौप यहां पर थी और एक जीटर ट्रैक्टर अमैम्बल करने का कारखाना लगा था जोकि बाद में वह वहां से चला गया । जिस वक्त शह शहर बना था उस वक्त यहां पर सड़कें बनाई गई थीं और उमके बाद कोई काम इन पर नहीं हुआ । वहा की म्यूनिसिपल कमेटी की यह हालत है कि उसके पान अपने मूलाजिमो को तनखाह देने को नहीं है । पिछले तीन महीने सें उसने तनखाह नहीं दी है । सड़कें जब से बनी है तब से उनकी मरम्मत नहीं हुई और न कोई नई सड़क बनी है । मेरे से पहले वर्मा साहब इम कांस्टिचुऐसी का प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन उस समय भी कोई काम नहीं हुअ । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कु छ सडकें बताना चाहती हूं जिनका बनाना बहुत जरूरी है । अमीन से किरमच की सड़क की किलोमीटर है । कारसा से सांकडा तीन किलो मीटर का फाउल है । इसी तरह निगडू से सांकडा भी तीन किलो मीटर का फासला है । रमाना रमानी से बडालवा आठ किलोमीटर का फासला है ।

समीर से पढ़ाना दो किलो मीटर है । शामगढ से ' तरावडी डेढ़ किलोमीटर का फासला है, वरथल से अमीन तीन किलोमीटर का फासला है और रायपुर से बरथल साढ़े तीन किलोमी टर है । डिप्टी स्पीकर साहब । मेरे क्षे व में नीलोखेडी और तरावडी दो मार्किटिंग कमेटीज हैं और इनका एक करोड़ रुपया मार्किटिंग बोर्ड में जमा है । अगर हमको इक्का तीसरा हिस्सा भी मिल जाए तो हमारी सड़कों का खर्चा पूरा हो सकता है ।

12.00 बजे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता है । इन्तनयली कलसी, हथीरा, बारवा और एबला में इस समय मिडिल स्कूल्ज हैं । इन सभी जगहों पर हाई स्कूल बिल्डिंग्ज के लिए पन्द्रह पन्द्रह कमरे तैयार हैं । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको हाई स्कूल अपग्रेड कर दिया जाप । इसी तरह से कुमारखेडी में राक मिडल स्कूल की बिल्डिग बनी पड़ी है । वहां पर जो प्राईमरी स्कूल पहले है, उसको अप–ग्रेड करके मिडल स्कूल बना दिया जाए इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के नीलोखेड़ी में एक कालेज और नवोदय विद्यालय खोलने का भी प्रावधान किया जाए ताकि हुस इलाके के लोगों को फायदा हो सके । बड़ी देर से यहां पर कालेज की हमारी डिमांड चल रही है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, नीलोखेडी में आज से 40 साल पहले एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर की बिल्डिग बनाई गयी थी । अभी उसको सिविल हस्पताल में अपग्रेड कर दिया है और उसमें एक दो डाक्टर भी हमें मिल गये हैं लेकिन फिर भी जो पूरी की पूरी सहूलियतें वहां पर पब्लिक के लिये मुहैया की जानी थीं, वे अभी तक मुहैया नहीं की गयी हैं । इस तरफ ध्यान दिया जाए । इसी तरह से तरावडी के अन्दर एक डिसपैन्सरी थी उसको प्राईमरी हैल्थ सैन्टर ' बना दिया गया है । केवल एक डाक्टर अभी तक सरकार की ओर से वहां पहुंचा है और वहां दूसरी किसी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है । तरावडी की जो डिस्पैन्सरी थी उसको बदल कर निगडू में ले गये हैं लेकिन यह सब कुछ कागजों में ही किया गया है शायद एक डाक्टर वहां पर भेजा है । इसी तरह से हमारी हैल्थ सैन्टर्ज के बारे सौकडा रमाना– रमानी गांवों की भी डिमांडज हैं । मेरी सरकार से दरखास्त है कि मेरी इन बातों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत न हो क्योंकि हैल्थ को टौप प्रायरिटी मिलनी चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, नीलोखेडी और तरावडी में दो म्यूनिसिपल कमेटीज' हैं । इनके पास पैसा बहुत कम है । यहां तक कि नीलोखेडी की म्यूनिसिपल कमेटी का सारा पैसा तो तकरीबन तनख्वाहों में ही निकल जाता है । शायद एल ० आई ० सी ० से भी लोन लिये गये हों । पैसा न होने के कारण सीवरेज,

सड्कों और पीने के पानी की बुरी हालत हए । इन दोनों म्यूनिसिपल कमेटीज को सरकार की तरफ से ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाए ताकि उस इलाके के विकास का कार्य हो सके । लोगों के विकास के लिये, लोगों की सेहत के लिये इस तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है । मेरे हल्के में समाज कल्याण विभाग की ओर से जो हरिजनों के लिये चौपालों का काम था, वह भी अधूरा पड़ा है । सरकार इस तरफ ध्यान दे क्योंकि दलित लोगो और हरिजनों की भलाई के लिये काम करवाया जाना सरकार के अपने हित में ही है । इन लोगों की सरकार को हर प्रकार से सहायता करनी चाहिये चाहे वह पैसे के मामले में हो या मकान आदि के सम्बन्ध में हो । इन्हीं लोगों के कारण आज देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो रहा है । इन लोगों के उत्थान के लिये अभी भारी विकास के कार्य करने की आवश्यकता है जिनकी ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये । इससे देश और प्रदेश की उन्नति होगी । जितना भी ज्यादा कर्जा हो सके, सरकार को इन गरीब तबकों के लोगों को देना चाहिये ताकि वे अपने जीने के लिये कोई न कोई काम धन्धा भी कर सकें । सरकार ने काफी मदद इस बार की है । अगर इससे ज्यादा और प्रोत्साहन सरकार दे सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी । इन लोगों के पास कोई ट्रेनिंग नही है, कोई साधन नही है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें । अगर कोई छोटा मोटा उद्योग ये लोग लगाना चाहे तो –उनके पास लाखों रुपया नही हो सकता । यहां तक कि अगर कोई गरीब किसान भी अपनी

खेती बाड़ी छोड्कर अपना कोई व्यवसाय या काम करना चाहे तो वह भी बिना सरकार की मदद के नहीं कर सकता । व्यवसाय करने के लिये लाखों रुपये की आवश्यकता होती है और वह तभी पूरी हो. सकती है जबकि सरकार की तरफ से इन गरीबों को इमदाद दी जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बिजली और सिंचाई मन्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारा इलाका चावल की खेती के लिये मशहूर है सारे भारत में वहां का चावल जाता है । क्वालिटी और क्वांटिटी दोनो लिहाज से नोलोखेडी व तरावडी की प्रसिद्धि है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उस इलाके में पूरी बिजली की सप्लाई नही है । तरावडी में एक सब–स्टेशन 33 के० वी ० का आज से कई साल पहले मन्जूर हुआ था लेकिन उस पर अभी तक काम चालू नही किया गया है । हमारे इलाके की उपज को देखते हुए सरकार को हंस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि इस इलाके की पैदावार और बढ़ सके और लोगों को भी इससे लाभ हो सके ।

डिप्टी सीकर साहब, चौधरी भजन लाल जो कें समय में वहां एक आई ० टी ० आई० खोलने का सरकार का इरादा था लेकिन वे तो सैन्टर में चले गये और यह मामला अब वहीं पर ही रुका पड़ा है । इसलिये सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि अगर उस इलाके में आई० टी ० आई० खोल दिया जाए तो लोगों को बहुत फायदा होगा । लोग वहां से कुछ न कुछ ट्रेनिंग करके

अपना काम धन्धा शुरू कर सकेंगे । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और बहुत सालों से नीलों बेड़ी में आई० टी ० आई ० की जो मांग चली आ रही है, उसको इम्पलीमैंट करवाएगी । वहां पर एक लैन्ड डिवैल्पमैंट बैक भी बना हुआ है और वह बैंक एक किराये की। बिल्डिग में चल रहा है । इसी तरह से तरावडी, निगडू और अमीन में भी बैक्स हैं और वे भो प्राईवेट बिल्डिगों में चल रहे हैं । उनको चाहिये कि वे अरनी बिल्डिगें बनाएं क्योंकि उनके पास अपने साधन हैं । इसलिये सरकार की तरफ से

उन्हें यह हिदायते होनी चाहिये कि वे अपनी बिल्डिंगें बनाएं जिससे सरकार 'को भी बचत होगी । मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद करता हू कि आपने आज मुझे बोलने के लिये समय दिया । कई बार मैं खड़ा भी हुआ लेकिन. समय नहीं मिला । फिर भी मैंने अपने विचार आप लौगों के सामने, अपने हल्के से मुताल्लिक रखे हैं ताकि कल को हम वहां जाकर अपने बोटर्ज से यह तो कह सकें कि भाई हमने भी विधान सभा के अन्दर आप लोगों की भलाई के लिये, विकास के लिये काफी कुछ कहा है । मैं तो अपने हल्के के मुताल्लिक निवेदन ही कर सकता हूं बाकी जो पालिसी मैटर्ज हैं वे तो मिनिस्टर साहेबान ने ही हल करने हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, यह इस विधान सभा का शायद आखिरय सैशन होंगा । पता नहीं

कौन वापिस आता है कौन नही अ है । इसलिये सभी को यहां बोलने का मौका मिलना ही चाहिये ताकि किसी के दिल में कोई बात रह न जाए । अन्त में मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और एक बार फिर सरकार से रिकवैस्ट करता हू कि जो–जो सजैशंज मैंने यहां पर रखी हैं उनको पूरा किया जाए । धन्यवाद ।

चौधरी प्रभु राम (सढौरा–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हू । इस सात्र का बजट जो वित्त मन्त्री महोदय नें यहां पर रखा है, वह बहुत अच्छा बजट है और उस बजट में किसी के ऊपर कोई टैक्सो का बोझ नहीं डाला गया है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के के बारे मं कुछ बातें कहना चाहता हूं । मेरा हल्का घाट का इलाका है, वहा पर बहुत गरीब लोग बसते हैं । हरिजन और बैकवर्ड लोग बसते है । इस बजट के अन्दर सरकार ने इन लोगों के लिए काफी पैसे का प्रावधान रखा है, इन लोगों को काफी इमदाद दी है । मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इन लोगों की जहां इतनी मदद करने का सरकार ने आश्वासन दिया है वहां इनके रहने के लिये जिनके पास कोई साधन नहीं है, जमीन नहीं हए, मकान वगैरह भी बनाए जाने चाहिये । सरकार शहरों में कालोनीज बनाने जा रही हए । शहरों में तो पहले ही लोग खुशहाल होते हैं, लोगों को काफी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वे अपने मकान अपने आप भी बना सकते हैं ।

अगर उसी तरह की कालोनीज देहातों में बनायी जाए तो उमसे सरकार को भी और लोगों को भी फायदा होगा । मेरा इलाका ऐसा है कि जहां पर कच्ची झोंपडियां बनी हुई हैं और हर साल किसी न न किसी कारण से उनमें आग लग जाती है और लोग बरबाद हो जाते हैं न् डिप्टी स्पीकर साहब, जब आग बुझाने वाले आते हैं तो वे इन लोगों से आग बुझाने की कीमत भी मांगते हैं । इसलिये इस तरह की हिदायतें होनी चाहिये कि इस तरह से जब लोग बरबाद हो जाएं, आग लग जाए तो उन से आग बुझाने के चार्जिज नहीं लेने चाहिये । एक तो वे लोग वैसे ही मर जाते है दूसरा उन से चार्ज किया जाता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्कें के अन्दर चार पांच पुल बनने बड़े आवश्यक है जिनके न बनने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है । मैं पुलों का नाम बता देता है जोकि इम प्रकार से हैं–

(1) 'बिलासपुर घनौड़ा रोड पर सोमनदी पर पुन जोकि हिमाचल को मिलाता है, ।

(2) सढौग से मिरजापुर घाट जाते हुए।

(3)) सढौरा से नारायागगढ़ जाते हूप मारकण्डा नदी का पुल ।

(4) नारायणगढ से गगरानी जाते हुए ।

इन पुलों के ऊपर बरसात के दिनों में आने जाने– में काफी दिक्कत होती है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है । कई कई दिनों तक पानी रुका रहता है । सढौरा से मिरजापुर का जो पुल है, इसके लिये चौधरी भवन लाल द्वारा पहले एक बार एलान भी किया जा चुका है लेकिन चौधरी भजन लाल जी बाद में केन्द्र में चले गार और इम गुल को बनाने का काम वहीं का वहीं ही रह गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे ताकि लोगों को दिक्कत न हो, मेरे हल्के की डिबैल्पमैंट हो और गरीब आदमियों को सहूलियत भी हो । वहां पर न तो कोई हस्पताल है और न कोई शहर नजदीक है । लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी रहती है । इसलिये यह बहुत जरूरी है । एक पुल मारकंडा नदी पर बनना जरूरी है । अगर यह रुल बन जाए तो लोगों को इधर उधर जाने में बहुत सहूलियत होगी । अब खिजराबाद से बिलासपुर होते हुए चण्डीगढ आना पड़ता है जोकि लम्बा रास्ता है । इसलिये यह पुल जरूरी है । इसके साथ साथ मेरे हल्के मैं दो सब तहसीलें हैं । एक बिलासपुर है और दूसरी सढौरा है । बिलासपुर में शहर में बस अड्डा हौने की वजह से बहुत ऐक्सीडैट होते हैं और कई बार कुछ आदमी मर भी चुके है । जब कर्नल साहब ट्रांसपोर्ट मन्त्री थे तो इन्होंने बस अड्डे के लिए दो–तीन एकड़ जमीन अनाज मंडी के पास एक्वायर करवाई थी लेकिन अभी तक वहां पर बस अड्डा नहीं बना है । वहां पर पानी का भी कोई इन्तजाम नहीं है । मैं दरखास्त करूंगा कि अनाज मंडी के पास अड्डा बनना बहुत जरूरी

है उसे कन्दी बनाया जाए । सढौरा बहुत बड़ा कस्बा है और सब तहसील है उसको तहसील हैडक्वार्टर बनाया जग। । वहां का बस अड्डा भी शहर से बाहर निकाला जाए क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ रहती है । जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है, मेरे हल्के में काफी स्कूल अपग्रेड हुए हैं इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं । मेरे हल्के में गरीब आदमी रहते हैं । सढौरा में प्राइमरी से मिडल स्कूल किया है लेकिन वहां पर कमरे थोड़े हैं । बच्चे धूप में बैठते हैं । कुछ पैसा तो गांव वालों ने इकट्ठा किया है और अगर 20–30 हजार रुपया सरकार भी लगा दे तो वहां पर और कमरे बन सकते है । मेरा गांव किशनपुरा है जोकि छछरौली के पास है । वहां पर एक हाइडल प्रोजैक्ट की कालोनी बनी हुई है जिसके लिए हमारी जमीन ऐक्वायर की गई थी. । वहां पर एक रैस्ट हाउस भी है जोकि मेरे गांव से दो किलोमीटर है । उस कालोनी में 24 घंटे बिजली और पानी रहता है लेकिन मेरे गांव में न बिजली है और न पानी है । अगर मेरा गांव उस हाइडल प्रोजैक्ट की लाईन से जोड़ दिया जाए तो हमें बिजली और पानी मिल सकता है क्योंकि उस हाइडल प्रोजैक्ट कालोनी के लिए हमारी जमीन ऐक्वायर की गई है इसलिये उसके साथ जोडा जाना हमारा हक बनता है । इसलिये सरकार से दरखास्त है कि मेरे गांव को उस प्रोजैक्ट के साथ जोड़ कर बिजली और पानी दिया जाए । धन्यवाद ।

चौधरी कुन्दन लाल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किं आपने मुझे टाइम दिया । जिस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हू यह हरियाणा की तरक्की के लिए है । आज चाहे कोई गरीब आदमी है, हरिजन है, मजदूर है या बैकवर्ड क्लास का आदमी है इनकी तरक्की के लिए हमारी सरकार ने और मुख्य मन्त्री जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए. हैं । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने हरियाणा को सूरज की किरण की तरह से हिन्दुस्तान में उभारा है । अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगे रखूंगा । मैं डिमांड नं० 68, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 पर बोल्गा । डिमांड नं ० 6 पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब हरिजन, वीकर सैक्शन और पिछड़े लोगों की भलाई के लिए सरकार ने सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम की है । इसके लिए मैं सरकार का अभार प्रकट करता हूं । हमारी सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज और हरिजन कल्याण निगम के लिए काफी धन राशि रखी है जिसके लिए मैं बहुत आभरी हू । लेकिन कुछ बैंकों की वजह से हमारी तरक्की के अन्दर बड़ी भारी रुकावट है । चाहे किसान है, चाहे वीकर सैक्शन का आदमी है या बैकवर्ड क्लास का आदमी है इनको बैंकों से कर्जा लेने के लिए 3– 3 महीने तक चक्कर लगाने पड़ते हैं । निगम तो अपनी मार्जिन मनी का लोन पास कर देती है लेकिन बैंक वाले चक्कर कटवाते हैं । मैं हरियाणा में अगर किसी बात की कभी समझता हू तो वह बैकों से कर्जा लेने की है । इसके लिए हमारी सरकार को और मुख्य मन्त्री जी को सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि इससे हमारी बड़ी

भारी बदनामी होती है । बैक वालों ने अपने दलाल बना रखे हैं जिनके जरिए वे पैसा जाते है । बैंक वालों को जब तक दलाल जाकर नहीं कहता है तब तक वे लोगों के चक्कर कटवाते रहते हैं । कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो थक कर बैठ जाते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पिछड़े निगम को वने हुए पांच साल हो गए हैं । उस वक्त यह निगम लोगों को सीधा कर्जा देती थी । जो दस्तकार लोग थे चाहे वे किसी भी बिरादरी के थे उससे उन्होंने बड़ा भारी लाभ उठाया था । उस वक्त वे जितना कर्जा लेना चाहते थे उनको फौरन मिल जाता था । ऐसा होने से वे अपने कारोबार में जल्दी जुट जाते थे । आज क्या है, यह केवल पिछड़े वर्ग निगम की. ही बात नहीं बल्कि तीनों निगमों के साथ ऐसा हो रहा है । बैक वाले आज गरीब आदमी के साथ बड़ा अन्याय करते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जैसे पहले निगम द्वारा सीधा कर्जा दिया जाता था उसी तरह से अब भी दिया जाए ताकि लोगों को बैकों के चक्कर न काटने पड़े । गरीब लोग निगम से कर्जा ले कर अपनी दस्तकारी लगाएं और अपने बाल बच्चों का पेट पात्र सकें । इसी तरह से मैं अब सड्कों पर आता हू । मैं समझता है कि पी ० डब्ल्यू० डी० वालों ने मेरे हल्के में खास तौर पर बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं । इसके लिए मैं मन्त्री जी क धन्यवाद करता हु । लेकिन कुछ सड़कें अभी बहुत जरूरी हैं जो बननी चाहिएं । जैसे एक सड़क जीन्द रोड से सफीदों को जाती है । वहां एक गांव में सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि पहले सफीदों जाना पड़ता है और वहां से रताखेड़ा गांव में जाना पड़ता

है । रास्ते में सिर्फ एक किलोमीटर से कुछ ज्यादा का टुकड़ा है । अगर उसको मिला दिया जाए तो काफी रास्ता तय करना बच सकता है । वहां पर लोगों ने मिट्टी भी डाली हुई है और सब तरह से ठीक है । इसलिए अगर उस टुकड़े को पक्का कर दिया जाए तो दस किलोमीटर का रास्ता बच सकता है जिससे लोगों को फायदा हो सकता हे । डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से उटावडा से मीमनावाद का भी एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको भी पक्का किया जाना बहुत जरूरी है । इस रोड़ की चिकनी मिट्टी है जिसकी वजह से बारिश के दिनों में वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है । यदि कोई गाड़ी उधर से जाती भी है तो वह चिकनी मिट्टी में फंस जाती है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसे पएका किया जाये । इसी प्रकार से एक और सड़क है । यह सड़क भाई दयानन्द शर्मा के हल्के को औंर मेरे हल्के को आपस में जोड़ती ऐं । दोनों हल्कों के बीच में एक रोहडू गांव पड़ता है । इसे डेरा फत्तुकला बोलते हैं । इस रोड़. को वहां तक मिलाया जाये ताकि वहां के आदमी भी पक्के रोड़ का फायदा उठा सकें । इसी प्रकार से मैं पुरानी सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । पुरानी सड्कों की हालत बहुत खराब है । मेरे हल्के में पीलू खेड़ा की सड़क जो रेलवे क्रासिंग तक जाती है, बहुत खराब है । इसी प्रकार से भागडू–राना खडा की सड़क की भी बहुत खस्ता हालत है । इन सभी सड़कों की थोडी सी बारिश होने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती हे । इसी प्रकार से सफीदों बस स्टैण्ड से पानीपत रोड़ जो हे वह भी बहुत खराव हैं । पिछले

दिनों इस सड़क पर एक एक्सीडैन्ट में तीन आदमी मारे भी जा चुके हैं । मेरी मती जी से प्रार्थना है कि मेरे हल्के की जितनी भी सड़कें खराब हैं, उन सब को ठीक किया जाये । मैं शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हू कि उन्होंने मेरे हलके में कई स्कूल अपग्रेड किए हैं । मेरे हल्के के कुछ गांवों ने डेढ–दो लाख रुपये इकट्ठे करके स्कूलों की बिल्डिगें बनाई हैं । वहां पर भागखेडा गांव है जिसमें 8 वीं तक का स्कूल है उसे 10 वीं तक अवश्य अपग्रेड किया जाये क्योंकि उस गांव के आसपास किसी गांव में भी हाई स्कूल. नहीं है । आप को भी पता है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें पढने के लिए दूर नहीं भेजा उना सकता । गांव में बच्चों को देर तक पढ्ने के लिए बैठाया जाता है । गांवों की लड़कियां 10वीं तक 15– 16 सारन की हो जाती हैं इसलिए उनके मां बाप उन्हें द्र के गांवों में जो हाई स्कूल हैं, वहां पढ़ने के लिए न हीं भेजते जिसकी वजह से वें लडकियां 5 वीं या 8 वीं से आगे नहीं पढ पाती । इसी प्रकार से सिंवाना गांव वालों ने भी पौने दो लाख रुपये से स्कूल की बिल्डिंग बनाई है । यह स्कूल केवल लड़कियों का टे । मैं चाहुंगा कि सरकार इस स्कूल को भी 8वीं से 10 वीं तक अपग्रेड करे ताकि वहां की लडकिया आगे पद सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ की बात करना चाहूंगा । मेरे हल्के में सफीदों शहर के हस्पताल को 30 बैड का कर दिया गया हए । इसके लिए मैं मन्त्री जी का आभार प्रकट

करता हुं । इसी प्रकार से मुआना के अन्दर वहां के लोगों ने दो साल पहले 40 हजार रुपये इकट्ठे करके और 8 किल्ले जमीन इकट्ठी करके हैल्थ डिपार्टमंट को दो साल पहले दे दी है लेकिन अभी तक वहां पर डिस्पैन्सरी का काम शुरू नहीं किया जा सका है । मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां पर डिस्पैन्सरी का काम जल्दी से जल्दी मुख करवाया जाये । सफीदों के अन्दर आई ० टी ० आई ० खोलने के लिये जमीन दे दी गई है ले किन अभी – तदा आई ० टी ० आई ० चालू नहीं की गई है । मैं सरकार से अनुरोध करूगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी आई ० टी ० आई ० की विल्डिंग बना करके आई ० टी ० आई ० को चालू किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बस स्टैण्ड के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । वहां पर बस स्टैण्ड बनाने में बाई पास की दिक्कत का जिक्र नन्दी जी ने क्यैश्चन्ज आवर में किया है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर बाई पास बना कर वहां के बस स्टैण्ड के निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सफीदों के अन्दर कोई उद्योग नही है । जिस प्रकार से सरकार ने जीन्द शहर में उद्योग खोलने के लिए 15 परसैन्ट की ग्रांट देने का फैसला लिया है, उसी प्रकार से सफीदों शहर के लिए उद्योग खोलने के लिए भी. 15 परसैन्ट

की कि ग्रांट दी जाये ताकि वहां पर भी अधिक से अधिक इण्डस्ट्रीज लग सकें और वहाँ के लोगों को रोजगार मित्र सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सफीदों शहर में कोई हुड्डा की या हाउसिंग बोर्ड की कालोनी नहीं है । मैं चाहुंगा कि वहां पर कोई न कोई हुड्डा की तरफ से या किसी और की तरफ से कालोनी बनायी जाये। वहां पर अच्छे मकान न होने की वजह से वहां के आफिसर्ज को भी रहने में काफी दिक्कत आती है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सफीदों के अन्दर कोई आवास कालोनी और मिनी सैक्टर्ज बसाये जायें ताकि वहां के लोग भी अउछे–अच्छे मकानों में सारी सुविधाओ के साथ रह सके ।

चौधरी शकरूल्ला खां (फिरोजपुर झिरका) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेवात का इलाका हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । अब सरकार ने 7– 8 साल से वहां पर सराहनीय काम शुरू किए हैं । फिर भी मैं आपके जरिए कुछ मांगें क्हं के पूरिया के लोगो के लिए रखना चाहूंगा । मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी मागो पर महानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । उपाध्यक्ष महोदय. मैं तकरीबन सभी डिमांड्ज पर बोलना चाहूंगा । मेरे हल्के में सडको का काम हुआ है, उसके लिए मैं मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं । लेकिन एक सड़क के लिए मैं आगके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उने जल्दी में जल्दी बनाया जाये । यह सडक जमालगढ ने पुन्हाना सब्जी मण्डी तक बनाई जानी हु । यदि इन सडक को बनो दिया जाता है तो जो वहा पर हरिजन

वस्ती पड़ती है वह भी पक्की सडक में जुड़ जायेगा । इम सड़क को बनाने के लिए मार्किट कमेटी ने 2 लाख 54 हजार रुपये पी ० डब्ल्यू० डी ० के पास जमा भी किए हुए हैं । यह सडक बनाई जानी बहुत जरुरी है । में सरकार से रिक्वैस्ट करता हु कि इस सड़क को जितना जल्दी हो सके, पक्का बनाया जग' । इसी प्रकार से यूक सडक धीगा मनीहाबाद की है । यह सड़क हरियाणा ओर राजस्थान को आपस में मिलाती है । हरियाणा सरकार ने भी अपनी तरफ सैं मिट्टी डाल दी है और राजस्थान सरकार ने भी अपने एरिया में मिट्टी डाल दी है । इन दोनों –राज्यों के बीच यह जो सडक बनाई जा रही है, इसके पास एक गांव टोलर पड़ना है । मैं चाहता हूं कि हम सडक को वहा तक मिलाया जाये तो हरियाणा सें राजस्थान या राजस्थान से हरियाणा आने के लिये रास्ता बहुत छोटा हो जायेगा । मेरी मक्कार से प्रार्थना है कि इस तरफ ग्वाल ध्यान दिया जाये और इस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछेक बातें कहना चाहूंगा । मेवात में अभी तक कोई ऐसा हस्पताल नही है जहां पर वहाँ के लोग अपना इलाज अच्छी प्रकार से करवा सकें । पुन्हाना में एक बहुत पुरानी पी ० एच ० सी ० है । यह पी० एच० सी० भी झील में बनी हुई है । जब बारिश होती है तो वहां पर 3– 3 और 4– 4 फुट पानी खडा हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को पी ० एच ० सी ० तक आने जाने में

बहुत दिक्कत होती हैं । पुन्हाना कस्वे के लिए 30 बिस्तरों का एक हस्पताल जल्दी से जल्दी मन्जूर किया जाये । इसके लिए हमने 12 एकड़ जमीन भी स्वास्थ्य विभाग को दे दी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने मेरे हल्के के पिछोरा गांव को आदर्श गांव करार किया हुआ है । इन बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लासिज में कई बिरादरिया आती हैं । मेरे हल्के में एक बिरादरी सिक्का भी रहती है । अभी तक यह सिक्का बिरादरी बैकवर्ड क्लासिज में शामिल नहीं हुई है । जब इस जाति के लोग बैकवर्ड क्लासिज का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि सिक्का जाति बैकवर्ड क्लासिज में नहीं आती क्योंकि तुम्हारे दादा ने अढाई दिन राज किया था । इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मित्र सकता । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सिक्का बिरादरी को बैकवर्ड क्लासिज में शामिल किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक शुबह नहीं कि एस० वाई० एल० कैनाल का काम तेजी से चरन रहा है लेकिन उसका पानी यदि मेवात तक न पहुंचा तो दुःख होगा । मेवात के लोग आप जानते हैं काफी पीछे हैं । आज सारे हरियाणा में फसल अच्छी है, लोगों के रहने सहने का स्तर अच्छा है लेकिन

मेवात के इलाके में सूखा पड़ा हुआ है । उनकी दोनों ही फसलें नही हुई हैं । वे बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि वहां पानी नहीं है, नहर नहीं है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेवात नहर मेवात तक पहुंचाई जाए और इसका काम नवम्बर दिसम्बर तक पूरा किया जाए । मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि तिगांव माईनर जो मंजूर हो चुकी है और जिसके लिए पैसा मिल चुका है, का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेवात एरिया में काफी लोग पशु पालते हैं । वे गाय, भैस और मेड़–बकरी पाल कर अपना गुजारा करते है । वे दूध बेच कर अपनी आजीविका चलाते है । लेकिन वहां कोई पशुओं का हस्पताल नहीं है जिसमें पशुओं के बीमार होने पर उनका इलाज करवाया जा सके । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पशुओ के ज्यादा से ज्यादा हस्पताल खोले जाएं । इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि वन विभाग के कर्मचारी लोगों को भेड–बकरियां चराने नहीं देते । वे लोगों को जुर्माना करते हैं और पुलिस से तंग करवाते हैं । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेवात के –इलाके में भेड –बकरियों के चराने के लिए छूट दी जाए और– उनको पुलिस से भी तंग न करवाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं० 23 परिवहन के बारे में है । परिवहन विभाग अच्छा चल रहा है, इसमें शक शुबह नहीं है लेकिन फिरोजपुर झिरका सब–डिपो के बारे में मैं एक बात

कहना चाहता हूं । उसमें 196 बसें है लेकिन बड़ी मजबूरी में कहना पडता है कि जो बस हरियाणा के दूसरे हिस्से में खराब हो जाती है उसे फिरोजपुर झिरका डिपो में भेजा जाता है । एक बस वहां नई चली थी जिसका उदघाटन कर्नल राव राम सिंह जी ने किया था लेकिन अब वह भी बन्द कर दी गई है । मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के अधिकारियों से पता किया था और मुझे पता लगा है कि फिरोजपुर झिरका सब डिपो अच्छी आमदनी दे रहा है । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां ज्यादा से ज्यादा नई बसें चलाई जाए । पर्यटन विभाग की डिमांड के तहत, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हू कि एक पर्यटन केन्द्र मेवात में भी खोल दिया जाए ताकि वहां के लौंग भी उसका फायदा उठा सकें और उन्हें पता लगे कि इनमें खाने पीने की कैसी अच्छी चीजें मिलती हैं । गृह विभाग की मांग के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि फिरोज– पुर झिरका का थाना 1854 में बना था और आज उसकी हालत काफी खस्ता है । बरसात में वहां के कमरों में पानी भर जाता है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है और हवालात की भी बहुत गन्दी हालत है । उसको नया बनाया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका बोर्डर पर हैं । वहां थाने में जीप जरूर दी जाए ताकि कर्मचारियों की आने जाने की. दिक्कत मिट सके ।

अन्त में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री साहब से एके रिक्वैस्ट करूंगा कि भारत सरकार से रिक्वैस्ट

करके मेवात के इलाके में रेलवे लाईन जरूर निकाली जाए । वह इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ है । लोग वहां उद्योग भी नही लगाते क्योंकि आने जाने और मात्र लाने ले जाने कीं सहूलियत वहां नहीं है । हमारे मुख्य मन्त्री जी रेलवे विभाग के मन्त्री भी रह चुके हैं । मैं जब मन्त्री था तो हरियाणा सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा भी था और चौधरी बंसी लाल जी का जवाब भी आया था कि हम इस बारे में सोच विचार करेंगे । इन शब्दों के साथ, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिह सुरजेवाला) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन धमीजा साहब, जो हमारे एक सीनियर मैम्बर हैं, ने चूकि बिजली के बारे में और एस० वाई० एल० के बारे में एक बात कही थी इसलिए मैंने हाउस का समय लिया । उन्होंने अम्बाला में खास कर दस्तकारी के क्षेत्र में बिजली की कमी की शिकायत की । अम्बाला कैन्ट और अम्बाला सिटी का एरिया धूलकोट के 220 के० वी ० सब स्टेशन, अशोका के 66 के० वी ० सब स्टेशन और आई० ओ० सी ० के 66 के०वी० सब स्टेशन से फीड होता है । 22० के०वी ० सब स्टेशन धूलकोट का कन्ट्रोल बी० बी ० एम० बी ० के पाम है । जब पूरे रीजन में बिजली की समस्या आती है, खास तौर पर जब डेसू ओवर डा करता है, तब कट लग जाता है । फिस्वैन्सी कट अनशड्यूल्ड होता है । कई बार बिजली एक दो

मिनट से ज्यादा अमी तक भी चली जाती है । दो महीने पहले वहां काफी प्रौब्लम रही है । इस वात की मुझे इनसे हमदर्दी है । लेकिन इस दौरान बिजली बोर्ड ने बहुत कोशिश की है । बी ० बी० एम० बी ० से भी मामला टेक अप किया गया औह डेसू और गवर्नमैंट औफ इंडिया से भी मामला टेक आर किया गया जिसकी वजह वे अब बिजली की सप्लाई काफी अर्सा से ठीक है और जो फिक्वैन्सी कट लगता था वह नहीं लग रहा है । इम प्रौब्लम को मौल्व करने के लिए हरियाणा बिजली बोर्ड ने पूरी स्टेट में जगह जगह 220 के० वी ० सब–स्टेशनज बनाने का प्रोग्राम बनाया है । 220 के० वी० सब स्टेशन करनाल बन कर चालू हों चुका है । नरवाना 22० के० वी० सब– स्टेशन साल–डेढ़ साल पहले वन गया था । मार्च–अप्रैल तक कैथल मैं बन जाएगा । शाहबाद, कुरुक्षेत्र और दूसरी जगह पर भी सब–स्टेशन्ज बनाने का प्रोग्राम है और इसके लिए जल्दी से कार्यवाही कर रहे है । जैसे–जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे कन्ट्रोल में आएगा, इन प्रकार की प्रौब्लम नही आएगी । जहा तक अम्बाला की इंडस्ट्रीज को बिजली की सप्लाई का सवाल है, उसकी फिगर्ज मैं अप्रैल, 86 से जनवरी, 1987 तक के पीरियड की हाउस को बताना चाहूंगा । लोगों का ख्याल है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल शिरया को सबने ज्यादा बिजली मिलती है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला फरीदाबाद के बहुत नजदीक है जहां तक इंडस्ट्रीज में बिजली की कंजम्पशन का सवाल है । कई महीनो में तो अम्बाला को फरीदाबाद से भी ज्यादा बिजली. की सप्लाई मिली है । अप्रैल

1986 में अम्बाला की इंडस्ट्रीज को एक दिन में 12.06 लाख यूनिट्स बिजली मिली, मई, 1986 में 11.66 लाख यूनिटस, जून, 198 अ मे 12 44 लारब यूनिटस जुलाई, 1986 में 13.30 लाख यूनिटस, अगस्त, 1986 में 13.11 लाख यूनिटस, सितम्बर, 1986 मे 11.73 लाख यूनिटस अक्तूबर, 1986 में 11.32 लाख यूनिटस, नवम्बर, 1986 में 10.24 लाख यूनिटस, दिसम्बर, 1986 में 11.03 लाख यूनिटस और जनवरी, 1987 में 10.03 लाख यूनिटस बिजली रोज मिली । अगर फरीदाबाद केआंकडे ये जानना चाहे तो वे भी मैं बता देता हु । फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज को अप्रैल, 1986 में 15 लाख यूनिटस, मई, 1988 मे 18 लाख यूनिटस जून, 1986 ने 1 5 लाख यूनिट्स जुलाई 1986 में 16 लाख यूनिटस, अगस्त, 1986 में 13 लाख यूनिटस, सितम्बर, 1 988 में 10 लाख यूनिटस, अखबर, 1986 में 12 लाख यूनिटस, नवम्बर, 1 986 में 11 लाख यूनिटस दिसम्बर 1986 में 11 लाख यूनिटस और जनवरी, 1987 में 9 लाख यूनिटस बिजली रोज मिली ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला कैन्ट और अम्बाला सिटी में हर घर में इंडस्ट्री लगी है और वे लोग पावर के अलावा डोमैस्टिक यूज के लिए जो बिजली मिलती है उसको भी यूज करते हैं । कानून कायदे के मुताबिक इसमें थोडी बहुत अड़चन है लेकिन सरकार यह सोच कर कि इतने बडे पैमाने पर चूंकि छोटे–छोटे परिवार काम कर रहे हैं कोई आपत्ति इस बारे में नहीं उठाती । तो डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा बै उम्मीद

यह है कि आने वाले समय में बिजली की सप्लाई में काफी सुधार होगा क्योकि बिजली बोर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए काफी रुपया खर्च कर रहा है और अगले साल के लिए भी इम काम के लिए उन्हें काफी रुपया दिया गया है । उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कहा, वह यह है कि जब तक एस० वाई० एल० को केन्द्र सरकार अपने हाथ मे नही लेगी तब तक उनकी तसल्ली पूरी तरह नही होगी । ऐसा कह कर वे वाजह तौर पर लोगो की तरजमानी कर रहे है । जब से यह सरकार बनी द्रुँ, तभी से हुस बात को विलेय प्राथमिकता दी जा रही है कि एस० वाई० एल० का काम भारत सरकार अपने हाथ में ले । इम प्रयास का यह नतीजा हुआ कि भारत सरकार ने एस० वाई० एल० का सालम खर्चा अपने जिम्मे ले लिया है । यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मील पत्थर है कि एम० वाई० एल० का खर्चा केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिया, सरकार को उम्मीद थी कि एस० वाई० एल० का काम भी भारत सरकार जल्दी ही अपने हाथ में ले लेगी लेकिन लोकदल की तीन मैम्बर्ज कमेटी ने हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड किया । लोक–दल की इस कमेटी ने पब्लिकली यह वात कह कर कि एस० वाई० एल० का काम सन्तोषजनक है और इमे भारत सरकार के अपने हाथ में लेने से नुक्सान होगा राजनैतिक तौर पर प्रेरित हो कर हरियाणा सरकार का अहित किया है । मैं आपके माध्यम से हाउस को बनाना चाहूंगा कि ज्यों ही इराडी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश होगी., हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस काम को अपने हाथ में ले लेगी । इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट

तीनों सरकार को कमी भी आ सकती है । यह रिपोर्ट पार्लियामैंट की टेबल पर भी रखी जायेगी । दूसरी बात इन्होंने यह कही कि इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला तो आ चुका है और जो भी फैसला होगा वह हमें मानना होगा । जो भी पानी हमें मिलेगा वह लेना होगा । इनके ये शब्द मायूसपूर्ण थे जिनकी वजह से मैंने यह समझा कि उनका स्पष्टीकरण करू ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सदन और लोगों की रोशनी में नई आयी कि इराडी ट्रिब्यूनल का गठन हुआ वह राजीव लौंगवाल ऐग्रीमैंट की बिना पर हुआ था । हरियाणा में यह आवाज बार बार उठाया गई कि फैसला करते समय किसी भी स्टेज पर हरियाणा को कंसल्ट नहीं किया । यह शिकायत हरियाणा की जनता को भी थीं । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।) राजनैतिक तौर पर प्रेरित हो कर चौधरी देवी लाल ने और लोकदल के दूसरे लोगों ने शुरू से ही इस प्रकार का प्रचार किया ताकि हरियाणा सरकार और हरियाणा के अधिकारी जो –इस काम में लगे हुए है, उनका मनोबल गिरे और जो प्रयत्न वे लोग कर रहे हैं, वे न करें । इन लोगों ने कहा कि हरियाणा को 1 –7–8 5 को जो पानी मिलता था उससे फालतू पानी नहीं मिलेगा । इन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा ने अपने केस को खो दिया है । वे यह प्रचार निरन्तर प्रैस और पब्लिक प्लेटफार्म पर करते रहे । बड़े दु:ख की बात है कि उन्होंने ऐसी बात कही । स्पीकर साहब, कहां के अधिकारी, कर्मचारी, वकीलों की टीम या जो भी इस काम

में जुटे हुए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत, ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के साथ केस तैयार करके ट्रिव्यूनल के सामने पेश किया । As a result of this, tables were turned adversely on the3 other side. आपने देखा होगा कि जैसे जैसे केस प्रौसीड हुआ हमारे दूसरे पक्ष ने कई दफा कोशिश की कि ट्रिब्यूनल से रीगल आउट हो जायें । काफी ऐवीडैन्स आने के बाद उन्होंने देखा कि रिक्मैन्डेशन्ज उनके खिलाफ जायेंगी और हरियाणा के हक में जायेगी तो चौधरी देवी लाल ने उस समय कहना शुरू किया कि हरियाणा को पानी पूरा तो मिल जायेगा और शायद फालतू भी मिल जाये लेकिन पानी हरियाणा में नहीं पहुंचेगा । दूसरे जो हमारे पंजाब के लोग थे उनमें भी कई ऐसे फ्रैक्शन थे जो ट्रिव्यूनल का बाईकाट करना चाहते थे । स्पीकर साहब, अभी भी जूरी की रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन हम पूरे यकीन के साथ यह बात कह सकते हैं कि जो केस हमने तैयार किया है, आंकडे दिये हैं, सबूत पेश किये हैं और लीगल प्वायंट्स सिक्योर किये हैं, उसके हिसाब से हरियाणा को पूरा हक मिलेगा । हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा पानी मिलेगा । इसके अलावा जो इराडी ट्रिब्यूनल की इन्टर–स्टेट प्रौसीडंग्ज हुई हैं, उनके बारे भी मैं बताना चाहूंगा । यह ट्रिब्यूनल 2–4– 1988 को इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट, 1956 के तहत कांस्टीच्यूट हुआ । इस कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बाल कृष्ण इराडी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जब हैं । केरल हाई कोर्ट के जब थी पी ० सी ० बालाकृष्णा मैनन और जस्टिस ए० एम ० अहमदी गुजरात हाईकोर्ट के जज इस ट्रिव्यूनल

के मैम्बर थे । हरियाणा की टीम में सब से योग्य कौंसिल श्री एन० ए० पालकीवाला थे जो हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध जुरिस्ट हैं । उन्होंने हमारे केस में कोई पैसा चार्ज नहीं किया । हमारा केस फ्री लड़ा । दूसरे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर ऐडवोकेट छपी कपिल सिब्बल हें जो कि पालकीवाला की गैरहाजरो में कमीशन के सामने पेश होते थे क्योंकि हर तारीख पर वे नहीं जा सकते थे । सीनियर कीसिल होने के नाते से उन्होंने केस तैयार किया । श्री जी० एल० साली और श्री एस० के० मेहता भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं । इन्होंने भी रिकार्ड तैयार कराने में हमारी मदद की । इस प्रकार से जो भी अफसर थे उन्होंने इस केस को तैयार करने में लगभग एक साल का समय लगाया । श्री ए० एन० मल्हौत्रा रिटायर्ड इंजीनियर–इन चीफ क्रो ऐडवाइजर के रूप में रखा गया । इसके अलावा श्री ए० आर० सेठी, चीफ इंजीनियर, मिस्टर के० सी ० शर्मा, एस० ई०, मिस्टर वी ० पी ० वोहरा, ऐक्सीयन, मिस्टर गुप्ता तथा और भी स्टाफ टैक्निकल साइड से था । अध्यक्ष महोदय इन्होंने रोजाना दिन रात मेहनत करके और अपने सुख को छोड़ कर इस केस की तैयारी में समय लगाया । इस केस को तैयार करने में फील्ड के अफसरों का मी काफी हाथ था । ला डिपार्टमैंट के श्री ए० पी ० चौधरी तथा आर्ड) पी ० वशिष्ट भी शामिल थे । इन्होंने भी पूरी तरह हिस्सा लिग और सरकार की पूरी मदद की । श्री बी ० पी. ० चौहान हैड आफ दि हिमाचल या यूनिवर्सिटी जो कि स्पैशलिस्ट आन इन्टरनेशनशल वाटर ला डिसप्यूटस हैं, उनको भी हमने ऐन्गेज किया । फाइनैंशियल

कमिशनर श्री एम० सी. ० गुप्ता ने भी बहुत सा समय ट्रिव्यूनल की सीटिंग्ज अटैन्ड करने और केस को तैयार करने में लगाया । हमारी सरकार ने जो केस पेश किया उसके 37 वौल्यूमज हैं और जो जवाब दावा पेश किया है उसके 2700 पेज हैं । उन वौल्यूमज की 38 कापियां तैयार करवानी पड़ी । इनमें सात क्वींटल के करीब वजन था जिसमें नक्शे वगैरह भी शामिल थे । ट्रिव्यूनल की टोटल 44 सीटिंग्ज हुई । हमारे वकील, आबकारी रोडवाइजर और दुसरे जो लोग थे, उन्होंने मेहनत से और जिस डैडीकेशन के साथ काम किया, उसके लिये हरियाणा सरकार और जनता को उनकी ऐप्रीसिएशन करनी चाहिए और हमें उनका धन्यवादी होना चाहिये । इन्ही लोगों कीं मेहनत का यह नतीजा था कि अपने केस की फाउन्डेशन को मजबूत बनाया । जब भी कभी इराडी कमीशन की रिपोर्ट छपेगी, हरियाणा को पूरा अधिकार मिलेगा और जो हमारे राजनैतिक तौर पर विरोधी हैं उनकी भी यह राय है कि इन लोगों ने बहुत अपादा मेहनत की । इसलिए हमें पूरा हक मिलेगा और पहले से ज्यादा पानी मिलेगा । मैं यह बात हाउस को बताना चाहूंगा कि कोई वजह मायूसी की नहीं है । इराडी ट्रिब्यूनल से हरियाणा को पूरा इन्साफ मिलेगा और एस० वाई० एल० नहर जल्दी से. जल्दी कंस्ट्रक्ट होगी, इसका हरियाणा को पानी मिलेगा । इन सारी बातों का सेहरा श्री राजीव गांधी, हमारे मुख्यमन्त्री हरियाणा सरकार और इस सारे हाउस को तथा हरियाणा के लोगों को मिलेगा, जो इस बात में दिलचस्पी रखते हैं ।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री फूल चन्द) : आदरणीय. अध्यक्ष महोदय, मांगों पर चर्चा करते हुए लगभग सभी सदस्यों ने नयी सड़कों की मरम्मत की और स्कूल बिल्डिग्ज की चर्चा की । वैसे तो मैंने आज एक सवाल के उत्तर में. जवाब दिया है कि सरकार कीं नीति प्रायरिटी टू रिपेयर औफ रोडज की है । सारे प्रान्त में सर्वे करवा कर नीड बेस्ड यानी जिन सड्कों की मरम्मत होनी बइत जरूरी है, उन सड्कों की मरम्मत करवायी जायेगी । जहां तक अध्यक्ष महोदय, नयी सड़कें बनाने का सवाल है, नयी सड़क का हर एक केस अलग से देखा जाता है और बजट में रुपये पैसे के प्रोविजन के अनुसार उस सड़क को प्रायरिटी दी जाती है या काम शुरू किया जाता है । हमारे माननीय सदस्य भले राम जी ने एक दो ऐसी सड़कों का जिक्र किया जहां पर गांव वालों ने तिहाई का काम किया हुआ है । उन्होंने यह भी कहा कि वहां पर जमीन का मुआवजा देने की भी बात नहीं है । ऐसी सड्कों को विभाग खास तौर पर दिखवायेगा और उनको प्रायरिटी भी देगा । इसके अलावा कुछ स्कूलों की बिल्डिंग्ज की मुरम्मत के बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि उनकी मरम्मत नहीं हुई है । वह हम देखेंगे । अगर शिक्षा विभाग की ओर से उनकी मरम्मत का पैसा जमा है तो उनकी मरम्मत हम बहुत जल्दी करवा देंगे । उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्कुल्ज की बिल्डिग्ज को पी ० डब्ल्यु० डी ० द्वारा टेक ओवर कर लिया जाये । उसके बारे मे जैसे कि सभी सदस्य जानते हैं कि जैसे बस स्टैण्ड ट्रांसपोर्ट के है और स्कूल शिक्षा विभाग के है, और पी ० डब्ल्यू० डी० उन्हें

तभी मेनटेन करता है या बनाता है जब सम्बन्धित विमाग से पैसा आता हैं । हम सम्बन्धित विभाग को लिखेंगे औररू उनकी ओर विशेष ध्यान दिश जायेगा । मैं सदन क्एरू सभी माननीय सदस्पों जिन्होंने अगने अपने क्षेत्र की मांगों की चर्चा की है, का आभारी हू कि उन्होंने अपनी मांगों को सदन में हाई लाईट किया है । यहा पर काफी सारे पुलों की बात भी आयी । माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत सारे पुल राज्य में वन रहे हैं और बहुत सारे पुलों की रूप रेखा भी बनाई जा रही है । यह सब, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि रुपये पैसे पर निर्भर करेगा । रुपये पैसे की स्थिति ठीक होगी तो सभी कामों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । फिलहाल मरम्मत को प्रायरिटी दो जा रही है । धन्यवाद ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में डिमांड्ज मंजूर कराने के लिये जो चर्चा हुई, उसमें डिमांड्ज पर किसी को कोई आपत्ति नही है । सदस्यों ने अपने क्षेत्र की या अपनी कास्टिचुऐंसीज की प्रौब्लम्ज और कामों को हाईलाईट किया है । उनकीं मांग है कि उनके लिए पैसा रखा जाये या उनके लिये प्रोविजन किया जाये या उनकी तरफ ध्यान दिया जाये । मैं इन्हीं बातों का जवाब देने की मुख्यतः कोशिश करूंगा । जिन बातों का नहीं. दे पाऊंगा उनके लिये विभाग के अधिकारी सभी बातों को नोट करते हैं और उस बारे में हम उचित कार्य– वाही करने की कोशिश करेंगे । इन डिमान्ड्ज पर श्री भले राम जी ने बहस शुरू की । राम सिंह जीं, हमारे साथी अजमत

खां, लीला कृष्ण जी, धमीजा साहब, प्रभु राम, कुन्दन लाल और शकरूल्ला जी वगैरा ने चर्चा की । भले राम जी ने सबसे पहले बोलते हुए रैवेन्यू विभाग के बारे में जिक्र किया कि आजकल पटवार– खानों की कमी है । पटवारी ऐसी जगहों पर बैठते हैं जो कन्ट्रोवर्शीयल जगह होती है । सभी लोग वहां पर जा नहीं पाते । इस तरह से कुछ भ्रष्टाचार होता है । उनका बहुत अच्छा सुझाव है । इसमें दिक्कत यह है कि पहले पटवार खाने हुआ करते थे । वह खत्म हो गये । उनकी तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया । इस सुझाव पर हम विचार करेंगे । एजुकेशन के बारे से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्र की मांग रखी । मेवात एरिया में कालेज की माग की गयी और यह कहा गया कि वहुत दूर–दूर तक बच्चों को और खासकर लड़कियों को जाना पडता है । रादौर हल्के मे भी यह मांग आयी और अम्बाला कैट से भी गवर्नमैंट कालेज खोलने की माग की गयी । कुछ मिडल स्कूल की डिमाडज नीलोखेडी क्षेत्र की भी आयी । अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ ने यूक ब्यौरो मदन में दिया गया था कि अगले माल में शिक्षा विभाग 100 नये प्राइमरी स्कूल मोस्टली लड़कियों के लिये और 100 प्राइम स्कूल मै मिडल स्कूल बनाने के लिये प्रोविजन कर रहा है । इसके अलावा 50 मिडल स्कूल वे हाई स्कूल गौर 25 सीनियर सैकंडरी स्कूल (10 प्लस 2) बनायेगा । उनके कुछ नार्म्ज हैं जिनमें– बच्चों की तादाद और कमरों का या बिल्डिंग का होना जरूरी होता है, उस हिसाब से विभाग देखता है । जिन लोगों से और जिन क्षेत्रों से ये मांग आयी हैं, उनके लिये

जांच पड़ताल की जा रही है । जहां पर 'भी यह मांग सूरी हो सकती है, वह– आने वाले साल मैं पूरी की जाये गी । अस्पतालों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई । कहीं पर डाक्टर नही है, कहीं पर दवाइयों की कमी है । इसक्एरू अलावा और ज्यादा पी ० एच० सीज० खोलने की खास तौर पर मांग जगह–जगह से आयी कि नयी पी ० एच० सीज० बनाई जायें ।

इसके लिये अब कुछ पैसों का प्रोविजन आने वारने साल में किया गया है जिसमें कुछ पी ० एच० सीज० और सब–मैटर्ज बनाये जायेंगे । जहां पर डाक्टर्ज की कमी है वहां पर उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जायेगी । एक मांग अम्बाला कैट के बाहए में यह आयी कि 75 बैड का वहा पा जो बड़ा पुराना अस्पताल है, त्तको 100 बैड का किया जाये, इस पर भी गौर जायेगा । इसी तरह से सफीदों मे 30 बैड का जो अस्पताल सैक्शन कर दिया गया है और उस पर काम भी शुरू हौ चुका है, उसके बारे मे यह कहा गया कि उमकी जल्दी से पुरा किया जाये । मैं यह कहूंगा कि अगर काम शुरू हो चुका है तो उस पर काम तेजी से ही किया जायेगा । आंगनवाडियो की और हरिजन चौपाल्ज की बात भी यहां पर आयी । चौपाल्जं के लिये इस माल काफी पैसा दिया गया तैं । डिसैट्रेलाइज्ड प्लानिंग में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया इसके लिये दिया गया । इसी साल में 84 लाख रुपया और दिया गया । 16 लाख रुपये का नौमंली इसके लिये प्रोविजन होता था । इस वजह से इस सात्र

हमने 2 करोड़ 10 लाख रुपया दिया है जबकि नौर्मली इसके लिये एक साल में 15– 16 लाख रुपया ही रखा जाता था । आप देखें कई गुना ज्यादा पैसा इस काम के लिये दिया गया हए । अगले माल में भी डिसैंट्रेलाईजेशन प्लानिंग से यह रियायत दी गयी है कि 6 करोड़ रुपया जो इसके लिये रखा गया है उसका वन–फिफ्थ इस काम के लिये दे दिया जायेगा । इसको प्रायरिटी दी जायेगी । इससे काफी काम हो जायेगा । ऐनीमल हस्वैडैरी की डिस्पैसंरियों की मांग भी की गयी । नई डिस्पैसरियां खोलने के लिये भी इन बजट में प्रोविजन किया गया है । जहां पर जरूरत है, वहां पर मैरिट के हिसाब से खोलने की कोशिश की जायेगी । टूरिस्ट काम्पलैक्सिज की मांग भी यहां पर आयी । गोहाना में और फतेहाबाद में भी टूरिस्ट काम्पलैक्स खोलने की मांग की गयी । जहां पर भी जरूरत है, वहां पर बनाने के लिये गौर किया जायेगा । इसके अलावा लोन्ज के बारे में भी कहा गया । मैं समझता हूं कि इसमें काफी हार्डशिप है । मेवात एरिया में और ड्राउट एरियाज में हम बिजली भी किसानों को नहीं दे पाये । लोगों को लोन भी नहीं मिलता । हम इसको एग्जामिन करेंगे और इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेगे । स्पीकर साहब, एक मांग यह की गई कि जो बैकवर्ड क्लासिज निगम है वे लोगों को सीधा कर्जा दे दे बैकों से न दिलवाएं । लोगों को सीधा कर्जा देने का प्रावधान होना चाहिए । स्पीकर साहब, पैसे की कमी की वजह से यह नहीं हो सकता, बैकों का सहारा लेना पड़ता है । चौधरी लीला कृष्ण ने कहा कि फतेहबाद को पैडी एरिया घोषित

किया हुआ है लेकिन उसको इम्पलीमैंट नहीं किया । स्पीकर साहब, इसको भी देख लेंगे ।

13.00 बजे ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, आलरेडी फतेहाबाद और सिरसा पैडी एरिया डिक्लेयर किए हुए हैं ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, इस बारे में हम हिदायत दे देंगे । नीलोखेडी में पी० एल० डी ० बी० की बिल्डिंग के बारे में बात कही गई । स्पीकर साहब, बिल्डिग तो बैक ही बनाता है । स्पीकर साहब, बाकी जनरल बातें कही गई कि शहरों की सड़कें खराब हैं । इस बारे में पी ० डब्ल्यू० डी ० मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है । कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रिपेयर वगैरह पर लगाया जाए और इस काम को काफी प्रायरिटी दी जा रही है । अम्बाला कैन्ट में एक सिविल एयर पोर्ट बनाने के– बारे में जिक्र किया गया । स्पीकर साहब, इस समय इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि क्या स्थिति है । इस पर गौर करेंगे और जरूरत होगी तो बना देंगे । अम्बाला कैट में हुड्डा की कालोनी बनाने की मांग की गई है । इस बारे में विस्तार से मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर हुड्डा की कालोनी डिवैल्प करेंगे । चौधरी अजमत खां ने पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में कहा कि वह ठीक

नहीं है उनके व्यवहार को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं । सीकर साहब, काफी हद तक यह बात ठीक है और सारा देश इस बात से पीड़ित है । कई जगहों पर इस तरह के वाक्यात होते हैं । भारत सरकार ने इस बारे में एक गोरे आयोग बनाया था । उसने कुछ सिफारिशें की थीं । उन सिफारिशों के तहत कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक को ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि वे ठीक व्यवहार करें । अच्छे व्यवहार के लिए रिओरिएन्टेशन कोर्स का इन्तजाम भी करते हैं । एक मैम्बर ने कहा कि विजिलैसं और सी० आई० डी ० के विंग डिफरैन्ट होने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार न बढ़े । इस समय ये पुलिस के अण्डर ही आते हैं इसलिए वे ज्यादा इफैक्टिव नही है इसलिए इनका सैपरेट विंग होना चाहिए । स्पीकर साहब, विजिलैसं में जो लोग लाए जाते हैं वे अच्छे करैक्टर के लाए जाते हैं । जिन लोगों की सी० आर० अच्छी होती है और जिनके खिलाफ कोई डाउटफुल रिपोर्ट नहीं होती, उन्हीं को लिया जाता है । सी० आई० डी ० के कर्मचारी डायरैक्टली डी ० जी ० पी ० के अण्डर फइशन करते हैं । इन पर विशेष दबाव नहीं दुाएता । स्पीकर साहब, एक मांग यह की गई कि फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना की थाने की विल्डिग्ज बहुत पुरानी हैं इनको ठीक किया जाए और नई बिल्डिंग्ज बनाई जाएं । स्पीकर साहब, यह ठीक है कि सारे प्रदेश में थानों की बिल्डिग्ज खराब और जर्जर हैं । हम नई विल्डिग्ज बनाने की और कुछ को रैनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पीकर साहब, मेवात में रेलवे लाइन की माग की गई । उन आनरेवल मैम्बर साहब ने खुद ही बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और भारत सरकार से उनको जवाब भी आया था । चौधरी लीला कृष्ण ने फतेहाबाद में टूरिस्ट कौम्प– लैक्स बनाने की बात की । स्पीकर साहब, हम मैरिटस पर देखते है और जहां जरूरत होती हैं वहां बनाते हैं । यहां पर दादूपुर नलवी प्रोजैक्ट का भी जिक्र आया और इस बारे में स्पैसिफिक क्वैश्चन भी पूछा गया । इस बारे मैं विस्तार से बता दिया गया है । इस साल इस प्रोजैक्ट के लिए डेढ करोड़ रुपया रखा है । यह प्रोजैक्ट अठाईस 'करोड़ से ज्यादा का प्रोजैक्ट है । इसी पंचवर्षीय योजना में जो साल बाकी रह गए हैं उसमें इसको पूरा करेंगे । यह पैसा थोड़ा है । सरकार की कोशिश है कि बाकी तीन साल में पूरा पैसा दिया जाए । सरकार नहर, माइनर और नए प्रोजैक्ट बनाने पर काफी पैसा खर्च कर रही है । यह प्रोजैक्ट इसलिए शुरू नहीं हो सका कि जमीन ऐक्वायर नहीं हुई । यह कोई प्लौजिबल ऐक्सक्यूज नहीं है । दो साल पैसा पडा रहा लेकिन जमीन ऐक्वायर नहीं हुई । मन्त्री जी खुद देखें कि जमीन ऐक्वायर क्यों नहीं हुई और यह ढील क्यों हुई?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इसमें एल० ए ० ओ० की अप्वायंटमैट नहीं हुई थी इसलिए जमीन ऐक्वायर नहीं हो सकी ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : जो एल० ए० ओ० लगाया जाता है वह एच० सी० एस० होता है और उसको गवर्नमैंट ही लगाती है । स्पीकर साहब, यहां यह मांग हुई कि जमुना और दूसरी नदियों पर प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए पैसा क्यों नही रखा जाता । जब बरसात शुरू होती है तो काम शुरू किया जाता है और वह बरसात में बह जाता है । स्पीकर साहब, इस बात में काफी वजन है । इस पर सरकार गौर करेगी कि समय रहते काम शुरू किया जाए । क्योंकि फ्लड कमेटी होती है इसलिए विलम्ब हो जाता है । वैसे तो फ्लड कन्ट्रोल के लिए हर साल तेरह चौदह करोड़ रुपया रखा जाता है लेकिन पिछले सालो ये कुछ पैसा चूकि एस ० वाई ० एल ० की तरफ डाइवर्ट होता रहा इसलिए दिक्कत आई । अब आगे दिक्कत नहीं आएगी । चौधरी लीला कृष्ण ने रंगोई नाला का जिक्र कया और साथ हो साथ फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का भी जिक्र किया । इसके लिए दस लाख रुपया रखा है । यह सैकिण्ड फेज में पूरा किया जाएग। अम्बाला कैट, सढौरा और बिलासपुर ने बस अड्डे की मांग की गई । जैसा कि ट्रांसपोर्ट मि निस्टर साहब ने बताया है कि सढोर और बिलासपुर के बस अड्डे अण्डर कंसीडेरशन है । अम्बाला कैट में जमीन ऐक्यायर हो चुकी है और एक सवाल के जवाब में भी बताया था कि उस जमीन में फिलिग हो रही है और इसको जल्दी ही बना दिया जाएगा ।

स्पीकर साहब, चौधरी अजमत खां ने एक बहुत अच्छी मांग की कि मेवात एरिया में टैक्नीकल ऐजुकेशन की कमी है । वह बैकवर्ड एरिया है । वहां एक टैक्नीकल इंस्टीव्यूशन बहुत देर से मन्जूर हुआ पड़ा है लेकिन वह बन नही रहा है । स्पीकर साहब, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उटावड में पीली – टैक्नीक खोलना मान लिया गया है । इसके नयू इस ऐनुअल प्लान मे यानी 1987 – 88 में बीस लाख रुपया रखा गया है । नक्शे वगैरह बनवाए जा रहे है । इसी तरह से नए माइनर्ज की माग की गई । इन बारे में आई ० पी ० एम ० साहब ने बताया है कि नई माडनर्ज बना रहे हैं जहा जरूरत है और जो इन कम्पलीट हैं उन पर भई ध्यान दिया जा रहा एं । स्पीकर साहब, ड्रेनेज वर्क्ज पर भी ध्यान दिय जा रहा है । स्पीकर साहब. ड्रैज माइनर्ज डिस्ट्रीब्यूटरीज पर पुल वगैरह की सारी मांगें नोट कर ली हैं और इन के बारे में पूरा ध्यान दिया जाएगा । फतेहाबाद के बारे में कहा गया कि वहां पानी में कुछ गांव डूबे हुए हैं । अगर वहां देर न बना दी जाए तो वह पानी निकल सकता है और वहां काश्त हो सकती है । स्पीकर साहब । इसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे । तरावडी में एक सब–स्टेशन की मांग की गई । इसको ऐक्सपीडाइट करवाएंगे । इसी तरह से बबैन में एक 33 के ० वी ० का सब–स्टेशन है उसको 66 के ० वी ० का सब–स्टेशन बनाने की मांग की गई । स्पीकर साहब, उसको भी इसी ऐनुअल प्लान में रख रहे हैं और आने वाले साल 1987 – 88 मैं उस पर काम शु रू कर दिया जाएगा । स्पीकर साहब, यह कहा गया कि

अम्बाला में बिजली की कमी है । हम अम्बाला को जगाधरी, धूलकोट और हिमाचल से भी बिजली दे रहे हैं । जहां से भी इजी ली बज ली अबे लेबल होता है, वहां से देते हैं

स्पीकर साहब, एन ० आर ० ई ० पी ०, आर ० एल ० ई ० जी ० पी ० स्कीम्ज के लिए ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए! यह मांग यहां पर कीं गई । अध्यक्ष महोदय । मैं सदन को बताना चाहता है कि आई ० आर ० डी ० पी ० के तहत 6.74 करोड़ रुपया रखा है, एन ० आर ० ई ० पी ० के तहत 447 करोड़ रूपया रखा है और आर ० एल ० ई० जी ० पी ० के तहत 5.50 करोड़ रुपये रखे हैं । इस तरह से इन स्कीम्ज के तहत 16.71 करोड़ गाया रखा गया है । स्पीकर साहब, इसमें भारत सरकार की ओर सें कंट्रीव्यूशन भाती हैं । जितना पैसा वहां से मन्जूर होता है उतना ही हमें कंटीव्य्ट करना पड़ता है । अगर अपनी ओर से हम यह काम करें तो पूरा खर्चा हमें करना पड़ेगा । जितना पैसा है उससे काफी जरूरत पूरी हो रही. है कोई खास दिक्कत नही है । इसी तरह से कुछ ऐनीमल हस्बैन्डरी की डिस्पैन्सरियां खोलने का भी यहां पर जिक्र आया इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि आने वाले साल में इमके लिये बजट में काफी प्रावधान किया जा चुका है और जहां पर आवश्यकता होगी, वहां हम खोल देंगे । मास्टर राम सिंह जी ने– भूनाखेडी में इसके लिये जोर दिया है । इस बारे अगर हो सका हम अगले साल देखेगे तेकिन दो जगहों नूह और फिरोजपूर झिरका में 1987– 88 में दो

डिस्पैन्सरियां बनाने के लिये पैसा रखा गया है, मन्जूर किया गया है ।

स्पीकर साहब, अम्बाला टाउन को बैकवर्ड एरिया घोषित करवाने के लिये धमीजा साहब ने कई बार कहा कि अम्बाला को बैकवर्ड एरिया घोषित किया जाए । मैं उनको बनाना चाहता हूं कि अम्बाला की कालका तहसील तो पहले से ही बैकवर्ड घोषित की जा चुकी है लेकिन उनका ग्रीवैस यह है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने रोहतक जिले को अम्बाला से पहले बैकवर्ड घोषित कैसे करवा लिया? यह ग्रीवैंस उनका जायज है । लेकिन रोहतक को तो स्टेट की ओर से बैकवर्ड घोषित किया गया है, सैन्टर की तरफ में नही । मैं समझता हूं कि उनकी ग्रीबैस पार्टली मीट हो जाएगी । सैन्टर से शायद प्रायरिटी उनको मिलेगी । इसके साथ–साथ मेवात के एरिया के बारे में एक शौर बात कही गयी कि वहां पर पुरानी बसें इस्तेमाल की जा रही हैं । यह कोई खास बात नही है । आपस में मिल कर भी यह समस्या हल हो सकती है । साथ ही जो आई ० टी ० आईज ० के बारे में भी जिक्र आया, उस बारे मैं इतना ही कहूंगा कि इस बारे में प्लानिंग कमिशन की ओर से बैन लगा हुआ है । हिदायतें हैं कि इक्विपमैंट पर और ध्यान दिया जाए । इस तरह से बाकी की जो मांगें हैं, वे सारी नोट कर ली गयी हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा । अतः मेरा प्रस्ताव है कि इन डिमांडज को पास किया जाए । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब मैं वेरियस डिमान्डज फार ग्रान्ट्स को हाउस की वोटिंग के लिये रखता हूं । क्या इनको एक साथ पुट कर दिया जाए?

आवाजें : ठीक है जी ।

Mr. Speaker : All right.

Questiion is :-

That a sum not exceeding Rs. 94,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 22,53,62,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs 5,20,50,000 for revenue expenditure be granted

to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 11,36,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 4— Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 5,83,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 31,14,48,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 89,72,06,000 for revenue expenditure and Rs. 38,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 34,99,95,000 for revenue expenditure and Rs. 38,22,53,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 1,78,79,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 1,07,59,31,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 10—Medical

& Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 6,16,25,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 10,36,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 36,53,20,000 for revenue expenditure and Rs. 2,37,18,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare and Re-habilitation.

That a sum not exceeding Rs. 2,72,50,003 for revenue expenditure and Rs. 1,67,70,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges Under Demand No. 14-Food and Supplies

That a sum not exceeding Rs. 1,09,88,24,003 for revenue expenditure and Rs. 1,32,66,99,000 for capital expenditure be grated to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 10,67,46,000 for revenue expenditure and Rs. 4,29,36,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987.88 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 49,33,87,000 for revenue expenditure and Rs. 3,93,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 16,21,30,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Hus5andry.

That a sum not exceeding Rs. 2,49,17,090 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 22,92,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that wil come in the course of payment for the year 1987-83 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not excecing Rs. 35,26.80,003 for

revenue expendture be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1937-88 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 5,95,65,093 for revenue expenditure and Rs. 5,92,78,039 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of paymen for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operatioa.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,75,78,000 for revenue expenditure and Rs. 13,50,50,009 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 1,53,41,003 for revenue expenditure and Rs. 1,08,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2,37,19,54,000 be granted to the Governor to defray charges that wil come in the course of payment for the year 1987-88 in respect of charges under Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried

श्री अध्यक्ष : अब हाउस 9 मार्च, 1987 बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है ।

13.13 बजे ।

(तत्पश्चात् हाउस सोमवार दिनांक 9–3–87 को बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।)